R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 21 । अंक : 06
16 से 31 दिसम्बर 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

लोकसभा चुनाव
2024

लोकसभा चुनावों की पटकथा तैयार

गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम चुनावों ने सबको किया सचेत

चुनाव अब चेहरा बनाम चेहरा नहीं, बल्कि चेहरा बनाम मुद्दों की लड़ाई

आज़ादी का अमृत महोत्सव

हम बच्चों का भविष्य संवारते हैं
इसलिए
कोयला निकालते हैं

कोल इण्डिया
Coal India

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

कोल इण्डिया लिमिटेड का एक अनुषंगी कम्पनी

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

CCLRanchi | CentralCoalfieldsLtd | centralcoalfieldsltd | Central Coalfields Limited | cclranchi

इस अंक में

वल्लभगाथा

9 | उल्टा न पड़ जाए दांव

भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना को उनकी ईमानदार छवि के चलते ही मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त का डीजी बनाया था। 2 जून 2022 को पदभार संभालने के साथ ही...

राजपथ

10-11 | अब सारे मंत्री चुनावी मोर्चे पर

भाजपा आलाकमान ने मप्र में 51 फीसदी वोट के साथ 200 विधानसभा सीटों को जितने का टारगेट सत्ता और संगठन को दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अब पूरी सरकार मैदानी मोर्चा संभालेगी। इसके लिए...

चर्चा में

15 | मप्र के भ्रष्ट अफसर ईडी के रडार पर

मप्र के भ्रष्ट अफसर अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में जिन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, ईडी की सक्रियता ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल ईडी ने जल संसाधन विभाग से पांच...

घोटाला

18 | आयुष्मान योजना में घोटाला

मप्र में गतदिनों वायरल हुए एक वीडियो ने आयुष्मान भारत योजना में हो रहे घपले-घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो में एक महिला अधिकारी सामने वाले से 10 लाख रुपए यह कहते हुए मांग रही हैं कि सीएम हाउस से लेकर सभी को पैसा देना पड़ता है। दरअसल अफसरों और...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

गुजरात-हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजों पर अगर समग्र दृष्टि डाली जाए तो इन नतीजों ने जी-जान से जुटे और पूरी ताकत से जूझे हुए सत्ता के दावेदार तीनों राजनीतिक दलों को झटका भी दिया तो जश्न मनाने..

19

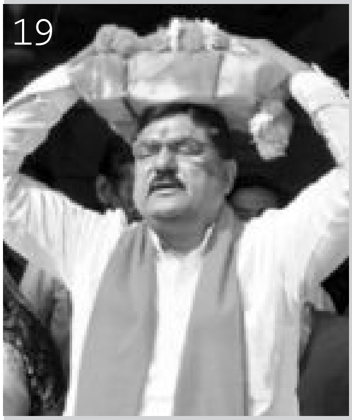

29

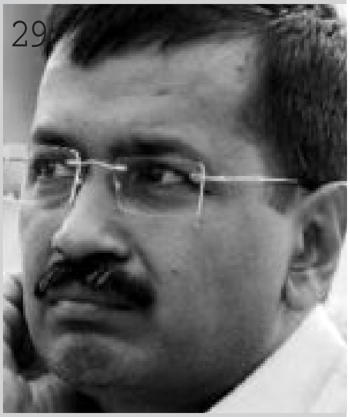

44

45

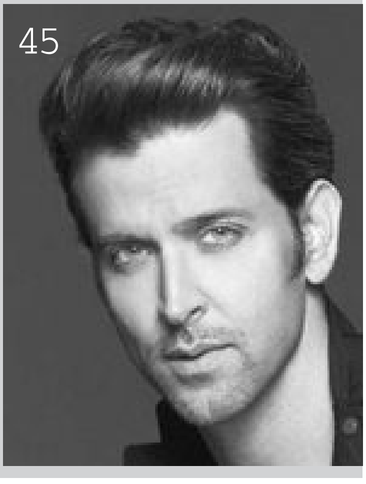

राजनीति

30-31 | हिंदुत्व में हिस्सेदारी

राहुल गांधी को अरसे से एक ऐसे अस्त्र की तलाश रही है, जिसे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो संघ और भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सके और येन-केन प्रकारेण वो अपनी पार्टी को फिर से वो जगह...

महाराष्ट्र

34 | महाराष्ट्र और कर्नाटक में ठनी

एक अखंडित व संप्रभु देश में दो राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर तलवारें खिंची नजर आएं तो यह आश्चर्य और चिंता, दोनों का विषय है। लेकिन, हमारे देश में यह कोई नई बात नहीं है। असम-मेघालय, असम-मिजोरम, असम-नागालैंड, असम-अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख...

बिहार

37 | भूमिहारों का दबदबा

बिहार में चुनाव भले 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण अभी से ही बनाने में जुट गई हैं। इस समीकरण को लेकर सभी पार्टियों ने सवर्ण वोटरों को साधने के लिए अपने दल में शीर्ष पद पर सवर्ण...

6-7	अंदर की बात
40	महिला जगत
41	अध्यात्म
43	कहानी
44	खेल
45	फिल्म
46	व्यंग्य

अपनी बात

चुनावी रंग दिखाएगी मेट्रो...

किसी शायर की ये पंक्तियां हैं...

बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो।
मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो।।

ये पंक्तियां राजनेताओं और राजनीति पर सटीक बैठती हैं। यानी जो समय के साथ बदले वही अच्छा राजनेता है। मप्र में अब 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी चाल बदलनी शुरू कर दी है। सत्तारुढ़ भाजपा विकास कार्यों को तेजी से अमली जामा पहनाने में जुट गई है। सरकार का फोकस है कि विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल और इंदौर में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट को हर हाल में पूरा किया जाए। यानी मप्र की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर के लोगों को 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले मेट्रो की सौगात मिल सकती है। इसके लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं। मेट्रो मिशन को पूरा करने के लिए सरकार ने अपने सबसे विश्वसनीय और तेज तर्रार आईएएस अधिकारी मनीष सिंह को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। दरअसल, राज्य सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों से पहले भोपाल-इंदौर मेट्रो के पहले रूट की शुरुआत हो जाए। सरकार की मंशा चुनावों में इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में भुनाने की है। राज्य में अगले विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। इस महत्वाकांक्षी मेट्रो रेल परियोजना को इन चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि हमारी प्राथमिकता है भोपाल-इंदौर में मेट्रो रेल के पहले गलियारे का काम जल्द से जल्द पूरा करते हुए इसमें सितंबर 2023 तक रेल को हरी झंडी दिखा दें। गौरतलब है कि पिछले तीन महीनों के काम में उल्लेखनीय प्रगति भी दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि मप्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 14 सितंबर 2019 को इंदौर में 7,500.80 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले चरण की नींव रखी थी। इसके तहत शहर में 31.55 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल गलियारा बनाया जाना है। गौरतलब है कि इंदौर में प्रस्तावित मेट्रो रेल परियोजना को लेकर पिछले एक दशक से सरकारी दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से इसका काम लगातार पिछड़ता चला गया है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले डेढ़ साल में कोविड-19 के प्रकोप के चलते भी इसका काम बाधित हुआ। भोपाल में मेट्रो रेल का काम तेजी से चल रहा है। मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मानें तो निर्धारित लक्ष्य यानि सितंबर 2023 तक मेट्रो ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने लगेगी। इसके पहले चरण के कॉरिडोर का काम करीब 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रिऑरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 7 किमी का काम किया जाना है। सरकारी स्तर पर दावा किया जा रहा है कि प्रिऑरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 7 किमी मेट्रो ट्रैक पर मेट्रो रेल का संचालन सितंबर 2023 में हर हाल में प्रारंभ कर दिया जाएगा। एमपीएमआरसीएल द्वारा अनुबंधित सिविल वर्क्स पैकेज की प्रगति के अनुसार करीब 40 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इसमें करीब 35 प्रतिशत राशि भी व्यय की जा चुकी है। प्रिऑरिटी कॉरिडोर के अंतर्गत 6.2 किमी वायडक्ट का कार्य चल रहा है जो कि करीब 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है। प्रिऑरिटी कॉरिडोर के तहत 8 स्टेशनों के निर्माण के लिए भी वर्क आर्डर जारी कर दिया गया है।

यानी सरकार की पूरी कोशिश है कि मेट्रो चुनावी रंग दिखाने के लिए तैयार हो जाए।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 21, अंक 6, पृष्ठ-48, 16 से 31 दिसंबर, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्कण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वात्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बजट असरदार हो

कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। आने वाले बजट सत्र में सरकार को मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए असरदार बजट पेश करने की जरूरत है।

● **शफीक कुरैशी,** ग्वालियर (म.प्र.)

कांग्रेस भी तैयार

भाजपा ने आगामी चुनावों को लेकर अपनी साख मजबूत करनी शुरू कर दी है। उधर, कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। और इस बार कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नजर आ रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा और हिमाचल की जीत ने मप्र कांग्रेस को संजीवनी दी है।

● **आशु श्रीवास्तव,** गुना (म.प्र.)

भोजन की विविधता बढ़ाएं

भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां लोगों के भोजन में सबसे कम विविधता है। भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग (प्रजनन आयु वर्ग) की महिलाओं के समूह में केवल 41 प्रतिशत महिलाओं के दैनिक भोजन में न्यूनतम भोज्य विविधता (भोजन में 5 या 5 से ज्यादा खाद्य वर्गों का होना) मौजूद है।

● **राकेश ओझा,** इंदौर (म.प्र.)

महिला वोटरों पर फोकस

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों में सफल हो रही है। कांग्रेस की इस यात्रा में महिलाएं भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। राहुल गांधी महिलाओं को साथ पदयात्रा कर आधी आबादी के बीच अपनी पैठ को मजबूत करना चाहते हैं। कांग्रेस महिलाओं के बीच अपनी पैठ इसीलिए भी गहरी करना चाहती हैं, क्योंकि देश में अब महिलाएं अपने मत का प्रयोग चुनावों के दौरान बढ़-चढ़कर कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश में 43.8 करोड़ महिला मतदाताएं थीं, जो अब बढ़कर 46.1 करोड़ हो गई हैं। महिला मतदाताओं की भूमिका चुनावों में हमेशा खास रही है।

● **प्रिया नामदेव,** भोपाल (म.प्र.)

बाघों की रखवाली जरूरी

मप्र एक टाइगर स्टेट है। लेकिन यहां आए दिन बाघों की मौतों से मप्र से टाइगर स्टेट का तमगा कहीं छिन न जाए। प्रदेश में लगातार हो रही बाघों की मौत में सबसे आश्चर्यजनक पहलु यह है कि नेशनल पार्क में रहने वाले बाघ भी सुरक्षित नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाघों की सबसे ज्यादा मौतें टाइगर रिजर्व क्षेत्र में हुई है। कान्हा टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा 30 और बांधवगढ़ में 25 मारे गए थे। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

● **अमन सक्सेना,** शिवपुरी (म.प्र.)

भाजपा चुनाव में नहीं छोड़ेगी कोई कसर

मप्र सहित अन्य राज्यों में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मैदान में उतर चुका है। आने वाले दिनों में मप्र में चुनावी बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। संघ के वरिष्ठ नेता प्रदेश में भाजपा के कुछ आला नेताओं से अलग से भी मुलाकात कर सकते हैं। भाजपा के अन्य नेता भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। मुख्यमंत्री सहित प्रदेश अध्यक्ष ने भी क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है।

● **रोशनी सोनी,** राजगढ़ (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना

पिछले कई दिनों से भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग जारी है। दोनों ही दल एक-दूसरे पर गंभीर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक ओर जहां भाजपा 'आप' पर नई शराब नीति में घोटाले के आरोप लगा रही है तो वहीं 'आप' भाजपा पर केंद्रीय जांच एजेंसियों (ईडी, सीबीआई) का गलत इस्तेमाल कर सरकार गिराने के आरोप लगा रही है। इस बीच नई शराब नीति में हुए कथित घोटाले के सिलसिले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में दाखिल किए गए आरोपपत्र में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जो बातें कहीं उससे लग रहा है कि इस जांच का निशाना बहुत सीधा नहीं है। कहा जा रहा है कि यह 'कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना' वाली बात है। दरअसल जांच दिल्ली में चल रही है, छापे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री, राज्य के अधिकारियों और कारोबारियों के यहां पड़े लेकिन निशाना तेलंगाना है। इस मामले में तेलंगाना के कई कारोबारियों और नेताओं को इसमें निशाना बनाया गया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जांच की आंच उन तक पहुंचेगी। ईडी के आरोपपत्र में साउथ ग्रुप की बात कही गई है। इस साउथ ग्रुप में जिन लोगों के नाम हैं उनमें एक नाम के कविता का है। इस बीच सीबीआई ने उनसे पूछताछ भी की है।

एनसीपी के होंगे थरूर!

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जल्द ही पार्टी से किनारा कर सकते हैं। इसको लेकर कयास भी लगाए जाने लगे हैं। खबर है कि शशि थरूर जल्द ही एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। एनसीपी केरल अध्यक्ष पीसी चाको ने इस ओर इशारा कर कहा- 'अगर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एनसीपी में आते हैं तो हम गर्मजोशी से उनका स्वागत करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें बाहर भी करती है तो भी वह तिरुवनंतपुरम से सांसद बने रहेंगे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि थरूर को कांग्रेस में नजरअंदाज किया जा रहा है।' दरअसल, कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद से यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में शशि थरूर को नजरअंदाज किया जा रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद थरूर को बड़ी भूमिकाओं से दूर रखा गया है, जिससे थरूर नाराज चल रहे हैं। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए थरूर ने भी नामांकन भरा था। हालांकि वह खड़गे से बड़े अंतर से चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें कांग्रेस की उच्चस्तरीय कमेटियों में भी जगह नहीं मिली।

'बंगला खाली करो कि मंत्री आते हैं'

'बंगला खाली करो कि मंत्री आते हैं' के स्वर कुछ ऐसे ही उठते हैं कि 'सिंहासन खाली करो कि...।' ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा कि सत्ता परिवर्तन के साथ बंगला खाली करने को लेकर तू-तू, मैं-मैं, नहीं हुई हो। कभी मामला नोटिस तक गया तो कभी न्यायालय तक भी पहुंचा। देर-सवेर निदान होता ही रहा लेकिन तब तक राजनीतिक गलियारों में नेतागण अपनी-अपनी दुंदुभी बजाते रहे। ऐसा ही कुछ इन दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में देखने को मिल रहा है। दरअसल महागठबंधन की सरकार जब सत्ता में आई तो भाजपा के मंत्री, पूर्व मंत्री हो गए। पूर्व मंत्री होते ही बंगला खाली करने का जो सामान्य निर्देश है, उसके मुताबिक एक माह के भीतर आपको अपने अनुकूल बंगले में शिफ्ट करना होता है। ऐसा नहीं होता है तो एक नोटिस जारी होता है। इसके बाद बंगला खाली करना अनिवार्य हो जाता है। इस बार जिन मंत्रियों को बंगला खाली करने का निर्देश मिला है, उनमें पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार जैसे महत्वपूर्ण लोग शामिल हैं।

नहीं जुड़ पाए दिल

राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के लिए आरंभ से ही कहा जा रहा है कि यह भारत के साथ-साथ कांग्रेस को जोड़ने के लिए है, लेकिन इंदौर से यात्रा के निकलने के बाद भी कांग्रेसियों के दिल जुड़ते नजर नहीं आए। दरअसल हुआ यूं कि विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग गुटों के नेता पूरे समय यह जताने-बताने का प्रयास करते रहे कि यात्रा के लिए सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने ही की है। कुछ ने मौका मिलते ही केंद्रीय नेताओं के समक्ष अपने प्रतिस्पर्धी नेताओं को नीचा दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। कई जगह ये दृश्य नजर आए। यात्रा जब ग्रामीण क्षेत्र में थी, तब वरिष्ठ नेताओं के ये संवाद भी सुने गए कि 'अब आप लोग ही कर लो, मैं तो घर निकल रहा हूं।' पदाधिकारियों को पूरा माजरा समझ भी आ रहा था, लेकिन स्थिति न बिगड़े इसलिए वे चुप्पी साधे आगे बढ़ते रहे। गौरतलब है कि कांग्रेस की 'भारत जोड़ो यात्रा' मप्र में आने से पहले कांग्रेसियों में जो जोश नजर आ रहा था, वह जोश यात्रा के इंदौर पहुंचते ही थोड़ी-थोड़ी दूरी पर बदलता गया।

भीड़ में भटके कप्तान

कांग्रेस पार्टी में कैसी धाक थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की। महाराजा पटियाला के साहबजादे तो थे ही, राजीव गांधी के सखा भी थे। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। पार्टी में उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था। नवजोत सिंह सिद्धू ने खूब तेवर दिखाए पर कैप्टन ने उन्हें उपमुख्यमंत्री बनाना तो दूर कोई वजनदार मंत्रालय तक नहीं दिया। लेकिन, पिछले साल मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद वे आपा खो बैठे। कांग्रेस से इस्तीफा दिया। अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाई। फिर, भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सूबे में ऐसी झाड़ू चलाई कि कैप्टन खुद भी विधानसभा चुनाव हार गए। तभी तो इस साल सितंबर में अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। लेकिन, तीन महीने के इंतजार के बाद भाजपा ने उन्हें झुनझुना थमा दिया। पुनर्वास के नाम पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया।

साहब के जाते ही रसूख दिखने लगा

प्रदेश के मालवा क्षेत्र के एक बड़े जिले में इन दिनों एक बार फिर से एक भूमाफिया का रसूख सातवें आसमान पर पहुंच गया है। आलम यह है कि इस भूमाफिया की काली करतूत सामने आने के बाद जो लोग इससे दूर हो गए थे, वे एक बार फिर से इसके साथ नजर आने लगे हैं। दरअसल, इस भूमाफिया को 1997 बैच के एक आईएएस अफसर ने जेल भिजवाया था। उसके बाद जब इस जिले की कमान 2009 बैच के प्रमोटी आईएएस अफसर के हाथ कलेक्टरी आई तो जिले के बाहुबली, भूमाफिया, अपराधी से लेकर नेता तक परेशान हो उठे। साहब की धमक ऐसी थी कि बड़े-बड़े माफिया और अपराधी अपने आप को जेल में ही सुरक्षित मानने लगे। साहब के दौर में जिले का विकास इस कदर हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी तूती बोलने लगी। लेकिन साहब के जाते ही एक बार फिर से भूमाफिया, बाहुबली और अपराधी रसूखदार बनने लगे हैं। इसका नजारा गत दिनों तब देखने को मिला जब जिले के सबसे बड़े भूमाफिया ने जेल से बाहर आने के बाद अपने बेटे की शादी कराई। इस शादी में मंत्री, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री के पुत्र, भाजपा के एक महासचिव के सुपुत्र विधायक और प्रदेश के कई नामदार थिरकते नजर आए। जिन लोगों ने भी यह नजारा देखा, उन्होंने यही कहा कि अगर 2009 बैच वाले साहब अभी तक कलेक्टर रहते तो यह नजारा नहीं दिखता। गौरतलब है कि पूर्व कलेक्टर साहब की जिले में अभी भी तूती बोल रही है।

मंत्री पुत्र की आवारगी

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में प्रदेश के एक मंत्री के पुत्र की आवारगी खूब चर्चा में है। यह मुद्दा चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि मंत्री पुत्र ने एक सरकारी महिला अधिकारी पर हाथ डाला है। सूत्रों का कहना है कि अपने बड़बोलेपन के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले एक मंत्री के पुत्र ने उनके ही विभाग की एक महिला अफसर को अपने प्यार के जाल में फांस लिया है। आलम यह है कि कई मौकों पर दोनों को एकसाथ देखा गया है। जिस महिला अधिकारी की यहां बात हो रही है, वे अपने आशिक के पिता के विभाग में ही डिप्टी डायरेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। दोनों के बीच प्यार है या समझौता, यह तो शोध का विषय है, लेकिन इनकी रंगरलियों की कहानियां राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में चटखारे ले लेकर सुनाई जा रही है। आलम यह है कि लोग अपने तरफ से भी कुछ न कुछ मिलाकर इस कहानी को रोचक बना रहे हैं। यह स्पष्ट कर दें कि जिस मंत्री पुत्र की यहां बात हो रही है, वे पूर्व में अपने अपराधिक कृत्यों के कारण काफी चर्चा में रहे हैं और उनकी करतूतों की वजह से मंत्रीजी की इमेज भी खराब हुई थी और कुछ समय तक उन्हें बैराग्य लेना पड़ा था।

गाज महिला अफसर पर ही गिरी

राजधानी भोपाल में आयोजित तब्लीगी इज्तिमे को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेशभर से पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे। इन्हीं में से दो लोग ऐसे थे, जो इन दिनों प्रदेश के पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बने हुए हैं। इनमें से एक थे मालवा क्षेत्र के एक जिले के एडिशनल एसपी और दूसरी थीं एक महिला सब इंस्पेक्टर। बताया जाता है कि इज्तिमे में 3 दिन की ड्यूटी के दौरान दोनों में इश्क परवान चढ़ा। यह इश्क इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों सारी हदें पार करने को तैयार हो गए। बताया जाता है कि एक दिन दोनों इंदौर में एक हाईवे के एक होटल में अपनी खुशियां बांटने पहुंच गए। इनके आगे-पीछे कौन है, यह सब भूलकर दोनों अपने प्यार में इस तरह मशगूल हो गए कि उसकी चर्चा चारों ओर होने लगी। यह बात महिला सब इंस्पेक्टर के पुराने आशिक को भी लग गई। बताया जाता है कि वह होटल पहुंच गया और साहब और उनकी प्रेमिका को होटल के कमरे में रंगरेलियां मनाते पकड़ लिया। फिर क्या था, पुराने आशिक ने जमकर अपना गुबार निकाला और महिला पुलिस अधिकारी की जमकर कुटाई कर दी। मामला वहां से निकलकर आगे बढ़ा और इसकी शिकायत डीआईजी इंटेलीजेंस के पास पहुंची। शिकायत मिलने के बाद साहब का तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बेचारी महिला अधिकारी पर गाज गिरी और उन्हें ग्वालियर-चंबल संभाग के एक जिले में भेज दिया गया।

त्रिया चरित्र या हकीकत

हाल ही में एक वीडियो ने प्रदेश की राजनीतिक वीथिका में भूचाल ला दिया है। दरअसल, इस वीडियो में एक महिला जमकर बवाल काटती नजर आ रही हैं। वह प्रदेश सरकार के एक मंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते नजर आ रही है। यह भी कहा कि वह उसे बर्बाद करने ही आई है। विवाद आईडी प्रूफ मांगने पर शुरू हुआ। मामला मंत्रीजी के क्षेत्र का ही है, जहां के वे राज परिवार से संबंध रखते हैं। वीडियो में तो महिला ने यह तक कह दिया कि वह होगा आपका मंत्री, यहां आएगा तो पैर छुएगा मेरे भी। महिला ने खुद को मंत्री से भी बड़ा बताया। आईडी मांगने पर कहा कि पहचान देने मंत्री को यहां बुलाओ। जब भाजपा नेता और होटल मालिक ने महिला से कहा कि आप हमारे मंत्री के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकती, वे हमारे राजा हैं। इसके बाद महिला ने अपने मोबाइल पर कोई वीडियो या फोटो दिखाया, जिसके बाद भाजपा नेता शांत हो गए। हालांकि एक अन्य वीडियो में महिला माफी मांगते दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह मामला त्रिया चरित्र का है या इसमें हकीकत है।

रसूखदारों के पैसों से बना 'वन'

गत दिनों राजधानी के एक बड़े व्यावसायिक घराने पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की तो उसे कई रसूखदार लोगों की काली कमाई के स्रोत हाथ लगे हैं। बताया जा रहा है कि जिस व्यावसायिक घराने पर आयकर विभाग ने कार्रवाई की उसे बड़ा बनाने में कई मंत्रियों, नेताओं और अधिकारियों का योगदान रहा है। यानी इन सबकी काली कमाई के पैसों ने इसे नंबर वन बनाया है। बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने तो कई अफसरों के सामने उनकी काली कमाई का ब्यौरा भी रख दिया है। अपनी काली कमाई का ब्यौरा आने के बाद कुछ अफसर सेटिंग में जुट गए हैं। उधर, मंत्रियों और नेताओं की पेशानी पर भी बल आ गया है। इसकी वजह यह है कि आयकर विभाग काली कमाई वाले लोगों की सूची ईडी को सौंप देता है। ऐसे में सभी को यह डर सता रहा है कि अगर ईडी ने इस मामले में दस्तक दी तो उनकी जीवनभर की कमाई उजागर हो जाएगी। बताया जा रहा है कि जिन रसूखदारों की काली कमाई का काला चिट्ठा मिला है, वे इस कोशिश में जुटे हैं कि जैसे-तैसे सेटलमेंट हो जाए।

एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। पूरे देश को यह जानने का अधिकार है कि आखिरकार एलएसी पर ऐसा क्या हुआ, जिसके कारण दोनों देशों की सेना में हाथापाई की नौबत आई।

● **मल्लिकार्जुन खड़गे**

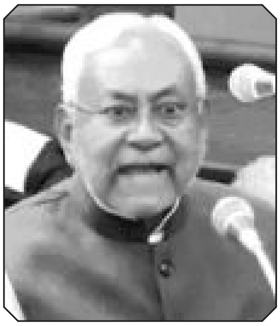

बिहार में हमने पूरी ईमानदारी के साथ शराबबंदी लागू की है। इसके लिए कठोर कदम भी उठाए गए हैं। शराबबंदी का महिलाओं के साथ प्रदेश की लगभग सारी जनता ने स्वागत भी किया है, लेकिन अवैध शराब का कारोबार भी पनपा है। सरकार लगातार कह रही है कि कोई भी शराब न पिए। ऐसे में दारू पीकर मरे तो क्या सरकार मुआवजा देगी। एक पैसा नहीं देंगे।

● **नीतीश कुमार**

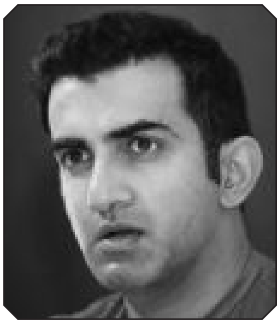

बांग्लादेश में भारत को मिली हार यह बताती है कि बीसीसीआई खिलाड़ियों के साथ जो प्रयोग कर रहा है, वह ठीक नहीं है। हम यह मानते हैं कि भारत की स्ट्रेंथ विश्व में इस समय काफी मजबूत है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम को प्रयोगशाला बना दिया जाए। बीसीसीआई के प्रयोगों का असर है कि टीम लगातार हार रही है।

● **गौतम गंभीर**

मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं ताकि मुझे याद रखा जाए। लेकिन हमारी निगेटिव छवि बनाई जा रही है। महल की मीडिया टीम ने लगातार खबरें बताकर शाही परिवार के सदस्यों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि शाही परिवार बंटा नजर आता है।

● **प्रिंस विलियम हैरी**

मैंने ओम शांति ओम, मैरीकॉम, उमरिका, रंगून, एक्सोन आदि फिल्मों में अभिनय किया है, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। मैं मणिपुरी हूं, लेकिन लोगों ने चाइनीज कहकर रिजेक्ट कर दिया। स्वीमिंग सूट पहना तो घरवालों के ताने मिले और हिंदी फिल्में की तो मणिपुर में बैन कर दी गई। इन तमाम बाधाओं के बाद मैंने आगे बढ़ने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे जगह-जगह रोका गया। दरअसल, लोगों ने मेरी अभिनय क्षमता की जगह मेरे रूप-रंग पर अधिक ध्यान दिया, इसलिए मुझे फिल्मों में मेन रोल की जगह साइड रोल दिया गया। उधर, कई आतंकी संगठनों ने मुझे धमकी दी, लेकिन मैं किसी से नहीं डरी और आज अपना मुकाम हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही हूं।

● **लिन लैशराम**

वाक्युद्ध

एमसीडी चुनाव में जनता ने आम आदमी पार्टी को बहुमत देकर यह सिद्ध कर दिया है कि 15 साल से भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया है। दिल्ली की जनता ने हम पर विश्वास जताया है। हम उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। इसके लिए सबसे पहले कचरे के पहाड़ को खत्म करने का लक्ष्य है।

● **अरविंद केजरीवाल**

आम आदमी पार्टी के चुनावी वादों में फंसकर दिल्ली की जनता ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन पंजाब की तरह यहां की जनता को भी कुछ नहीं मिलने वाला है। केजरीवाल केवल खोंखले वादे करके जनता को बरगला रहे हैं। उनका यह खेल गुजरात और हिमाचल में फेल हो गया है। बहुत जल्द ही दिल्ली में भी पर्दा उठेगा।

● **संबित पात्रा**

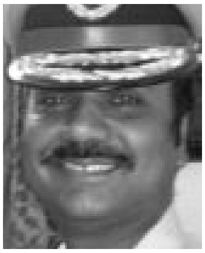

उल्टा न पड़ जाए दांव

भ्रष्टाचार पर प्रहार करने के लिए 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवाना को उनकी ईमानदार छवि के चलते ही मुख्यमंत्री ने लोकायुक्त का डीजी बनाया था। 2 जून 2022 को पदभार संभालने के साथ ही मकवाना ने लोकायुक्त पुलिस की धीमी कार्यप्रणाली को गति में लाना शुरू कर दिया। पुरानी शिकायतें, पुराने अपराध पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुराने केस का बड़ी संख्या में निपटारा होने लगा। हालांकि इस बीच कुछ काम करने में अड़चनें भी सामने आईं, जिनको दूर करने सुझाव मकवाना की तरफ से लोकायुक्त को दिए गए। सूत्रों के अनुसार उन सुझाव पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको हटाने की पटकथा लिखनी शुरू हो गई। लोकायुक्त ने मकवाना को हटाने के लिए सरकार के दरबार में हाजिरी देनी शुरू कर दी। लोकायुक्त को खुश करने के लिए सरकार ने मकवाना को वहां से हटा दिया है। उनकी जगह 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी योगेश चौधरी को पदस्थ किया गया है। सरकार के इस कदम से लोकायुक्त तो खुश हो गए हैं, लेकिन चौधरी मकवाना की तरह ही ईमानदार, सख्त और स्टेट फारवर्ड अफसर हैं। सूत्रों का कहना है कि जिस मंशा से कैलाश मकवाना को लोकायुक्त डीजी के पद से हटाया गया है, वह मंशा योगेश चौधरी के रहते शायद ही पूरी हो। दरअसल, सरकार ने यहां दोहरा खेल खेल दिया है। पहला यह कि लोकायुक्त को खुश कर दिया है, और दूसरा यह कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को सशक्त बनाने दमदार अफसर को लोकायुक्त डीजी बना दिया है।

● कुमार राजेन्द्र

अगले साल कई नौकरशाह होंगे रिटायर

वर्ष 2023 में कई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवानिवृत्त होंगे। इसी कड़ी में जो आईएएस सेवानिवृत्त होंगे, उनमें अशोक शाह, शैलेंद्र सिंह, मुकेश शुक्ला, अल्का श्रीवास्तव, श्रीनिवास शर्मा, अजय तिर्की और राजीव रंजन शामिल हैं। इसी तरह जो आईपीएस सेवानिवृत्त होंगे, उनमें बलवीर सिंह, एसएल थाऊसेन, अन्वेष मंगलम, केटी वाईफे, एमएल छारी, अनिल कुमार शर्मा, तिलक सिंह, मुकेश कुमार जैन, पवन कुमार जैन, अनिता मालवीय, एसडब्ल्यू नकवी, डी श्रीनिवास राय, वीके महेश्वरी और जी जनार्दन, सुशोभन बेनर्जी आदि शामिल हैं। वहीं जो आईएफएस सेवानिवृत्त होंगे, उनमें 1996 बैच के एम कालीदुरई, 2001 बैच के प्रभात कुमार वर्मा, 1987 बैच के बसंत कुमार सिंह, 2003 बैच के डीके पालीवाल, 2008 बैच के एसकेएस तिवारी, 1987 बैच के चंद्रकांत पाटिल, 1994 बैच के के अनिल कुमार खरे, 1987 बैच के आरआर ओखंडियार, 1988 बैच के अतुल कुमार जैन, 2014 बैच के ग्रजेश कुमार बरकड़े, 1999 बैच के आरपी राय, 1988 बैच के अमिताभ अग्निहोत्री, 2014 बैच के डीएस डोडवे, 2014 बैच के राजवीर सिंह, 1998 बैच के हरीश चंद्र गुप्ता, 1987 बैच के अजीत के श्रीवास्तव, 1988 बैच के सुनील अग्रवाल, 1991 बैच के एसपी शर्मा, 2003 बैच के राजीव कुमार मिश्रा, 1987 बैच के जसवीर सिंह चौहान, 1986 बैच के रमेश कुमार गुप्ता, 1987 बैच के पुष्कर सिंह आदि शामिल हैं।

मनु श्रीवास्तव और केसी गुप्ता बनेंगे एसीएस

मप्र में नए साल के पहले 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी में 2 आईएएस अधिकारी एसीएस बनेंगे। दरअसल, नए साल के पहले महीने में 1988 बैच के शैलेंद्र सिंह रिटायर होने वाले हैं। इनकी जगह 1991 बैच के आखिरी अधिकारी मनु श्रीवास्तव अपर मुख्य सचिव बनेंगे। वहीं फरवरी माह में 1990 बैच के आईएएस अधिकारी सेवानिवृत्त होंगे, उनकी जगह 1992 बैच के केसी गुप्ता को अपर मुख्य सचिव बनाया जाएगा। दरअसल, इसी बैच के पंकज अग्रवाल केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं, इसलिए उन्हें काल्पनिक एसीएस मानकर पंकज अग्रवाल को एसीएस बनाया जाएगा।

नए साल में मप्र को मिलेंगे 15 नए डीआईजी

मप्र सरकार के एसपी से डीआईजी पद पर प्रमोशन वाले प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं है, बावजूद इसके नए साल में प्रदेश को 15 नए डीआईजी मिलेंगे। 2009 बैच के 15 आईपीएस अफसरों का डीआईजी बनना तय है, क्योंकि अभी डीआईजी के 15 पद खाली हैं। दो डीआईजी पदोन्नत होंगे, जबकि दो डीआईजी रिटायर्ड होंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने 10 डीआईजी के अतिरिक्त पद पर पदोन्नति का प्रस्ताव भेजा था। इससे 2009 बैच के सभी आईपीएस डीआईजी बन सकते हैं। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद में डीपीसी की गई थी। जैसे-जैसे वैकेंसी आएगी, प्रतिपूर्ति हो जाएगी। 2 अफसर पुलिस महानिदेशक संवर्ग में आ गए हैं, ये संजीव झा और जीपी सिंह हैं। गृह मंत्रालय ने 28 नवंबर को सरकार को जवाब भेजा है कि आईपीएस नियमावली (वेतन) 2016 के अनुसार मप्र संवर्ग के आईपीएस अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाए। राज्य ने केंद्र को कुल 26 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा था। 26 पदों के लिए प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ था। केंद्र की अनुमानित के अनुसार 15 पदों पर ही पदोन्नति हो सकेगी। 13 अफसरों को जनवरी 2023 से पदोन्नति मिलेगी। 14वें क्रम के अफसर को अप्रैल 2023 और 15वें अफसर को जून 2023 को पदोन्नति मिलेगी। नए साल में प्रमोशन के बाद एसपी तरुण नायक-सागर, नवनीत भसीन-रीवा, मुकेश कुमार श्रीवास्तव-सीधी, मोनिका शुक्ला-विदिशा, सुनील कुमार जैन-कटनी, अवधेश गोस्वामी-राजगढ़, डालूराम तेनीवार-दमोह, अमित सांघी-ग्वालियर, तुषारकांत विद्यार्थी-निवाड़ी, सत्येंद्र कुमार शुक्ला-उज्जैन, बीरेंद्र सिंह-सिंगरौली और एसपी टीकमगढ़ प्रशांत खरे डीआईजी पद पर प्रमोट हो सकते हैं।

मप्र में भाजपा अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मैदानी मोर्चा संभाल लिया है। अब मप्र सरकार के मंत्री मैदानी मोर्चा संभालेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों के साथ बैठक कर उन्हें चुनावी मंत्र दे दिया है। अब शिवराज का मंत्र लेकर प्रदेश के सभी मंत्री मैदान में उतरेंगे।

अब सारे मंत्री चुनावी मोर्चे पर

भाजपा आलाकमान ने मप्र में 51 फीसदी वोट के साथ 200 विधानसभा सीटों को जितने का टारगेट सत्ता और संगठन को दिया है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए अब पूरी सरकार मैदानी मोर्चा संभालेगी। इसके लिए राष्ट्रीय संगठन और संघ के वरिष्ठ नेताओं ने रणनीति बनाकर सत्ता और संगठन को सौंप दिया है। इस रणनीति पर काम करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 दिसंबर को मंत्रियों के साथ बैठक की और उन्हें चुनाव का मंत्र देते हुए प्रभार वाले जिलों में सक्रिय होने का निर्देश दिया। आने वाले समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ ही अब मंत्री और विधायक भी दौरे करेंगे। सबसे ज्यादा दौरे करने वाले दोनों दिग्गज नेताओं का रोडमैप तैयार होने लगा है। दोनों प्रमुख नेताओं के दौरे को भाजपा के लिए कमजोर रहे बूथ व सीटों के हिसाब से रखा जाएगा।

मप्र में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। सरकार, केंद्र और राज्य की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान (17 सितंबर से 31 अक्टूबर) चलाया गया था। इसमें 83 लाख पात्र व्यक्ति विभिन्न योजनाओं के लिए चिन्हित किए गए। इन्हें लाभ पहुंचाने की शुरुआत भी बैतूल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर चुके हैं। अब इस कार्यक्रम को विस्तार देने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसमें घर-घर पहुंचाकर यह पता लगाया जाएगा कि कितने और व्यक्ति ऐसे हैं, जिन्हें योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकता है। इसके लिए मंत्री और विधायक घर-घर जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा भी सहयोगी की भूमिका निभाएगी। पार्टी पदाधिकारी भी घर-घर संपर्क करेंगे और योजनाओं के बारे में फीडबैक जुटाकर सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार ने जनसेवा अभियान में मंत्रियों के समूह बनाकर जिलों के दौरे पर भेजा था। इसमें शिविर लगाकर पात्र हितग्राहियों के आवेदन लिए गए थे। 83 लाख व्यक्ति विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र पाए गए और अब इन्हें स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री संभागवार कार्यक्रम कर रहे हैं और मंत्रियों को प्रभार के जिलों में जाकर हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र या आदेश देने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सरकार का प्रयास है कि चुनाव से पहले उन सभी व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ दिला दिया जाए, जो पात्रता तो रखते हैं पर उन्हें लाभ नहीं मिला है। इसके लिए अब घर-घर संपर्क अभियान चलाने की कार्ययोजना तैयार की गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल का कहना है कि हरदा में हमने इस प्रयोग को किया है। इसके अच्छे परिणाम सामने आए हैं। अब इसका विस्तार किया जा रहा है। अभियान में केंद्र और राज्य सरकार की सभी हितग्राहीमूलक योजनाओं के लिए ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जाएगा, जो पात्र हैं पर लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं, प्रदेश भाजपा भी इस अभियान में सहयोगी की भूमिका निभाएगी। घर-घर संपर्क करके फीडबैक जुटाकर सरकार तक पहुंचाया जाएगा। सरकार विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के जल्द ही सम्मेलन भी प्रारंभ करेगी।

2018 से सबक लेते हुए इस बार सत्ता और संगठन पूरी तरह सचेत है। इसलिए इस बार हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में दौरे के दौरान क्या-क्या करेंगे, उसकी पूरी रिपोर्ट संगठन तैयार करेगा। यानी अब पार्टी मंत्रियों के दौरों की पूरी निगरानी करेगी। इसके आधार पर मंत्रियों की परफॉर्मेंस तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि मप्र विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश भाजपा पूरी रणनीति के तहत काम कर रही है। एक ओर जहां बूथ स्तर पर संगठन मजबूत बनाने की कवायद की जा रही है, तो वहीं सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लोगों को लाभ मिले, ऐसे प्रयास हो रहे हैं। प्रभारी मंत्री अपने जिलों में कितने सक्रिय रहते हैं, इस पर भाजपा संगठन ने भी अपनी नजर रखनी शुरू कर दी है। प्रदेश संगठन की पिछली कुछ बैठकों में

मुख्मयंत्री की तरह मंत्री भी होंगे एक्टिव

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ दिनों से अलग ही रूप में नजर आ रहे है। औचक निरीक्षण और अन्य दूसरे कार्यक्रमों में जिलों में पहुंचने पर मंच से ही लापरवाह और अनियमितता करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर रहे है। इससे लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों में भी भय दिख रहा है। इसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सरकार के खिलाफ जनता में बन रही नेगिटिव छवि को बदलने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं, विपक्ष मुख्यमंत्री के एक्शन को दिखावा बता रहा है। उनका आरोप है कि जनता सरकार के काम से परेशान है। इसलिए अब यह सब ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने रात्रि भोज के दौरान अपने कैबिनेट सहयोगियों से कहा- चुनाव का समय आ गया है, मजबूती के साथ जुट जाएं। मुख्यमंत्री आवास में रात्रि भोज से पहले मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से जन सेवा अभियान, पेसा के नियम सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। चुनाव का समय आ गया है। मजबूती के साथ जुट जाएं। जन सेवा अभियान में बहुत अच्छा काम हुआ है। 83 लाख हितग्राही विभिन्न योजनाओं के लिए चिन्हित हुए हैं। इन्हें समारोह करके लाभ वितरण करना है। दिसंबर में सभी मंत्री अपने प्रभार के जिले में दो दिन के लिए जाएं और विकास के कामों की समीक्षा करें।

कार्यकर्ताओं और संगठन के पदाधिकारियों द्वारा सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों एवं प्रभारी मंत्रियों की उपेक्षा की शिकायतें सुनाई पड़ी हैं। इस पर संघ ने भी अपने स्तर पर नाराजगी जताई है। और मुख्यमंत्री को जहां प्रभारी मंत्रियों को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रभार के क्षेत्रों में प्रवास करने को कहा गया है, तो वहीं संगठन ने प्रभारी मंत्रियों के प्रवास पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि मप्र में 2023 के विधानसभा चुनाव में एक साल से भी कम का समय बचा है। इससे पहले भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के औचक निरीक्षण के बाद अब प्रभारी मंत्री भी प्रभार वाले जिलों में हॉस्टल, सीएम राइज स्कूल समेत अन्य विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया क सौहार्दपूर्ण चर्चा में मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से आग्रह किया है कि दिसंबर माह में सभी मंत्री प्रभार के जिलों में दो दिन जाएंगे। विकास के कार्यों की समीक्षा करेंगे। 83 लाख लोगों को स्वीकृति पत्र दिए हैं, जिनको संभागीय जिलों में मुख्यमंत्री और प्रभारी मंत्री बांटेंगे। गृहमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को प्रभार वाले जिलों में हॉस्टल, अस्पताल, सीएम राइज स्कूल के कामों की गति और विकास कार्यों की समीक्षा करने को कहा है।

बताया जा रहा है कि संगठन प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से प्रमारी मंत्रियों की सक्रियता की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगा, जिसके आधार पर आगामी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। विशेषकर प्रभारी मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं या नहीं, उनके द्वारा किसी गांव में रात्रि विश्राम कर चौपाल लगाई जा रही है या नहीं। इसी तरह गांवों में मंत्री शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं को तत्काल दूर कराने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं या नहीं, इन सभी बिंदुओं की रिपोर्ट जिला संगठन द्वारा तैयार कराई जाएगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 22 मंत्रियों का समूह बनाकर उन्हें तीन जिलों की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिन्हें जिलों में जाकर लोगों की समस्याओं का निराकरण करने को कहा गया था, किंतु इनमें एक-दो समूह के मंत्रियों को छोड़ दें, तो बाकी मंत्रियों ने ज्यादा रूचि नहीं दिखाई थी, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह स्वयं गांव-गांव तक पहुंचे थे। इस पर संगठन ने नाराजगी जताई थी। बैठक में यह मामला उठा था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से अपने प्रभार के जिलों में ज्यादा समय देने के निर्देश दिए थे। मप्र भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे सभी कार्यकर्ता जनता के हितों के लिए काम कर रहे हैं। सरकार में बैठे कार्यकर्ता भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। कहीं कोई गुंजाइश होगी, तो उसे दूर किया जाएगा। हम सबका उद्देश्य प्रदेश की जनता की समस्याओं का निराकरण कराना और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है और हमारा संगठन और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड बनने की खबर सामने आते ही प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों अजब सी हलचल मची हुई है। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश के मौजूदा 30 मंत्रियों की रिपोर्ट कार्ड सत्ता और संगठन द्वारा तैयार करवाई जा रही है। रिपोर्ट कार्ड तैयार होने की खबर मिलते ही उन मंत्रियों के होश उड़ गए हैं, जो अभी तक अपना टास्क पूरा करने में पिछड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रदेश में करीब आधे से ज्यादा मंत्री ऐसे हैं, जो अपने विभागीय काम के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। उनमें से करीब एक दर्जन से अधिक तो ऐसे हैं जिनकी स्थिति दयनीय है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री बारीकी से एक-एक पॉइंट पर नजर रखे हुए हैं। विभागीय समीक्षा के दौरान मंत्रियों के सामने उनका रिपोर्ट कार्ड रखा जाएगा। उसके बाद यह रिपोर्ट कार्ड पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाएगा। आगे चलकर जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो इस रिपोर्ट कार्ड को आधार बनाया जाएगा। प्रदेश में आम विधानसभा चुनाव होने में अभी भले ही करीब एक साल का समय है, इसके बाद भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अभी से चुनावी मोड में आते दिखने लगे हैं। यही वजह है कि उनके इस मोड में बाधा बनने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी हो रही है।

दरअसल सरकार नहीं चाहती है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति वर्ष 2018 के चुनाव परिणामों की तरह रहे। इसके लिए सरकार अब अपना पूरा ध्यान विकास और जनकल्याणकारी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने पर लगा रही है। इसके माध्यम से सरकार की मंशा उसके खिलाफ कोरोनाकाल में बनी एंटी इनकंबेंसी को दूर करना है। यही वजह है कि प्रदेश में भी राज्य सरकार केंद्र की तरह तमाम समीकरणों को साधने के लिए राज्य मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करने की तैयारी कर रही है। इस पुनर्गठन के पहले मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई है। जिसमें कई मंत्रियों की परफॉर्मेंस पुअर पाई गई है।

● **कुमार विनोद**

...वर्ना बढ़ेंगी मुश्किलें

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि समय रहते अगर सचेत नहीं हुए तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डिनर के दौरान मुख्यमंत्री ने अपने सदस्यों से कई मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही जो प्रदेश के हिस्सों से मंत्रियों को लेकर रिपोर्ट मिली उसका ब्यौरा भी मंत्रियों के सामने मुख्यमंत्री ने रख दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं जिलों का दौरा कर रहा हूं, आप लोग अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर लोगों से मिलें और योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक लें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश के हिस्सों का दौरा कर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी नजर आ रही हैं। स्पॉट पर ही शिकायत मिलने वाले अधिकारियों को मौके पर ही नाप रहे हैं। इन सबके बीच सरकार को एंटी इनकंबेंसी की चिंता सताने लगी है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों से दो टूक कहा कि प्रभार वाले जिलों में मंत्री रूचि नहीं दिखा रहे हैं। जिसके चलते कामों में लेटलतीफी और गुणवत्ताविहीन काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने डिनर पर मंत्रियों से कहा कि जमीनी स्तर पर काम करें। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि सभी मंत्री दिसंबर से ही 2 दिन अपने प्रभार वाले जिलों में रहे।

पेपरलेस वर्क में माननीयों की रुचि नहीं

इस बार सिर्फ 783 ऑनलाइन सवाल

विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को सवाल से लेकर ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की सूचनाएं, याचिकाएं, स्थगन प्रस्ताव तक ऑनलाइन पूछने की सुविधा दी है, लेकिन प्रदेश के विधायकों की ऑनलाइन सवाल पूछने में रूचि ज्यादा नहीं है। इस माह होने वाले शीतकालीन सत्र के लिए भी इस बार ऑनलाइन सिर्फ 783 सवाल ही पूछे गए हैं, जबकि ऑफलाइन सवालों की संख्या 849 है। मप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र इस बार 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच होने जा रहा है। 29 नवंबर तक इस सत्र के लिए सवाल पूछने की अंतिम तारीख थी, आखिरी दिन तक 58 सवाल ऑनलाइन पूछे गए, जिसमें ऑफलाइन 68 सवाल पूछे गए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह का कहना है कि शिवराज सरकार सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में पैसा पानी की तरह बहा रही है, सरकार विधानसभा को पेपरलेस नहीं करना चाहती। जहां तक बजट का सवाल है तो मप्र सरकार को तो बहुत कम राशि देनी है। पेपरलेस विधानसभा होने से जानकारी जनता को पता चलेगी, इसलिए शिवराज सरकार इस तरफ कदम नहीं बढ़ा रही है। भाजपा-कांग्रेस की कश्मकश में फंसा विधानसभा उपाध्यक्ष का चयन ढाई साल से खाली पड़ा है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम का कहना है कि ई-विधान व्यवस्था लागू होने के बाद दैनिक कार्यसूची, प्रश्नोत्तरी, बिल समेत सब कुछ डिजिटल होगा, इसके बाद पेपर पर कुछ नहीं होगा, इससे विधानसभा के 54 करोड़ रुपए हर साल बचेंगे और 28 करोड़ रुपए के ए4 साइज के कागज बचेंगे। इससे हमारा 70 प्रतिशत खर्च कम होगा। हर विधायक की सीट के सामने कम्प्यूटर सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी सिंगल क्लिक से मिलेगी। यानि पूरी विधानसभा हाईटेक और डिजिटल होगी।

मप्र के माननीयों को टक्नोफ्रेंडली बनाने के लिए विधानसभा ने ट्रेनिंग के साथ ही तमाम सुविधाएं दी हैं, लेकिन मप्र के आधे से अधिक विधायक आज भी ऑफलाइन सवाल पूछ रहे हैं। यह स्थिति तब है जब मप्र विधानसभा भी पेपरलेस की तरफ कदम बढ़ा रही है। फिलहाल राशि नहीं मिलने से पेपरलेस विधानसभा का सपना अभी अधर में लटक गया है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की मंशा है कि, दूसरे राज्यों की तरह मप्र विधानसभा भी पेपरलेस हो जाए, लेकिन सरकार से फिलहाल बजट की स्वीकृति नहीं मिली है, जिसके चलते इस बार का शीतकालीन सत्र भी पेपर वाला होगा।

हालांकि प्रदेश के विधायकों को आजादी है कि वे विधानसभा में ऑनलाइन सवाल पूछें या ऑफलाइन। ऑनलाइन सवाल पूछने के लिए विधानसभा सचिवालय ने विधायकों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया। प्रोत्साहित किया, लेकिन ज्यादातर विधायक ऑफलाइन ही हैं। यानी उनकी रूचि ऑनलाइन सवाल पूछने में नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार 50 प्रतिशत से ज्यादा विधायकों ने ऑफलाइन ही सवाल पूछे हैं। शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। इसके लिए कुल 1632 लिखित सवाल विधायकों ने पूछे हैं। 783 सवाल ऑनलाइन और 849 सवाल ऑफलाइन पूछे गए हैं। पिछले सत्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। ऑनलाइन सवाल न पूछने पर विधायकों के अपने-अपने तर्क हैं। राजपुर विधायक बाला बच्चन के अनुसार ऑफलाइन सवाल पूछने का एकमात्र कारण व्यस्तताएं रहीं। ऑफलाइन के लिए फॉर्मेट में देना सुविधाजनक रहा, इसलिए सवाल सचिवालय को भेज दिए गए। 15वीं विधानसभा के लिए चुने गए विधायक, 14वीं विधानसभा की तुलना में ज्यादा शिक्षित हैं। हालांकि इनमें से 12 विधायक ऐसे भी हैं जो या तो सिर्फ साक्षर हैं या प्राइमरी (5वीं) पास हैं।

कुल 230 विधायकों की संख्या बल वाली मप्र विधानसभा में आगामी शीतकालीन सत्र के लिए मात्र 141 विधायकों ने ही लिखित सवाल पूछे हैं। इनमें से 72 विधायकों ने ऑफलाइन, जबकि 69 विधायकों ने ऑनलाइन सवाल पूछे हैं। इस संदर्भ में विधायक भोपाल उत्तर आरिफ अकील का कहना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन ही सवाल लगाता हूं। जब जैसी सुविधा होती है उसी तरह सवाल लगा देता हूं। ऑनलाइन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोतमा विधायक सुनील सराफ का कहना है कि पुराने सिस्टम के तहत ऑफलाइन सवाल पूछ रहे हैं। ऑनलाइन सवाल पूछने को आदत में शामिल नहीं कर पाया हूं। इस बार सोचा था कि ऑनलाइन सवाल पूछेंगे, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। विधायक महिदपुर बहादुर सिंह चौहान का कहना है कि भोपाल में ही था, इसलिए विधानसभा सचिवालय पहुंचकर ऑफलाइन सवाल दे दिए। हमारे लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सुविधाजनक है, लेकिन सुविधा के अनुसार ऑफलाइन भी सवाल पूछ लेता हूं।

ई-विधान व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए मप्र विधानसभा की टीम केरल और कर्नाटक राज्य का दौरा कर आई है, इस दौरे में विधानसभा अध्यक्ष के साथ विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह और आईटी से संबिधित अधिकारियो ने ई-विधान का अध्ययन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि देश की सभी विधानसभाएं एक ही पोर्टल से जुड़ जाएंगी तो जितने भी एजेंडे, नोटिस, प्रश्न और उनके उत्तर होंगे वे सब एक स्थान पर ही होंगे। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार हो गया है। विधानसभा सचिवालय और मंत्रालय के बीच काम-काज ऑनलाइन है। विधानसभा सचिवालय सवाल ऑनलाइन ही संबंधित विभागों को भेजता है। जवाब भी ऑनलाइन आते हैं। सचिवालय का प्रयास होता है कि विधायक ऑनलाइन सवाल पूछें।

● **सिद्धार्थ पांडे**

क्या राहुल की यात्रा दिखाएगी असर

मप्र में 382 किमी चलने के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब राजस्थान में प्रवेश कर गई है। कथित तौर पर यह यात्रा भले की राजनीतिक नहीं थी, लेकिन इसे मिशन 2023 के मद्देनजर देखा जा रहा है। क्योंकि प्रदेश कांग्रेस ने इस यात्रा के माध्यम से सत्ता में वापसी का सपना बुन रखा है। पूरा प्रदेश संगठन इस यात्रा को चुनावी रंग देने में लगा रहा। इस यात्रा में राजनीति के कई रंग देखने को मिले। कांग्रेस को इस यात्रा से बड़ी उम्मीद है। अब प्रदेश संगठन को इसे भुनाने के लिए रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। कांग्रेसियों के अनुसार राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से मालवा-निमाड़ की 66 विधानसभा सीटों पर तो कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना ही गए, साथ ही प्रदेशभर में कांग्रेसियों को जागृत कर गए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी की यात्रा मप्र में असर दिखा पाएगी?

दरअसल, राहुल गांधी की यात्रा भले ही मालवा-निमाड़ तक ही सीमित रही, लेकिन इसका प्रभाव पूरे प्रदेश पर पड़ा है। इसकी वजह यह रही की यात्रा के दौरान राहुल की यात्रा में कई रंग नजर आए हैं। ओंकारेश्वर में नर्मदा की आरती और महाकाल मंदिर में पूजा के दौरान भक्ति भाव का रूप दिखा, तो आदिवासी जननायक टंट्या मामा की जन्मस्थली में उन्होंने आदिवासियों के परंपरागत तीर-कमान पर भी हाथ अजमाया। डॉ. अंबेडकर की जन्मस्थली महू में संविधान की बात की। यानी मप्र की राजनीति की दिशा तय करने वाले तीन महत्वपूर्ण फैक्टर हिंदू, आदिवासी और दलित किसी न किसी तरह कवर हो गए।

पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह को तिरंगा सौंपा। पहले हिंदी भाषी प्रदेश मप्र में यात्रा को शानदार रिस्पांस मिला। इसके पहले कन्याकुमारी से शुरू यह यात्रा जिन राज्यों से गुजरी है, उनमें दक्षिण भारत के साथ मराठी राज्य महाराष्ट्र शामिल था। मप्र में कांग्रेस का जनाधार भी अन्य राज्यों की तुलना में काफी अच्छा है। यात्रा का मप्र में जिस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, उससे यहां पार्टी को अपना जनाधार मजबूत करने में मदद मिलेगी। यात्रा को मिले रिस्पांस से अभिभूत राहुल गांधी ने मप्र को अब तक की यात्रा का सबसे सफलतम प्रदेश बताया है। यात्रा के समन्वयक दिग्विजय सिंह को भी इस राजनीतिक यात्रा का लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा हैं। 75 की उम्र में दिग्विजय सिंह ने जिस तरह पैदल यात्रा की, वह चर्चा का विषय है, क्योंकि कांग्रेस के अन्य नेता राहुल गांधी के साथ कदमताल नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस के अधिकांश नेता फोटो खिंचवाने के लिए दिन में एक-दो बार यात्रा में शामिल होते हैं और उसके बाद वाहनों से यात्रा में चलते हुए दिखाई पड़ते हैं। मप्र के दोनों ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में राहुल गांधी द्वारा दर्शन और पूजन एक अच्छा राजनीतिक संकेत है।

मप्र में भारत जोड़ो यात्रा को कई बार विवादों का भी सामना करना पड़ा। आदिवासियों के मसीहा मामा टंट्या भील के जन्म स्थान पर भाषण में राहुल गांधी द्वारा अंग्रेजों के साथ उनकी लड़ाई और संघ द्वारा अंग्रेजों का साथ देने के बयान पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति उठाई। भाजपा की ओर से यह कहा गया कि जब मामा टंट्या को फांसी हुई थी तब आरएसएस का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर इसको कैसे और क्यों जोड़ा गया? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर भी राहुल गांधी की यात्रा विवादों में घिरी है। छत्तीसगढ़ और मप्र में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मप्र में सरकार और भाजपा अति सतर्क दिखाई पड़ी, लेकिन भाजपा ने यात्रा को ज्यादा तव्वजो नहीं दी। यात्रा का प्रभाव मप्र में लगभग एक साल बाद होने वाले चुनावों पर क्या पड़ेगा, इसको अभी से नहीं कहा जा सकता। यात्रा से माहौल भले ही बन गया हो लेकिन इसको चुनाव तक बनाए रखना कांग्रेस के राज्य नेतृत्व के लिए बहुत कठिन होगा। मप्र में कांग्रेस का मुकाबला शिवराज और भाजपा के बहुत मजबूत संगठन से है। फिर भी यात्रा का कांग्रेस को कितना लाभ होगा? यह बात तो चुनाव परिणामों के साथ ही स्पष्ट होगी लेकिन यात्रा राहुल गांधी को एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित करेगी।

● **अरविंद नारद**

यात्रा में दिखी कांग्रेस की खामियां

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को निश्चित रूप से सफलता मिल रही है लेकिन इस यात्रा से जो राजनीतिक संदेश और एजेंडा सेट किया जाना चाहिए उस दृष्टि से यात्रा को खास सफलता नहीं मिल पा रही है। मप्र में तो भारत जोड़ो यात्रा कई स्थानों पर कांग्रेस नेताओं में मतभेद का कारण भी बनती हुई दिखाई दी। बुरहानपुर में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा और पूर्व सांसद अरुण यादव के बीच में विवाद, सार्वजनिक रूप से सामने आए। इसी प्रकार इस यात्रा में कांग्रेस के कई नेताओं की भूमिका नगण्य दिखाई दी। कमलनाथ और उनके समर्थकों द्वारा यात्रा को पूरी तरह से हाईजेक कर लिया गया था। फिर भी जिस तरह से लोग यात्रा में सीधे जुड़े उससे यह साफ है कि यात्रा से कांग्रेस पार्टी को एक साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा, लेकिन यह सब इस बात पर निर्भर है कि यात्रा के दौरान बने माहौल को मप्र कांग्रेस के नेता किस तरह बनाकर रखते हैं। अब मप्र काग्रेस चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गई है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी चुनावी जमावट के लिए मैदान में उतरेंगे। प्रदेश प्रभारी जयप्रकाश अग्रवाल, राष्ट्रीय सचिव सह संगठन प्रभारी सीपी मित्तल, कुलदीप इंदौरा, संजय कपूर और सुधांशु त्रिवेदी प्रदेश के अलग-अलग जिलों में दौरे करेंगे। इसमें जिला और ब्लॉक इकाइयों के साथ बैठक करके चुनाव की तैयारियों को देखेंगे। इसके बाद संभागीय सम्मेलन का सिलसिला शुरू होगा। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि जल्द ही जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां भी होंगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ 15 दिसंबर के बाद प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर आगामी कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।

मप्र में बढ़ी घूसखोरी

मप्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बाद भी सरकारी महकमों में घूसखोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि सरकार की सख्ती और जांच एजेंसियों की निगरानी के बाद भी रिश्वतखोरी चरम पर है। इसकी वजह यह है कि विभाग रिश्वतखोर अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रदेश में पिछले एक साल में 150 घूसखोर अधिकारी-कर्मचारी ट्रैप हुए हैं, लेकिन पुलिस विभाग को छोड़कर किसी अन्य विभाग ने इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की है। गौरतलब है कि लोकायुक्त प्रदेश में लगातार घूसखोर अधिकारियों-कर्मचारियों को ट्रैप कर रहा है। लोकायुक्त टीम की कार्रवाई के दौरान घूस लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सरकारी अफसर-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने में सिर्फ पुलिस विभाग ही सख्त है। पिछले एक साल (दिसंबर 2021 से दिसंबर 2022 तक) के दौरान प्रदेश में पकड़े गए 150 से अधिक घूसखोरों में 25 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इन सभी को 24 घंटे के भीतर पुलिस विभाग ने सस्पेंड कर दिया लेकिन दूसरे विभागों के सवा सौ से अधिक घूसखोर अफसर-कर्मचारियों का सिर्फ तबादला किया गया। इनमें दो अफसर तो ऐसे हैं, जो बतौर सजा हुए तबादले में भी मलाईदार पद पा गए। कुछ कर्मचारी दूसरी बार रिश्वत लेने के बाद भी कड़ी कार्रवाई से बचे हुए हैं।

बताया जाता है कि कई विभाग चाहते हुए भी घूसखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है सामान्य प्रशासन विभाग का एक आदेश। यह आदेश लोकायुक्त की कार्रवाई में ट्रैप होने के बाद स्थानांतरण की इजाजत देता है। लेकिन निलंबन को भी नियम विरूद्ध नहीं माना है। बड़वानी एसपी दीपक शुक्ला कहते हैं कि ट्रैप में नियम तो सभी विभागों के लिए तबादले का ही है, लेकिन पुलिस विभाग निलंबित इसलिए करता है ताकि कड़ी कार्रवाई का संदेश जाए। इधर, बड़ा सवाल यह है कि आखिर कड़ा संदेश दूसरे सरकारी विभाग प्रमुख क्यों नहीं देना चाहते। रिटायर्ड मुख्य सचिव केएस शर्मा का कहना है कि लोकायुक्त की कार्रवाई में रिश्वत लेते पकड़े गए अधिकारी-कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर लूप लाइन में भेजना चाहिए। इससे रिश्वत लेने वालों के प्रति समाज में संदेश जाए। तबादले से संदेश गलत जाता है। दूसरे जिले में समकक्ष पद पर पदस्थ करना भी शर्मनाक है। घूस लेने वालों पर पुलिस विभाग की सख्ती सराहनीय है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की किस तरह अवहेलना की जा रही है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दो अफसरों को बतौर सजा तबादले में भी मलाईदार पद दे दिया गया। इस साल मई में होशंगाबाद के सीएमएचओ डॉ. प्रदीप मोजेस दो हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए थे। उन्हें एक माह बाद ही बुरहानपुर में सिविल सर्जन बना दिया गया। घूसखोरी के मामले में लोकायुक्त टीम से पकड़े जाने वाले डॉ. मोजेस को सिविल सर्जन बनाने से इसलिए भी सवाल खड़े हुए क्योंकि जिस समय उनकी बुरहानपुर में तैनाती हुई, उस समय वहां के जिला अस्पताल में 12 करोड़ के घपले में ताबड़तोड़ कार्रवाईयां हो रही थीं। ऐसे ही शिवपुरी जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आरएस परिहार के घूस लेते पकड़े जाने के बाद उन्हें सीधी में इसी पद पर तैनात कर दिया गया। वहीं रिश्वत लेते पकड़े जाने वालों में 40 साल से ज्यादा उम्र वाले 80 प्रतिशत सरकारी अधिकारी-कर्मचारी हैं। हालांकि इंदौर में कुछ पुलिसकर्मी ऐसे थे, जो ज्वाइनिंग के दो से छह माह में ही ट्रैप हो गए। करीब पांच प्रतिशत कर्मचारी रिटायरमेंट से सालभर पहले रिश्वत लेते पकड़े गए। इनमें खंडवा के सीएमएचओ डॉ. डीएस चौहान जब नर्स के तबादले के बदले दस हजार की रिश्वत लेते पकड़े गए, तब उनके रिटायरमेंट के महज ढाई माह ही बचे थे। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाने के प्रभारी वीरेंद्र सिंह परिहार सेवानिवृत्ति से छह माह पहले और आगर मालवा जिले के कानड़ थाना टीआई मुन्नी परिहार रिटायरमेंट से एक माह पहले रिश्वत लेती पकड़ी गईं। रिश्वतखोरी में राजस्व विभाग के सबसे ज्यादा 35 से अधिक कर्मचारी-अधिकारी ट्रैप हुए। इनमें भी 27 पटवारी हैं। चेक से रिश्वत लेने के मामले भी सामने आए हैं। इस साल नवंबर में पन्ना में पीडब्ल्यूडी के उपयंत्री मनोज रिछारिया को 7 लाख की रिश्वत लेते लोकायुक्त टीम ने दबोच लिया। इसमें रिश्वत के रूप में एक लाख नगद और छह लाख का चेक दिया गया था। आयकर विभाग गुमनाम शिकायतों को खत्म नहीं करता है। ऐसी शिकायत आती हैं तो गोपनीय रूप से छानबीन की जाती है। शिकायत के तथ्य संज्ञान में लिए जाते हैं। इसमें सत्यता होती है तो आगे की कार्रवाई होती है। प्रदेश में जीएडी के अधीन जांच एजेंसी लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई का तरीका भी लगभग ऐसा ही है। ये जांच एजेंसी गुमनाम शिकायत को सीधे खारिज नहीं करती है। इस शिकायत में से जो भी काम के तथ्य होते हैं, उनको जांच में लिया जाता है। सामान्य प्रशासन विभाग के एसीएस विनोद सेमवाल का कहना है कि रिश्वत लेने वालों को सस्पेंड भी करते हैं। ये भी देखते हैं कि लोकायुक्त टीम ने क्या रिपोर्ट दी है। ट्रैप मामलों में सस्पेंड और अटैच कर्मचारियों के मामले में लोकायुक्त की रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ कहना सही होगा।

● **लोकेंद्र शर्मा**

मंत्रालय में शिकायत पेटी ही नहीं

भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के दावों के बीच प्रदेश के सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतों वाली पेटियां गुमनामी में खोने लगी हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के आदेशों में साफ है कि हर कार्यालय में सीलबंद शिकायत पेटी रखी जाने के साथ ही विभाग प्रमुख के हाथों सोमवार को खोली जाएगी। इन शिकायतों का अलग से रजिस्टर मेंटेन होगा, लेकिन इन आदेशों पर अमल नहीं हो रहा है। वल्लभ भवन की 650 करोड़ की नई एनेक्सी में कोई शिकायत पेटी नहीं लगाई गई है, जबकि पुरानी इमारत में जो एकमात्र पेटी नजर आती है, उसका ताला नहीं खुलता है। प्रदेश के मंत्रियों की सलाह पर मंथन-2007 में तय हुआ था कि गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसे अमल में लाने के लिए जीएडी से आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा पारदर्शिता के लिए अहम बिंदु जारी हुए थे, जो कागजों में सिमट गए। यह भी कहा गया था कि प्रत्येक 6 महीने में विभागाध्यक्ष और 3 महीने में कलेक्टर जिलास्तर पर मॉनीटरिंग करेंगे। वे कार्यालयों में शिकायत पेटी और रजिस्टर का निरीक्षण भी करेंगे। विंध्याचल, सतपुड़ा भवन में भी शिकायत पेटी खानापूर्ति के लिए लगी हुई है।

मप्र के भ्रष्ट अफसर ईडी के रडार पर

मप्र के भ्रष्ट अफसर अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर हैं। लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू में जिन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, ईडी की सक्रियता ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। फिलहाल ईडी ने जल संसाधन विभाग से पांच अभियंताओं (इंजीनियरों) राजीव कुमार सुकलीकर, शरद श्रीवास्तव, शिरीष मिश्रा, अरविंद उपमन्यु और प्रमोद कुमार शर्मा की संपत्ति का ब्यौरा मांगा है। ये 3333 करोड़ के निर्माण कार्यों में गड़बड़ी एवं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संदिग्ध हैं। उनकी चल एवं अचल संपत्ति के साथ नौकरी में आने से लेकर अब तक के वेतन का भी हिसाब मांगा गया है। इस कार्रवाई के साथ ही मप्र में ईडी की इंट्री हो गई है।

गौरतलब है कि इन दिनों ईडी देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार छापामार कार्रवाई कर रहा है। मप्र के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की उपसचिव सौम्या चौरसिया सहित खनन, अवैध वसूली और जमीन से जुड़े मामले में अधिकारियों के खिलाफ सर्वे की कार्रवाई हो चुकी है। ईडी ने संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार करके करोड़पति या लखपति बनने वालों की खैर नहीं। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारियों की अवैध संपत्ति जब्त होने के साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई भी होनी तय है। इसके लिए ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त में लंबित मामलों की भी जांच की जाएगी। इनमें कई आईएएस और आईपीएस अफसर भी हैं। जल संसाधन विभाग में चल रही परियोजनाओं में भ्रष्टाचार की शिकायतें बराबर सामने आती रहती हैं। जानकार बताते हैं कि ईडी लंबे समय से अगस्त 2018 से फरवरी 2019 के बीच सिंचाई परियोजना के दस्तावेजों को खंगाल रही थी। संस्था ने इस अवधि में स्वीकृत बांदा बांध, हनोता बांध, वर्धा बांध, अन्य चार परियोजनाओं के कार्यों और भुगतान, प्रेशर पाइप कार्य इकाई और बांधों की नींव को पतला करने की जानकारी चाही है। ईडी ने सभी के पैन नंबर, नौकरी में कहां-कहां किन पदों पर पदस्थ रहे इसका भी ब्यौरा मांगा है। उल्लेखनीय है कि रतनगढ़, पेंच, पार्वती नदी से जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए ठेकेदार राजू मेंटाना को एडवांस 887 करोड़ रुपए भुगतान करने के मामले में भी राजीव कुमार सुकलीकर संदिग्ध हैं। शासन इस मामले की जांच वर्ष 2019 से कर रही है पर अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच सुकलीकर सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। वहीं प्रमोद कुमार शर्मा को हाल ही में सरकार ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण में सदस्य सचिव नियुक्त किया है। अरविंद उपमन्यु सागर में मुख्य अभियंता के प्रभार में हैं तो शिरीष मिश्रा जल संसाधन मुख्यालय में मुख्य अभियंता (खरीद) हैं। ये निविदा से संबंधित काम देखते हैं।

जल संसाधन विभाग के अफसरों द्वारा मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर की गई मेहरबानी अब भारी पड़ने वाली है। गौरतलब है कि मप्र में सिंचाई संरचनाओं के निर्माण में वर्ष 2013 से सक्रिय मेंटाना कंस्ट्रक्शन कंपनी को जल संसाधन विभाग ने छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स का करीब दो हजार करोड़ का काम दिया था। पेंच व्यपवर्तन परियोजना सिवनी कैनाल के लिए 156 करोड़ रुपए सहित एक अन्य काम का ठेका दिया। इन कामों को शुरू करने के लिए कंपनी ने मशीनें खरीदने के लिए एडवांस राशि मांगी, तो विभाग ने 887 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए। इसके बाद कंपनी ने काम ही नहीं किया। यह मामला विधायक दिनेश राय मुनमुन ने विधानसभा में उठाया था। उन्होंने विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव राधेश्याम जुलानिया की भी घेराबंदी की थी। विधानसभा में मामला आने के बाद राजनीति गरमा गई और राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (इओडब्ल्यू) को जांच सौंपी गई थी।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

280 अफसरों के खिलाफ जांच लंबित

प्रदेश में ईडी के प्रवेश ने दागी अफसरों की परेशानी बढ़ा दी है। गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसे करीब 280 अफसर हैं जिनके खिलाफ ईओडब्ल्यू को शिकायत मिली है। लेकिन शासन की मंजूरी न मिलने के कारण इनके खिलाफ चार्जशीट ही पेश नहीं हो पा रही। कई बार पत्राचार के बावजूद संबंधित विभाग अभियोजन की स्वीकृति में आनाकानी कर रहे हैं। कुछ विभाग तो लोकायुक्त की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दे रहे। प्रदेश में लोकायुक्त संगठन को ऐसे 280 अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच शुरू करने का इंतजार है। इजाजत नहीं मिलने की वजह से भ्रष्टाचार के 15 केस 9 साल से लंबित हैं। सबसे ज्यादा नगरीय आवास और विकास विभाग के लगभग 31 मामले लंबित हैं। सामान्य प्रशासन विभाग और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 29-29 मामले लंबित हैं। वहीं राजस्व विभाग के 25 और स्वास्थ्य विभाग के 17 मामले लंबित हैं। अभियोजन स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के कारण चार्जशीट पेश करने में देर हो रही है। वैसे नियम के अनुसार अधिकतम 4 महीने में अभियोजन की स्वीकृति मिलनी चाहिए। आईएएस पवन जैन के खिलाफ केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की सलाह के बाद शासन ईओडब्ल्यू को केस चलाने की मंजूरी देगा। सामान्य प्रशासन विभाग पत्र लिखकर डीओपीटी से इस मामले में सलाह लेगी। ईओडब्ल्यू ने इंदौर से जुड़े 7 साल पुराने मामले में चालान पेश करने के लिए शासन से अभियोजन की स्वीकृति मांगी है। डीओपीटी से अभियोजन की स्वीकृति के बाद ही आगे की कार्रवाई हो सकेगी। तत्कालीन एसडीओ राजस्व पवन जैन पर रियल स्टेट के लोगों से सांठगांठ कर पर्यवेक्षण शुल्क जमा करने का आरोप है।

"मप्र को भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संकल्पित हैं। इसके लिए मप्र को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री के संकल्प को पूरा करने के लिए इस बार मप्र का बजट ऐसा होगा, जिससे आत्मनिर्भर मप्र का सपना साकार होगा। प्रदेश के बजट को तैयार करने के लिए वित्त विभाग के अधिकारी अभी से जुट गए हैं। बजट को अंतिम रूप देने से पहले जनता की भी सलाह ली जाएगी।"

बजट में आत्मनिर्भर मप्र की झलक...

सरकार ने मार्च में प्रस्तुत होने वाले बजट के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। मप्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह उत्साहित दिख रहे हैं, उससे तो यह साफ हो गया है कि प्रदेश का बजट आत्मनिर्भर मप्र पर आधारित होगा। शिवराज सरकार का आगामी बजट निश्चित रूप से प्रदेश की दिशा तय करने वाला होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शिवराज सरकार के लिए चुनौती भी है और अवसर भी। चुनौती इस मायने में कि राज्य में खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है और उसके मुकाबले आय में वृद्धि नहीं हो पाई है। जनता को राहत पहुंचाने वाली योजनाओं को गति देने के लिए वित्तीय स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। मुख्यमंत्री की सक्रियता और दूरदर्शी सोच के कारण ही राज्य को संकट से उबारने में मदद मिली है। हालांकि वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लेने की जरूरत अभी भी है।

प्रदेश का बजट इस बार तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। स्वयं का राजस्व बढ़ाने पर सरकार द्वारा जोर दिया जाएगा। साथ ही विभागों को बजट से अतिरिक्त भी वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कर्मचारियों के वेतन में तीन प्रतिशत की वृद्धि के हिसाब से प्रविधान रखे जाएंगे तो महंगाई भत्ते के लिए वेतन मद में कुल प्रस्तावित राशि का 32 प्रतिशत हिस्सा रखा जाएगा। प्रदेश में कर्मचारियों को अभी 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है।

अब तक की तैयारियों से माना जा रहा है कि विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट के जरिए सरकार बड़ा संकल्प जाहिर कर सकती है। सरकार के लिए यह बजट चुनौती के साथ एक बड़ा अवसर भी है। माना जा रहा है कि राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मप्र का खाका खींचने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इस बार का बजट अवसर सरकार के लिए भी होगा, क्योंकि जोखिम लेकर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं, वे सभी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कारगर साबित हुए हैं। कोरोना संकट से प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौट रही है। लगभग सभी क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण में वृद्धि हो रही है। यह शुभ संकेत हैं, क्योंकि सरकार ने प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो रोडमैप तैयार किया है, उसके लिए वित्तीय संसाधनों की अधिक जरूरत होगी। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभागों को अतिरिक्त आय सृजित करने के लक्ष्य भी दिए हैं। जीएसटी के बाद राज्य के पास टैक्स लगाने का दायरा सीमित हो गया है। ऐसे में उन

अधिकारियों-कर्मचारियों को बड़ी सौगात

मप्र के सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। जल्द ही उनके वेतन में बढ़ोत्तरी हो सकती है। राज्य सरकार 2023-24 का बजट बना रही है जिसमें वेतन मद में वृद्धि का प्रस्ताव है। विभागों से अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन मद में 3 प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव देने को कहा गया है। विभागीय प्रस्तावों पर विचार कर बजट प्रावधान कर राज्य सरकार इसकी मंजूरी दे सकती है। इसके साथ ही मजदूरों के लिए वेतन वृद्धि के प्रस्ताव बुलाए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए 23 और अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए 18 प्रतिशत के अनुसार राशि रखी जाएगी। सरकार एक साल में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने जा रही है। इसके लिए नियम में संशोधन भी कर दिया है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वे वर्ष 2022-23 और 2023-24 में की जाने वाली भर्ती और उनके वेतन-भत्तों पर आने वाले खर्च की जानकारी अलग से दें ताकि स्थापना व्यय का आंकलन किया जा सके। 5 जनवरी से विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों से वित्त विभाग के अधिकारी बजट प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।

विकल्पों पर विचार करना होगा, जिनके माध्यम से सरकार जनता पर कर का बोझ बढ़ाए बगैर आय बढ़ा सकती है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने देशभर के नामचीन विषय विशेषज्ञों के साथ मंथन के बाद आत्मनिर्भर मप्र का रोडमैप तैयार किया है। इसमें सभी क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विषम परिस्थितियों में बेहतर प्रबंधन करते आए हैं, वैसा ही इस दौर में भी वे बजट के माध्यम से करेंगे। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान करने के साथ आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए कदम उठाने से वह नहीं झिझकेंगे।

प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। इसलिए मप्र सरकार के दिशा-निर्देश पर वित्त विभाग के अधिकारी अभी से बजट की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार का बजट चुनावी रंग में रंगा रहेगा। मुख्य बजट में सरकार का कर्मचारियों के बकाया डीए सहित अधोसंरचना विकास पर फोकस रहेगा। इसके लिए यदि कोई विभाग नई योजना लाना चाहता है, तो उसे औचित्य बताना होगा। विभाग अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले सकेंगे, बल्कि इसके लिए प्रस्ताव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भेजना होगा और अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री द्वारा ही लिया जाएगा। वित्त विभाग ने आगामी बजट बनाने के लिए विभिन्न विभागों से तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ता में वृद्धि संभावित है। जानकारी के अनुसार आगामी वर्ष बजट में इसके लिए 46 प्रतिशत सभी विभाग प्रावधान करेंगे। शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ रुपए का मुख्य बजट और प्रथम अनुपूरक 9,784 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा। अगले साल विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक का आने की संभावना है। ये करीब 3.20 लाख करोड़ का हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बजट में कर्मचारियों के वेतन मद में तीन और मजदूरी के मद में पांच प्रतिशत की वृद्धि, महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में संभावित वृद्धि के लिए प्रावधान किया जाएगा।

वित्त विभाग ने विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। दायरा भी तय कर दिया गया है। सफाई, सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था इत्यादि में चालू वित्त वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत से ज्यादा बजट नहीं बढ़ेगा। वेतन के बजट में विभाग 3 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव दे सकते हैं। मजदूरी के लिए 5 प्रतिशत तक की वृद्धि के प्रस्ताव की छूट दी गई है। प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने होंगे। बजट से ज्यादा राज्य पर कर्ज है। स्थापना व्यय में इजाफा हो रहा है। कुल बजट की 26 प्रतिशत राशि वेतन में खर्च हो जाती है। सरकार खर्च कम करने के प्रयास में है। वित्त विभाग ने विभागों से कहा है कि जिन योजनाओं की निरंतरता की जरूरत नहीं रह गई है, उनके लिए बजट का प्रस्ताव न दिया जाए। एक समान योजनाओं का संविलियन कर बजट अनुमान तैयार किया जाए। जिन योजनाओं की जरूरत नहीं है या समाप्त कर दी हैं उनका बजट शून्य कर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। बजट में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा आर्थिक उन्नति के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बजट की 30 प्रतिशत राशि महिलाओं तथा बच्चों पर खर्च करने का प्रावधान करने के निर्देश वित्त विभाग ने संबंधित विभागों को दिए हैं। अगले बजट में सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान की योजनाओं में प्रावधान किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने के लिए बजट में पृथक से राशि का प्रावधान किया जाएगा। इन वर्गों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं को समेकित किया जाएगा। इस नवीन व्यवस्था में व्यय की जाने वाली राशि की मॉनीटरिंग भी करने का प्रावधान होगा।

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट की तैयारी प्रारंभ कर दी है। यदि विभाग कोई नई योजना लाना चाहते हैं तो उन्हें औचित्य बताना होगा। वे अपने स्तर से कोई निर्णय भी नहीं ले सकेंगे। उन्हें प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजना होगा और उस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। वहीं, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आगामी वर्ष में होने वाली संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सभी विभाग 46 प्रतिशत के हिसाब से प्रविधान रखेंगे। वित्त विभाग ने सभी विभागों को बजट प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

● डॉ. जयसिंह सेंधव

बजट में होगी विकास कार्यों की झलक

बजट भाषण के लिए सभी विभागों से आत्मनिर्भर मप्र को लेकर किए गए कामों का ब्यौरा मांगा गया है। दरअसल, बजट के माध्यम से सरकार यह बताएगी कि मप्र ने आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। चाहे निवेश बढ़ाना हो या अधोसंरचना विकास के काम हों, प्रदेश किसी राज्य से पीछे नहीं है। कृषि के क्षेत्र में भी लगातार विस्तार हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, चना, मसूर, सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी गई। इससे किसानों को सुविधा मिली और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आई। अटल प्रोग्रेस-वे के आसपास औद्योगिक क्षेत्र विकास के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना 2023 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मप्र के बजट में इस बार शिक्षा को प्राथमिकता, जनता से सुझाव शिवराज सरकार ने मांगे हैं। हालांकि सरकार विशेषज्ञों की राय भी ले रही है, विभागीय स्तर पर भी मंथन चल रहा है। लेकिन सरकार का यह भी मानना है कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं है। मप्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में सरकार का फोकस है कि बजट ऐसा हो जो आत्मनिर्भर मप्र अभियान को पूरा करने में मददगार हो। इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता से सुझाव मांगा है। सुझाव देने वालों ने कृषि, उद्योग और रोजगार के अवसरों पर फोकस करने की मांग ही है। ज्यादातर सुझाव अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर आए हैं।

आयुष्मान योजना में घोटाला...

मप्र में गतदिनों वायरल हुए एक वीडियो ने आयुष्मान भारत योजना में हो रहे घपले-घोटालों की पोल खोलकर रख दी है। इस वीडियो में एक महिला अधिकारी सामने वाले से 10 लाख रुपए यह कहते हुए मांग रही हैं कि सीएम हाउस से लेकर सभी को पैसा देना पड़ता है। दरअसल अफसरों और अस्पतालों की मिलीभगत से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। आयुष्मान भारत योजना से संबद्ध मप्र के 620 निजी अस्पतालों में से 120 ने 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। इनमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर सहित प्रदेश के ख्यातिप्राप्त निजी अस्पताल भी शामिल हैं। भोपाल और जबलपुर के कुछ अस्पतालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह जानकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तैयार कराई गई एक जांच रिपोर्ट में सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग अब इन निजी अस्पतालों पर अर्थदंड लगाकर वसूली कर रहा है और 15 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कुल 104 अस्पतालों से अर्थदंड वसूली के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। भोपाल के वैष्णव मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही आयुष्मान योजना की संबद्धता भी समाप्त कर अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया। आष्युमान योजना के अंतर्गत कुल 620 निजी अस्पतालों को तीन साल (वर्ष 2019 से जुलाई 2022 तक) में 1048 करोड़ 98 लाख 19 हजार 481 रुपए का भुगतान किया गया। वर्ष वार किए गए भुगतान में अधिकांश निजी अस्पतालों में वित्तीय फर्जीवाड़ा और ज्यादा बिलिंग की शिकायतें मिली हैं।

भोपाल के आयुष्मान भारत अस्पताल, राजदीप अस्पताल, वीसीएच अस्पताल, किशनानी अस्पताल, जीवनश्री अस्पताल, नवोदय अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर। जबलपुर का जीवन ज्योति अस्पताल एनटीपीसी गाडरवाड़ा, आदित्य सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर, सेठ मन्नूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट अस्पताल। गुना का सहयोग अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर प्रालि, राम हाईटेक अस्पताल, आरआर हाईटेक अस्पताल, मीनाक्षी अस्पताल। मुरैना का राधे कृष्ण अस्पताल और भिंड के बीएम अस्पताल को नोटिस जारी किया गया है। इन अस्पतालों से अधिक बिलों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रदेश के 104 अस्पतालों से अर्थदंड वसूला जा रहा है। इनमें भोपाल का एके अस्पताल, आधार, अजय, अक्षय, आल इस वेल मल्टीस्पेशियलिटी, अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवास, अर्मिता अस्पताल, आनंद, अपेक्स, आराधना मल्टीस्पेशियलिटी एंड किडनी, अरेरा ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर, आयुष्मान भारत, बालाजी चिल्ड्रन, बंसल, भोपाल केयर, बीआईएमआर अस्पताल ग्वालियर, बॉम्बे अस्पताल रिसर्च सेंटर जबलपुर, कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट जन विकास न्यास ट्रस्ट, केयर मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल, सेंट्रल, चिरायु हेल्थ एंड मेडिकल प्रलि, चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड चेरिटेबल, फाउंडेशन, सीएसएस एप्पल मल्टीस्पेशियलिटी, सिटी अस्पताल, सिटी अस्पताल दमोह, सिटी अस्पताल जबलपुर, धर्मलोक अस्पताल प्रालि, डीएनएस अस्पताल प्रालि, गैलेक्सी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल जबलपुर, जीडी अस्पताल रतलाम, गीता अस्पताल उज्जैन, ग्लोबल स्पेशियलिटी, ग्रेटर कैलाश अस्पताल प्रालि, गुप्ता नर्सिंग होम, गुरू आर्शीवाद, इंफिनिटी हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट ए यूनिट ऑफ आईएचआरसी जबलपुर, जेके अस्पताल एंड एनएल अस्पताल, जबलपुर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, जेश अस्पताल शाजापुर, जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, जय आरोग्य, जेके, कैलाश सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल ग्वालियर, एलबीएस, लीलावती मेमोरियल अस्पताल भोपाल, लाइफ मेडिकल अस्पताल, एकेजी हाईटेक अस्पताल अशोकनगर, लोटस, महावीर इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, माहेश्वरी नर्सिंग होम, मार्बल सिटी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, मेडिस्क्वर मेट्रो अस्पताल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर जबलपुर, एमजीएम अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर कटनी, मिरेकल्स अस्पताल, मिशन अस्पताल दमोह, मिताली अस्पताल बालाघाट, मोहनलाल हरगोविंद पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट, मोना अस्पताल, एमपी बिरला अस्पताल सतना, मल्टीकेयर अस्पताल भोपाल, नागपुर अस्पताल, नर्मदा अपना अस्पताल होशंगाबाद, नर्मदा ट्रामा सेंटर भोपाल, नवजीवन अस्पताल भोपाल और ग्वालियर, न्यूरो ट्रामा सेंटर एंड मल्टी स्पेशियलिटी, निरामय, पालीवाल, पांडेय, पाटीदार सेंटर एंड मल्टीस्पेशियलिटी मंदसौर, पाटीदार अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, पीपुल्स सेंटर अस्पताल प्रालि, प्राइम अस्पताल देवास, राम हाईटेक, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज एंड सीआर गार्डी अस्पताल, रीवा अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, आरजेएन अपोलो स्पेशल, आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, रोशन, सागरश्री अस्पताल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रालि, सहारा फ्रैक्चर एंड जनरल अस्पताल, संस्कारधानी अस्पताल, प्रालि, सराफ, सर्वोत्तम, सेठ मन्नूलाल जगन्नाथदास ट्रस्ट अस्पताल, सेवा सदन आई अस्पताल, शेल्बी अस्पताल, शांता नर्सिंग होम, श्रीगुरुनानक अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, श्रीसाईं, सिंगरौली अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, एसएनजी, एसएसआइएमएस ग्वालियर, स्वास्तिक मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, तृप्ति मल्टी स्पेशियलिटी एंड ट्रामा सेंटर, उबंतू अस्पताल भोपाल, उज्जैन चेरिटेबल ट्रस्ट, उज्जैन आर्थो, वंदना अस्पताल एंड ट्रामा सेंटर, विंध्या अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर शामिल हैं।

● राकेश ग्रोवर

ऐसे की गड़बड़ी

जांच में कई तरह के चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कई अस्पतालों में खुद के कर्मचारियों के नाम आयुष्मान कार्ड बनवा दिए गए थे और उन्हें मरीज बनाकर रकम निकाल ली गई। इसी तरह किसी मरीज का बिल 50 हजार का बना तो उसे बढ़ाकर दो लाख रुपए की राशि सरकार से वसूल ली जाती थी। ग्रामीण क्षेत्र के आयुष्मान कार्डधारियों को अस्पताल लाने के लिए जगह-जगह एजेंट नियुक्त किए गए थे। कुछ अस्पतालों ने इन्हें जनसंपर्क अधिकारी का पदनाम दे दिया था। बिलिंग की राशि में बढ़ोतरी का खेल जांच के नाम पर किया जाता था। महंगी-महंगी जांच के नाम पर बिल बना लिए जाते थे। जबलपुर के सेंट्रल इंडिया किडनी हॉस्पिटल द्वारा वेगा होटल में कार्डधारियों को प्रलोभन देकर ठहराया जाता था और इनके नाम पर फर्जी बिलिंग की जाती थी और फर्जी मरीजों को भी कुछ हजार रुपए दे दिए जाते थे। इसके संचालक डॉ. अश्विनी पाठक, दुहिता पाठक फिलहाल जेल में हैं। अब तक इन्होंने छह हजार फर्जी मरीजों के नाम पर आयुष्मान योजना से रकम निकाली थी। ये अस्पताल लोगों को लालच देकर उनके फर्जी आयुष्मान कार्ड भी तैयार करवाते थे।

भगवान करेंगे चुनावी नैय्या पार

मप्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के साथ नेता भी सक्रिय हो गए हैं। अपने-अपने क्षेत्रों में विधायक और मंत्री जनता के बीच जा रहे हैं और नए वोटरों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।

मतदाताओं को अपने पाले में लेने के लिए मंत्री-विधायकों ने नए-नए हथकंडे अपनाने भी शुरू कर दिए हैं। चुनावी साल आने से पहले ही पार्टी नेता अपने-अपने क्षेत्रों में धार्मिक आयोजन करा रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों ने विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक आयोजनों के जरिए मैदान में उतरने की तैयारी बना ली है। मप्र के नगरीय विकास मंत्री, कृषि मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्षेत्र में भागवत कथाएं बड़े स्तर से इस महीने में आयोजित की गई हैं। इन मंत्रियों के क्षेत्र में पहली बार बड़े स्तर पर श्रीमद्भागवत कथा हुईं क्योंकि पहली बार इन्होंने इस तरफ रुख किया है। इस समय प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से जनता के बीच में नेता सक्रिय दिखाई दे रहे हैं।

चुनावी साल में वोटरों को साधने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह, कृषि मंत्री कमल पटेल के अलावा विधायक जजपाल जज्जी ने अशोक नगर में कथा कराई, जिसमें मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, तुलसी सिलावट और बृजेंद्र सिंह यादव नजर आए। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने इंदौर में तो एक माह पहले भाजपा विधायक रमेश मेंदोला ने भी कथा कराई। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने क्षेत्र राजघाट में अयोध्या के नेपाली बाबा को लेकर पहुंचे। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी कथा कराने वालों में शामिल हैं। बागेश्वर धाम के संत का प्रबंधन देख रहे उनके भाई सालिगराम का कहना है कि पूरा दिसंबर बुक है। दमोह में स्थानीय विधायक कथा करा रहे हैं। राजनीतिक जानकार मंत्रियों और विधायकों के क्षेत्र में होने वाले इन आयोजनों को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह के आयोजन में बड़े पैमाने पर लोगों की भीड़ जुटती है, ऐसे में चुनावी साल में मतदाताओं को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। हालांकि इन आयोजनों का चुनाव में कितना फायदा मिलेगा यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि नेताओं ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

गौरतलब है कि कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने क्षेत्र में 7 से 13 दिसंबर के बीच श्रीमद् भागवत कथा करवाई। उन्होंने जय किशोरी को भी बुलाया था। लोगों का कहना था कि पहली बार हरदा जिले में इतनी बड़ी कथा का आयोजन हुआ। आखिरी दिन सामूहिक विवाह सम्मेलन का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचे थे। इसी तरह गोपाल भार्गव ने अपने क्षेत्र रहली में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था। इसमें मप्र समेत देशभर से 34 धर्म गुरुओं को बुलाया गया था। 5000 महिलाओं के साथ कलश यात्रा निकाली गई और उपहार भी दिए गए। यह कथा 5 से 12 दिसंबर तक चली।

मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी खुरई विधानसभा क्षेत्र में पहली बार बड़े स्तर पर कमल किशोर नागर को बुलवाकर भागवत कथा करवाई। पूरे विधानसभा क्षेत्र में यह कथा चर्चा का विषय बनी हुई है। कथा 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चली। इसमें भी श्रोताओं, कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की गई थी। भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस के विधायक भी क्षेत्र मे सक्रिय दिखाई दिए। प्रदेश में होने वाले 2023 विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का वक्त बाकी है, लेकिन भाजपा के मंत्री और विधायक अभी से चुनाव की तैयारियों में जुटते नजर आ रहे हैं। जिसकी एक झलक मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में हो रही भागवत कथा आयोजनों में भी देखने को मिल रही है। क्योंकि इस वक्त शिवराज सरकार के कई कद्दावर मंत्री अपने क्षेत्रों में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करवा रहे हैं, जिसे 2023 में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, शिवराज सरकार के कई मंत्रियों के विधानसभा क्षेत्र में भागवत कथाओं का आयोजन किया जा रहा है, देश के अलग-अलग कथावाचक भागवत करेंगे। धार्मिक आयोजनों में लोगों की भारी भीड़ जुटती है, ऐसे में इन आयोजनों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सभी विधायकों और मंत्रियों को अपने-अपने क्षेत्र में फोकस करने की बात कही थी। ऐसे में मंत्रियों के साथ-साथ विधायक भी कथाओं पर ध्यान लगाते नजर आ रहे हैं।

शिवराज सरकार में सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव ने रहली विधानसभा क्षेत्र में बड़ी भागवत कथा का आयोजन करवाया। गोपाल भार्गव के गृहनगर गढ़ाकोटा में आयोजित इस आयोजन में 37 धर्म गुरुओं को बुलाया गया, जबकि 5 हजार महिलाओं के साथ भागवत कथा के आयोजन के लिए कलश यात्रा निकाली गई, गोपाल भार्गव के विधानसभा क्षेत्र में 5 से 12 दिसंबर तक कथा का आयोजन किया गया। बता दें कि गोपाल भार्गव विधानसभा में सबसे सीनियर विधायक हैं और लगातार 8 विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। शिवराज सरकार में कद्दावर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र खुरई में भागवत कथा का आयोजन कराया। बताया जा रहा है कि यह खुरई विधानसभा क्षेत्र में अब तक की सबसे बड़ी कथा है। खुरई में प्रसिद्ध संत कमल किशोर नागर ने भागवत कथा की, जो 9 से 15 दिसंबर तक चली। शिवराज सरकार के एक और मंत्री कमल पटेल भी अपने विधानसभा क्षेत्र में भगावत कथा का आयोजन कराया, जहां हरदा में देश की प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी भागवत कथा सुनाने पहुंचीं, जिसे हरदा में अब तक की सबसे बड़ी भागवत कथा के तौर पर देखा गया।

● **प्रवीण सक्सेना**

पहले भी हो चुके हैं कई बड़े आयोजन

यह कोई पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में एक साथ इतने बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। इससे पहले भी कई मंत्री और विधायक धार्मिक आयोजन करवा चुके हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा विधायक रमेश मेंदोला, कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में बड़े धार्मिक आयोजन करवा चुके हैं। जबकि आने वाले वक्त में भाजपा-कांग्रेस के कई विधायकों के क्षेत्र में भी कथाओं की तैयारी चल रही है।

मप्र में मनरेगा में मजदूरों से लूट

मनरेगा से मलाई खा रहे जिम्मेदार

सरकार ने आम गरीबों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में पंचायतों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी यानी मनरेगा योजना लागू की है। दुनिया की सबसे बड़ी इस योजना का मूल उद्देश्य आस्था व श्रम मूलक कार्य कराकर लोगों को काम उपलब्ध कराकर उनका पलायन रोकना था, मगर ऐसा हो नहीं सका। सही मायने में अधिकारियों से लेकर पंचायत प्रतिनिधियों तक सभी मनरेगा से मलाई खा रहे हैं, वहीं जरूरतमंद ग्रामीण परेशान हैं। सच्चाई ये है कि एक तो 90 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं हो रहे हैं, जो कार्य होते भी हैं वे कागजों पर पूर्ण करके राशि आहरित कर ली जाती है। तालाब गहरीकरण, मिट्टीकरण, पौधरोपण, नाला सफाई के काम मनरेगा वाले अधिकांश काम मशीनों से कराए जा रहे हैं। वहीं कई काम कराए बिना ही मजदूरी तथा मटेरियल के नाम पर फर्जी मस्टर व फर्जी बिलों से राशि निकाल ली गई है। मनरेगा के काम मशीनों से कराने की शिकायत मिलने के बावजूद जिम्मेदार अफसर मौन बने हैं। ऐसे में जब गांव के लोग काम-दाम और रोटी न मिलने की शिकायत करके काम की तलाश में महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं तो आखिर ये मनरेगा की राशि कहां और कैसे खर्च की जा रही है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है।

मप्र में फिंगर प्रिंट की कॉपी कर गरीबों का पैसा डकारा जा रहा है। इस खेल में पंचायतों के सरपंच से लेकर पंचायत सचिव तक शामिल हैं। इसका खुलासा मुरैना जिले के रामपुर थाना पुलिस ने किया है। रामपुर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है, जो गांव-गांव जाकर अपने आपको कियोस्क सेंटर का संचालक बताता है और लोगों के पैसे निकलवाने का काम करता है। जब पुलिस ने उसके बैग की तलाशी ली, तो 140 लोगों के फिंगर प्रिंट की कॉपी और 500 लोगों के कागजात बरामद हुए। पुलिस ने शैलेंद्र धाकड़ (23) निवासी पहाड़गढ़ से जब पूछताछ की, तो उसने इस बात का खुलासा किया कि केवल वह ही नहीं, जिले की लगभग हर पंचायत में इस प्रकार का फर्जीवाड़ा चल रहा है। मजदूरों के फिंगर प्रिंट को कॉपी कर लिया जाता है और इसके जरिए उनके खाते में सरकार द्वारा आने वाला धन निकाल लिया जाता है। दूसरी तरफ पंचायत व पंचायत सचिव दोनों मिलकर मनरेगा में मजदूरों के कागज लगा देते हैं तथा उनके फिंगर प्रिंट की कॉपी बनाकर उनके नाम से मनरेगा का पैसा निकालते रहते हैं। जो काम है, वो जेसीबी से करा दिया जाता है।

रामपुर थाना पुलिस को खबर लगी कि एक व्यक्ति गांव में आकर अपने आपको कियोस्क संचालक बता रहा है तथा पैसे निकलवाने का कह रहा है। पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति को जब पकड़ा तथा उसके बैग की छानबीन की, तो उसमें कियोस्क मशीन के साथ ही ग्लूगन व विशेष प्रकार की ग्लू-रॉड पाई गई। एक नोटबुक में आधार कार्ड नंबर लिखे थे। इसके अलावा बड़ी संख्या में सिमकार्ड व महिला पुरुषों के फोटो थे। पूछताछ में उसने जो चौंकाने वाला खुलासा किया, उसे सुनकर सभी दंग रह गए। उसने पुलिस को बताया कि सरपंचों के बुलाने पर वह उनकी पंचायत में जाता तथा सरपंच उसे गरीबों के नाम व आधार नंबर देते। वह उन लोगों को बुलाकर उनके थंब स्क्रीन पर प्रिंट लेता था तथा उनको कॉपी करके रख लेता था। उनके फिंगर प्रिंट की कॉपी व आधार नंबर व फोटो से वह उनके नाम की सिम खरीदता था। इसके बाद फिंगर प्रिंट की कॉपी से उनका मनरेगा खाता खोलता था। इसमें उसी सिम का मोबाइल नंबर डाल देता था।

जब मनरेगा का पैसा मजदूर के खाते में आता, तो उसे निकालने के लिए जैसे ही उस मजदूर का फिंगर प्रिंट लगाकर ओके बटन दबाता, तो उसके उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आती, जो कि उसमें दर्ज होता था तथा उनके पास उसकी सिम रहती थी। उस ओटीपी को दर्ज कर खाते में से पैसा निकाल लिया जाता था। इस प्रकार उसने कई सरपंचों व पंचायत सचिवों के कहने पर मनरेगा का पैसा उन्हें निकालकर दिया है। शैलेंद्र धाकड़ ने पुलिस को बताया कि उसने फिंगर प्रिंट कॉपी करना यूट्यूब से सीखा है। उसने ऑनलाइन विशेष प्रकार की ग्लूगन व ग्लू रॉड मंगाई है। वह उस ग्लू रॉड को उस ग्लू गन में फंसा कर बायोमेट्रिक मशीन (थंब इम्प्रेशन मशीन) में चिपका देता था। उसके बाद वह अंगूठा लगवाता था। अंगूठा लगवाने के बाद वह उस पर फेविकॉल चिपका देता था। दो दिन तक सूखने के बाद वह फेविकॉल हटाकर जब उस ग्लू को हटाता था तो ग्लू पर उस व्यक्ति के साफ फिंगर प्रिंट की कॉपी उभरकर आ जाती थी। इसे वह सुरक्षित डिब्बी में रख लेता था तथा जब भी उसके खाते से पैसा निकालना हो तो उसी को बायोमेट्रिक मशीन में डालकर ओटीपी उसके नाम से खरीदी सिम पर आ जाती और उसे डालकर पैसा निकाल लिया जाता था। शैलेंद्र धाकड़ ने पुलिस को बताया कि उसने इसी ट्रिक से लोक निर्माण विभाग के एक रिटायर कर्मचारी पन्नालाल जाटव के खाते से 90 हजार रुपए उड़ाए थे। अगर वह पकड़ा नहीं जाता तो अभी तक और 500 लोगों के खातों से पैसा उड़ा देता। थाना प्रभारी पवन भदौरिया ने जब शैलेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की, कि अभी तक उसने कौन-कौन से पंचायत सरपंचों व पंचायत सचिवों के कहने पर मनरेगा व गरीबों के पैसे गलत तरीके से उनके खातों से उड़ाए हैं, तो उसने उनके नाम भी पुलिस को बता दिए हैं। अब पुलिस जल्द ही उन पंचायत सरपंचों व सचिवों को बुलाकर पूछताछ करेगी तथा बड़ा खुलासा करेगी।

छतरपुर जिले में मनरेगा के अधिकांश काम मशीनों से कराए जाने से गावों में काम की उम्मीद में बैठे श्रमिक खाली हाथ हैं। ऐसे में वे काम-दाम और रोटी की तलाश में गांवों से पलायन करने को मजबूर हैं। एक तो मनरेगा में गांव में काम ही नहीं मिलते, यदि काम मिल भी जाए तो भुगतान कम और देर से मिलता है। मजदूरी बकाया होने से मजदूर काम करने की बजाय गांव से बोरिया-बिस्तर समेटकर काम-दाम और रोटी के लिए महानगरों की ओर पलायन करना ज्यादा सही समझते हैं। ऐसे तमाम कारणों से गांव में काम व मजदूरी के अभाव में जिले से प्रतिदिन सैकड़ों प्रौढ़ और युवा मजदूर रोजगार की तलाश में कानपुर, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, हैदराबाद सहित अन्य महानगरों का रुख कर रहे हैं। सड़क किनारे गाड़ी की प्रतीक्षा करते पलायन कर रहे महिला-पुरुषों के जत्थों को देखा जा सकता है।

● जितेंद्र तिवारी

मिड-डे मील का कागजी मेन्यू

स्कूली बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए सरकार ने स्कूलों में मिड-डे-मील की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सोमवार से शनिवार तक पौष्टिक आहार का मैन्यू बनाया गया है। सोमवार को रोटी के साथ तुअर की दाल, चने व टमाटर की सब्जी, मंगलवार को पूरी के साथ हलवा, मूंगबड़ी, आलू टमाटर की सब्जी, बुधवार को रोटी के साथ चने की दाल एवं मिक्स सब्जी, गुरुवार को सब्जी वाला पुलाव और पकौड़े वाली कढ़ी, शुक्रवार को रोटी के साथ दाल और चने-मटर की सब्जी और शनिवार को पराठे के साथ मिक्स दाल और हरी सब्जी मेन्यू में शामिल किया गया।

विडंबना यह है कि इसके लिए सरकार ने प्रतिदिन और प्रति छात्र के हिसाब से मात्र 5.14 रुपए का बजट रखा है। स्वसहायता समिति को इतने रुपए में खाना बनाकर बच्चों को मैन्यू के अनुसार देना होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। समिति उपलब्धता के अनुसार बच्चों को खाना बनाकर देती है। अभी हाल ही में राजधानी से करीब 50 किलोमीटर दूर सरकारी स्कूल में मिड-डे मील का खाना खाने के बाद 17 बच्चे बीमार पड़ गए। उन्हें बदबू वाला खाना दिया गया था। इसके बाद जांच और खाने वाली समिति को ब्लैकलिस्ट करने से लेकर शाला प्रभारी को सस्पेंड तक कर दिया गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है।

राजधानी समेत जिले के ग्रामीण इलाके में स्थित सभी स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील की जांच की जाएगी। बैरसिया के एक स्कूल में खाना खाने से बच्चे बीमार हो गए थे। इसके बाद शासन ने यह तैयारी की है। जिला प्रशासन ने इसके लिए 20 टीमें बनाने के लिए कहा है। इसमें से 12 टीमें शहरी क्षेत्र के स्कूल और 8 टीमें बैरसिया समेत पूरे ग्रामीण इलाके में जाकर स्कूलों का मुआयना करेंगी। यह टीमें पांच मापदंड पर जांच करेंगी। इनमें जिस जगह मिड-डे मील बनाया जा रहा है, वहां साफ-सफाई, भोजन के लिए इस्तेमाल होने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता, भोजन बनाने वाले लोगों की दक्षता देखी जाएगी। इसके अलावा भोजन पर निगरानी करने वाले टीचर और बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा। एसडीएम आदित्य जैन ने बताया कि सभी स्कूलों में बारी-बारी से जांच करवाएंगे। गौरतलब है कि भोपाल से करीब 40 किमी दूर बैरसिया स्थित प्राथमिक स्कूल भैंसोदा में मिड-डे मील खाकर 35 बच्चे बीमार हो गए थे। आरोप है कि इन्हें खराब बेसन और मठा की कढ़ी खिलाई गई थी। जिस समय भोजन बना तब शिक्षक हरि सिंह टेलर स्कूल में नहीं थे। लापरवाही बरतने के बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके पहले भी स्कूलों में बनने वाले मिडडे मील को लेकर शिकायतें आती रही हैं। इसके लिए जिले के सभी बीआरसीसी और संकुल प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन स्कूलों में निगरानी रखें।

चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य मप्र

मप्र चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश में पहला राज्य है। वित मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा था कि बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक विकास पर ध्यान देना जरूरी है, इसलिए पहली बार चाइल्ड बजट लाया जा रहा है। इसके जरिए बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो सकेंगी। अभी तक 17 विभागों में बच्चों के लिए चल रही योजनाओं को चिन्हित किया गया है। इनमें चलने वाली योजनाओं को पहली बार एक साथ लिया गया है। सरकार ने बजट में इसके लिए 57 हजार 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

बैरसिया के मिड-डे मील प्रभारी योगेश सक्सेना ने बताया कि पहली से पाचवीं क्लास तक के बच्चों को स्वसहायता समूह द्वारा खाना दिया जाता है। इसके लिए समूह को प्रति व्यक्ति 5.14 रुपए दिए जाते हैं। इसके साथ 100-100 ग्राम चावल और गेहूं दिया जाता है। 6वीं से 8वीं क्लास के बच्चों के लिए 7.14 रुपए प्रति बच्चे दिया जाता है। इसमें चावल और गेहूं प्रति छात्र 150-150 ग्राम दिया जाता है। समिति को स्कूल परिसार में ही खाना बनाना होता है। अभी शायद बजट बढ़ा दिया गया है, लेकिन आदेश नहीं आए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने मिड-डे मील का खाना बनाने के लिए स्कूल परिसर में ही किचन शेड बनवाए हैं। इसके लिए हर शेड पर विभाग ने 2 लाख रुपए खर्च किए। यह वर्ष 2018-19 में बनाए गए, लेकिन हकीकत यह है कि शेड में खाना बनाया ही नहीं गया। बैरसिया की ग्रांड रिपोर्ट के दौरान यह सामने आया था कि किचिन शेड घटिया होने के बाद वह कभी खुले ही नहीं। ऐसे में पुराने और गंदे जगह पर खाना बनाया जा रहा है। सक्सेना ने बताया कि मिड-डे मील जनपद पंचायत द्वारा दिया जाता है। इसके लिए स्वसहायता समूह को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उनका एग्रीमेंट होता है। इसी के आधार पर उन्हें स्कूल में मिड-डे मील का काम दिया जाता है। जनपद को ही समूह की जांच से लेकर उसकी निगरानी करना होता है। समूह को खाना परिसर में ही बनाना होता है।

मिड-डे मील में शाला प्रभारी की जिम्मेदारी यह रहती है कि वह यह देखे की खाना स्कूल परिसर में ही बना हो। इसके साथ ही खाना तैयार होने के बाद उसे खुद टेस्ट करना होता है। अगर उसे लगता है कि खाना बच्चों को देने लायक नहीं है, तो वह उसे रिजेक्ट कर सकता है। सक्सेना ने बताया कि यह माना जाता है कि सभी बच्चे स्कूल नहीं आते हैं। ऐसे में स्कूल में बच्चों की उपस्थिति को देखते हुए अधिकतम 65 प्रतिशत बच्चों की संख्या निर्धारित की गई है। यानी स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो 65 प्रतिशत बच्चों का ही बजट दिया जाएगा। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हाथों को साफ रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन, मप्र के 20 हजार सरकारी स्कूलों में हैंड वाशिंग यूनिट नहीं बने हैं। 34 हजार में हैंड वाशिंग यूनिट की व्यवस्था ही नहीं है। 1500 में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। डेढ़ हजार स्कूलों में क्लासरूम नहीं हैं, तो 22 हजार में क्लासरूम कम जर्जर और 19 हजार में ज्यादा मरम्मत की जरूरत है।

● विकास दुबे

कोलेजियम पर कलह!

कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत के साथ ही इस पर विवाद शुरू हो गया। धीरे-धीरे यह साफ होने लगा कि कोलेजियम के नाम पर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। अन्य न्यायाधीशों की राय को तरजीह नहीं देने की बातें भी सामने आने लगीं। कानून मंत्री किरन रिजिजू और सर्वोच्च न्यायालय के बीच सार्वजनिक मतभेदों के कारण देश में कुछ अरुचिकर परिस्थितियां बनती जा रही हैं। मूल विषय कोलेजियम से जुड़ा हुआ है। काफी समय से कोलेजियम सिस्टम की कार्य पद्धति और उसकी उपादेयता पर बहस होती रही है। पिछले दिनों इस बहस में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी दखल दिया। इस बहस के मूल में यह है कि हमारे **सर्वशक्तिमान** न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का एकाधिकार कुछ न्यायाधीशों को केवल इसलिए हो, क्योंकि वे न्यायपालिका परिवार का हिस्सा होने के कारण उनके बारे में बेहतर समझ रखते हैं या उसमें आम आदमी के नुमाइंदों की भी भागीदारी इसलिए हो, क्योंकि न्यायाधीश केवल न्यायपालिका के ही नहीं, अपितु पूरे समाज के हित-रक्षक होते हैं? लिहाजा उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार के माध्यम से आम लोगों की आकांक्षाओं तथा अपेक्षाओं को भी स्वर मिलना चाहिए। वर्ष 1993 से पहले देश में इस तरह का कोई विवाद नहीं था। संविधान में यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। अनुच्छेद 124 और 217 में राष्ट्रपति से यह जरूर अपेक्षा की गई कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय देश के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय वहां के राज्यपाल से भी मशविरा करें। दूसरे लोकतांत्रिक देशों में भी न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार कार्यपालिका के पास ही है।

1993 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकार्ड बनाम भारत संघ के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के मामले में न्यायपालिका की राय को सर्वोच्चता देने की बात कही। तब नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मत व्यक्त किया कि न्यायाधीश चूंकि न्यायिक परिवार का हिस्सा होता है इसलिए उसके बारे में जितनी समझ न्यायाधीशों को होती है, उतनी दूसरों को नहीं हो सकती। अत: उसकी नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े विषयों पर न्यायपालिका को ही निर्णय लेना चाहिए। इसे अंजाम देने के लिए न्यायाधीशों के एक कोलेजियम की परिकल्पना की गई, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायधीश हों। संविधान पीठ के कुछ न्यायाधीशों ने अपने निर्णय में न्यायिक स्वायत्तता और निष्पक्षता के लिए इस कदम को जरूरी बताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपने वरिष्ठ साथियों के कोलेजियम की मदद से इसे अंजाम देंगे। इस मुकदमे में चूंकि कोलेजियम के न्यायाधीशों की संख्या और सहयोगी न्यायाधीशों की भूमिका के बारे में बहुत कुछ साफ नहीं था, इसलिए इसके क्रियान्वयन में शुरू से ही व्यावहारिक दिक्कतें आने लगीं।

कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत के साथ ही इस पर विवाद शुरू हो गया। धीरे-धीरे यह साफ होने लगा कि कोलेजियम के नाम पर मनमाने फैसले लिए जा रहे हैं। अन्य न्यायाधीशों की राय को तरजीह नहीं देने की बातें भी सामने आने लगीं, किंतु सब कुछ इतना गोपनीय था कि इस पर स्वस्थ बहस नहीं हो सकी। यह विवाद उस समय सतह पर आ गया जब वर्ष 1998 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को भेज दीं और सरकार ने उन्हें रोककर कोलेजियम एवं मुख्य न्यायाधीश के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी। तब नौ सदस्यीय संविधान पीठ की ओर से न्यायमूर्ति एसपी भरूचा ने कोलेजियम व्यवस्था को विस्तार से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि इसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा चार वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, निर्णय यथासंभव सर्वानुमति से लिया जाए और यदि किसी नाम पर कोलेजियम के दो सदस्य असहमत हों तो उसका नाम नहीं भेजा जाए। सैद्धांतिक रूप से यह व्यवस्था अब तक कायम है, किंतु इसे अब नजरअंदाज करने के प्रकरण भी सामने आने लगे हैं। मौजूदा कोलेजियम सिस्टम का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह गोपनीयता के अंधेरे में काम करता है। ऐसे देश में जहां पर पारदर्शिता की संस्कृति विकसित करने में न्यायपालिका की सबसे बड़ी भूमिका रही हो, उसका न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले में सब कुछ गोपनीय रखने के प्रति आग्रही होना समझ से परे है। हमारे देश में न्यायाधीशों को बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। वे नागरिक अधिकारों के प्रहरी हैं। देशभर से चुनकर आए सांसदों द्वारा पारित कानून पर न्यायाधीश रोक लगा सकता है। देश के करोड़ों लोग अपनी परेशानी के क्षणों में अदालतों पर भरोसा करते हैं। बाढ़, सूखा और महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं में भी आम आदमी को अदालतों ने राहत पहुंचाई है। ऐसे में न्यायाधीश अब केवल न्यायपालिका के परिवार के सदस्य मात्र नहीं हैं। वे करोड़ों लोगों के भरोसे का केंद्र भी हैं। इसलिए उनकी नियुक्ति को न्यायपालिका का आंतरिक मामला नहीं माना जा सकता।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले छानबीन की जरूरत

चूंकि न्यायाधीश भी हमारे समाज का हिस्सा हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण जैसे महत्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर उसमें अन्य को भागीदार बनाया जाए। इसके लिए कोलेजियम व्यवस्था की निर्णय प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि के व्यापक छानबीन की जरूरत है। इसमें अमेरिका के अनुभवों से हम सीख सकते हैं। वहां सीनेट की न्यायिक समिति देश के आम और खास लोगों से उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगती है, जिसे न्यायाधीश के रूप में नामित किया जाता है। इससे लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। तय समय सीमा के अंदर उस पर विचार करके निर्णय होता है और इस तरह से असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने का मौका मिलता है। कोलेजियम सिस्टम भी जरूरत के मुताबिक संशोधन करके इस व्यवस्था को अपना सकता है।

6 साल बाद भी अधर में प्रमोशन

मामला अभी विचाराधीन है

6 साल से प्रमोशन पर रोक होने के कारण कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। इन 6 सालों में अब तक 70 हजार से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं। जिनमें से करीब 39 हजार कर्मचारी रिटायरमेंट तक पदोन्नति का इंतजार करते रह गए, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला इसे देखते हुए अब सरकार नए पदोन्नति नियम बनाने जा रही है, जिससे न्यायालय की अवमानना भी न हो ओर राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन भी हो जाए। प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसमें कर्मचारियों की नाराजगी सरकार पर भारी ना पड़े इसलिए ये फैसला बहुत तेजी में लेने की तैयारी की जा रही है। हालांकि फैसला लेने के बावजूद सरकार को प्रमोशन में आरक्षण पर आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए नए पदोन्नति नियमों का खाका कुछ इस तरह तैयार किया गया है कि कोर्ट के आदेश पर भी अमल करने में कोई चूक ना हो। प्रदेश में फिलहाल 2016 से सरकारी विभागों में प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, यह इंतजार कब खत्म होगा यह कोई नहीं जानता। मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मई 2016 में यथास्थिति (स्टेटस-को) रखने के निर्देश दिए हैं। तब से प्रदेश में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति पर रोक लगी है। दूसरी ओर जिम्मेदार लोग सिर्फ बैठकों में व्यस्त हैं और भरोसा दिलाया जा रहा है कि सब ठीक होगा, लेकिन कर्मचारियों का सब्र अब टूटने लगा है क्योंकि प्रमोशन का इंतजार करते-करते 70,000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं और यह क्रम लगातार जारी है।

मप्र में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति 6 साल से रुकी हुई है, लेकिन सरकार अभी तक पदोन्नति का रास्ता नहीं निकाल पाई है। आलम यह है कि मप्र उच्च न्यायालय में पदोन्नति के मामले में सरकार के बार-बार हराने के बाद कर्मचारियों की पदोन्नति अटका रखी है। न्यायालय के आदेशों की अवहेलना पर पशु पालन विभाग के अधिकारियों को 13 दिसंबर को फिर से तलब किया गया था। दरअसल मप्र उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 30 जून 2016 द्वारा मप्र सरकार के पदोन्नति नियम 2002, आरक्षण के असंवैधानिक प्रावधानों के कारण अपास्त कर दिए गए थे। निर्णय के विरूद्ध सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सरकार की रोक की मांग न स्वीकारते हुए स्टेटस के अंतरिम आदेश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की गलत व्याख्या कर शासन द्वारा विगत 6 वर्षों से प्रदेश में सभी पदोन्नतियां बाधित कर दी गई हैं। जबकि उक्त निर्णय में कहीं भी अनारक्षित (सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक) वर्ग की पदोन्नति पर कोई प्रतिबंध नहीं था।

दरअसल, हाईकोर्ट के 30 अप्रैल 2016 के जिस फैसले को आधार बनाते हुए पदोन्नतियां रोकी गईं, वो सिर्फ पदोन्नति नियम 2002 के रिजर्वेशन रोस्टर तक सीमित है। बाकी पदोन्नति अभी भी यथावत हैं। जानकारों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले की शब्दश: व्याख्या नहीं होने के चलते पदोन्नतियां रोकी गईं। उस फैसले के पैरा 27 में स्पष्ट है कि पदोन्नति नियम में रिजर्वेशन, बैकलॉग रिक्तियों को कैरीफॉवर्ड करना एवं रोस्टर के ऑपरेशन के प्रावधान संविधान के विरूद्ध हैं। बाकी नियम के जरिए पदोन्नतियां की जा सकती हैं। बता दें कि प्रमोशन पर रोक के चलते बीते पांच साल में एक लाख से ज्यादा अधिकारी-कर्मचारी बिना पदोन्नत हुए रिटायर हो गए। पदोन्नति शुरू नहीं हुई तो हर साल 7 से 8 हजार कर्मचारी बिना प्रमोशन रिटायर होते रहेंगे।

वर्ष 2018 में धीरेंद्र चतुर्वेदी विरूद्ध मप्र शासन प्रकरण में उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति के अंतरिम आदेश की स्पष्ट व्याख्या दी थी तथा यह स्पष्ट किया था कि पदोन्नति नियम 2002 से पदोन्नति प्राप्त सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारियों-कर्मचारियों की पदोन्नति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इन नियमों में आरक्षण के असंवैधानिक प्रावधानों से पदोन्नति प्राप्त अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मियों को पदावनत करने के आदेश उच्च न्यायालय के निर्णय में दिए गए थे। अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति के अंतरिम आदेश का आशय मात्र यह था कि अंतिम निर्णय तक इन अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के कर्मियों को पदावनत न किया जाए। पुन: पशु पालन विभाग के 11 सामान्य ओबीसी वर्ग के पशु चिकित्सकों ने अवैधानिक रूप से पदोन्नति रोकने के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील की थी। न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय देते हुए समय सीमा निर्धारित कर पदोन्नति देने का निर्णय दिया था। इस प्रकरण में सरकार की रिव्यू पिटीशन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई। न्यायालय द्वारा बार-बार स्पष्ट व्याख्या देने के बावजूद विगत 6 वर्षों से मप्र सरकार द्वारा सामान्य पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के कर्मचारियों-अधिकारियों की पदोन्नतियां अकारण और अवैधानिक तरीके से रोकी गईं हैं। जिसके कारण बड़ी संख्या में हजारों कर्मचारी-अधिकारी बिना कोई पदोन्नति का लाभ प्राप्त किए ही सेवानिवृत्त हो चुके है। सैकड़ों कर्मचारी सेवानिवृत्ति की कगार पर हैं। उच्च न्यायालय ग्वालियर द्वारा स्पष्ट आदेश के बाद भी पशु चिकित्सकों को पदोन्नतियां नहीं दी गई। गत पांच दिसंबर को इसी प्रकरण में न्यायालय की अवमानना सुनवाई में प्रमुख सचिव पशु चिकित्सा विभाग तथा संचालक पशु चिकित्सा विभाग को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पड़ा। न्यायालय ने नाराजगी जताते हुए शासन द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हेतु कड़ी आलोचना की और पुन: 13 दिसंबर को संबंधित अधिकारियों को तलब किया था। न्यायालय की कठोर टिप्पणियों के बाद अब प्रकरण पर संभवत: कार्यवाही की जा रही है। स्पीक की मांग है कि सामान्य, पिछड़ा व अल्पसंख्यक वर्ग की पदोन्नतियां तत्काल प्रारंभ करें।

● सुनील सिंह

गुजरात-हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं और दिल्ली नगर निगम के चुनाव नतीजों पर अगर समग्र दृष्टि डाली जाए तो इन नतीजों ने जी-जान से जुटे और पूरी ताकत से जूझे हुए सत्ता के दावेदार तीनों राजनीतिक दलों को झटका भी दिया तो जश्न मनाने का मौका भी दे दिया। साथ ही इन चुनावों के नतीजों ने अगले साल कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों और उसके छह महीनों के भीतर होने वाले लोकसभा चुनावों की पटकथा तैयार कर दी है। ये चुनाव अब चेहरा बनाम चेहरा नहीं, बल्कि चेहरा बनाम मुद्दों की लड़ाई बनने वाले हैं।

● राजेंद्र आगाल

गुजरात, हिमाचल प्रदेश विधानसभा और दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजों ने अगले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों और उसके 6 महीनों के भीतर होने वाले लोकसभा चुनावों की पटकथा तैयार कर दी है। ये चुनाव अब चेहरा बनाम चेहरा नहीं, बल्कि चेहरा बनाम मुद्दों की लड़ाई बनने वाले हैं। गुजरात, हिमाचल विधानसभा और दिल्ली नगर निगम चुनाव तीन किले की तरह थे, जो जनता ने तीन पार्टियों क्रमशः भाजपा, कांग्रेस और आप को सौंपे। यह भारतीय लोकतंत्र का उन सबको करारा जवाब है, जो देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर सशंकित रहते हैं, ईवीएम पर संदेह करते हैं और यदा-कदा चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठाते हैं। इन चुनावों ने देश की अन्य राजनीतिक पार्टियों के सामने एक मिसाल खड़ी कर दी है। इसी के साथ 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का आधार भी हो गया है।

मोदी मैजिक के बीच मतदाताओं ने राजनीतिक पार्टियों को संदेश दे दिया है कि वे किसी झांसे या भ्रम में पड़कर वोट नहीं देते हैं। यानी आज भारत का मतदाता पूरी तरह सोच-समझकर अपने मत का प्रयास करता है। इसी का परिणाम है कि गुजरात में भाजपा की प्रचंड आंधी में कांग्रेस और आप उड़ गए, हिमाचल में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस ने और दिल्ली नगर निगम चुनावों में, जहां हिमाचल के 56 लाख के मुकाबले 79 लाख मतदाता हैं, आप को पूर्ण बहुमत मिला।

तीन चुनाव, अलग-अलग रंग

गुजरात-हिमाचल प्रदेश विधानसभाओं और दिल्ली नगर निगम के चुनावों के नतीजों ने अगले कुछ राज्यों के विधानसभा चुनावों और उसके छह महीनों के भीतर होने वाले लोकसभा चुनावों की पटकथा तैयार कर दी है। ये चुनाव अब चेहरा बनाम चेहरा नहीं, बल्कि चेहरा बनाम मुद्दों की लड़ाई बनने वाले है। भाजपा ने जहां मुद्दों से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और करिश्मे के बल पर गुजरात चुनाव में ऐतिहासिक कामयाबी पाई है और पहले भी हर चुनाव को मोदी करिश्मे से जीतने की कोशिश करती रही है और आगे भी करेगी, वहीं कांग्रेस, जो मोदी के मुकाबले कोई वैसा मजबूत चेहरा न होने की वजह से कमजोर पड़ती रही है, ने हिमाचल प्रदेश में चेहरे से ज्यादा मुद्दों पर जोर देने की रणनीति अपनाई और चुनाव जीतने में कामयाब रही है। कुछ इसी तरह आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम चुनावों में राजधानी के कूड़े को एक ऐसे जिताऊ मुद्दा बनाने में सफल रही कि उसने 15 साल से जमी भाजपा को हरा दिया। कुल मिलाकर चेहरा बनाम चेहरा की राजनीति अब चेहरा बनाम मुद्दों में बदलती नजर आ रही है।

संसदीय प्रणाली वाले भारतीय लोकतंत्र में पिछले करीब एक दशक से मुद्दों पर चेहरा भारी पड़ता रहा है। चाहे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव रहे हों या राज्यों के विधानसभा चुनाव ज्यादातर मामलों में मुद्दों पर चेहरा भारी पड़ता रहा है और चेहरा यानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता व करिश्मे ने कई बार भाजपा को बढ़त दिलाई है। लेकिन राज्यों के चुनावों में कई बार ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, के. चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी के चेहरे अपने-अपने राज्यों में मोदी के चेहरे और भाजपा पर भारी भी पड़े हैं। यानी ज्यादातर चुनाव मुद्दों से ज्यादा प्रतिद्वंद्वी दलों के नेताओं के चेहरों के बीच हुए और जो चेहरा भारी पड़ा उसके दल को कामयाबी मिली। इसी साल हुए उप्र विधानसभा के चुनावों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरों की संयुक्त

हिमाचल में क्यों नहीं गुजरात जैसा प्रदर्शन!

गुजरात में भाजपा की लगातार सातवीं बार जीत उसके लिए एक ऐतिहासिक और उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह उपलब्धि भाजपा की नीतियों, उसकी सरकार के कार्यों और नेतृत्व के प्रति गुजरात की जनता के भरोसे को व्यक्त करती है। इसके पहले लगातार सात बार जीत का रिकॉर्ड पश्चिम बंगाल में वाम दलों ने बनाया था। आश्चर्य नहीं कि भाजपा वाम दलों के रिकॉर्ड को तोड़ दे। जो भी हो, इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वाम दलों के सत्ता में रहते समय बंगाल में किस तरह चुनावी हिंसा होती थी। यह भी एक तथ्य है कि वाम दलों ने अपने लंबे शासनकाल में बंगाल को खस्ताहाल कर दिया, जबकि भाजपा के शासन में गुजरात तरक्की कर गया। स्पष्ट है कि आज के सूचना प्रधान युग, चुनाव आयोग एवं मीडिया की सक्रियता और ईवीएम के दौर में लगातार सातवीं बार जीत हासिल करना कहीं अधिक मायने रखता है। शायद यही कारण है गुजरात के नतीजों की धमक पूरे देश में सुनाई दे रही है। गुजरात के परिणाम यह भी बता रहे हैं कि राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वैसा ही विश्वास बना हुआ है, जैसे उनके मुख्यमंत्री रहते था। इसमें संदेह नहीं कि पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात का चौतरफा विकास करके दिखाया है। भाजपा को गुजरात में 156 सीटें मिलना इसलिए विशेष है, क्योंकि पिछली बार उसे 99 सीटें ही मिली थीं। तब कांग्रेस ने उसे कड़ी टक्कर दी थी और 77 सीटें हासिल की थीं। इसका एक कारण पाटीदारों के आंदोलन के साथ नोटबंदी और जीएसटी का असर था। यह समझना कठिन है कि इस बार कांग्रेस गुजरात में पूरी ताकत से चुनाव क्यों नहीं लड़ी? कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी केवल एक दिन के लिए गुजरात प्रचार करने गए।

लोकप्रियता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के चेहरों की लोकप्रियता पर भारी पड़ी। पंजाब में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के चेहरों ने कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। इन चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को चेहरे की बजाय मुद्दों पर लड़ने की रणनीति अपनाई। गुजरात में पार्टी को पहले से ही अनुमान था कि वह कितना भी कर ले वहां उसे कामयाबी नहीं मिलनी है, इसलिए वहां का चुनाव पूरी तरह स्थानीय नेताओं और विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के भरोसे छोड़ दिया गया। चुनाव मोदी बनाम राहुल न बने, इसलिए न तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा के मार्ग में गुजरात को शामिल किया गया, बल्कि राहुल गांधी चुनाव प्रचार में सिर्फ एक दिन के लिए गुजरात गए, जहां उन्होंने दो जनसभाओं को संबोधित किया। पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने काफी देर से कुछ दिनों तक चुनाव प्रचार किया।

हिमाचल में परंपरा कायम

इसके उलट कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए वहां चेहरे पर नहीं, बल्कि उन मुद्दों को उठाने पर जोर दिया जो जनता के बीच बेहद ज्वलंत थे। यूं तो प्रियंका गांधी लगातार हिमाचल प्रदेश में प्रचार करती रहीं, लेकिन कांग्रेस का पूरा प्रचार अभियान प्रियंका या किसी भी अन्य नेता पर केंद्रित होने की बजाय ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना), अग्निवीर भर्ती योजना, सेब किसानों के उत्पादों की पैकेजिंग पर जीएसटी, रसोई गैस और पेट्रोल-डीजल की मंहगाई और बेरोजगारी पर केंद्रित रहा। वहीं भाजपा ने पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर केंद्रित रखा। भाजपा को सबसे ज्यादा मोदी की लोकप्रियता पर भरोसा था और उसका आंकलन था सत्ता विरोधी रुझान

9 राज्यों में होने वाले चुनाव में दिखेगा असर

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के बाद अगले वर्ष कम से कम 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। उन्हें एक तरह से अगले आम चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाएगा। यदि मप्र, छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान में कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन नहीं करती, जहां उसका भाजपा से सीधा मुकाबला होगा तो उसके राष्ट्रीय स्तर पर उत्थान की संभावनाएं और कम होंगी। कांग्रेस की जैसी स्थिति है, उसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि हिमाचल की जीत कांग्रेस नेताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। राहुल गांधी भले ही भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपनी व्यक्तिगत छवि मजबूत करने में जुटे हों, लेकिन वह पार्टी को कोई सही दिशा नहीं दे पा रहे हैं। यह काम बतौर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी नहीं कर पा रहे हैं।

जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहा जाता है, पर मोदी करिश्मा भारी पड़ेगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने चार लोकसभा सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में छह चुनावी रैलियां कीं, और हिमाचल से अपने पुराने रिश्तों का हवाला देकर अपने लिए वोट मांगा। भाजपा के बागियों को मनाने की पहल भी खुद प्रधानमंत्री ने की। लेकिन चुनाव नतीजों में चेहरों पर मुद्दे भारी पड़े। हालांकि कांग्रेस और भाजपा को मिले मतों का अंतर महज 0.9 फीसदी ही है, लेकिन पिछले चुनावों की तुलना में भाजपा के मत प्रतिशत में पांच फीसदी की गिरावट भी आई है। लेकिन गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, कड़ी मेहनत और गृहमंत्री अमित शाह के चुनाव प्रबंधन ने कांग्रेस की कथित लो प्रोफाइल चुनाव रणनीति को ध्वस्त कर दिया। भाजपा ने न सिर्फ कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी के 149 सीटों के रिकार्ड को तोड़ा, बल्कि कांग्रेस को भी अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया। अपनी रणनीति के अलावा भाजपा को कांग्रेस नेतृत्व और आम आदमी पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने गुजरात में उसे ऐतिहासिक जीत दर्ज करने का रास्ता आसान कर दिया। 2017 के विधानसभा चुनावों में 99 के फेर में फंसी भाजपा और मोदी-शाह की जोड़ी ने इस बार तय कर लिया था कि वह किसी भी तरह की कहीं कोई चूक नहीं होने देंगे, जिससे भाजपा के हाथ से गुजरात की सत्ता फिसलने की सियासी दुर्घटना हो जाए। इसलिए भाजपा और खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कोई भी ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां से घुसकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उसके खेल को बिगाड़ सके।

2017 में 99 सीटों के दूध से जली भाजपा ने 2022 के छाछ को फूंक-फूंक कर पिया। वहीं कांग्रेस के 2017 में शानदार प्रदर्शन के बाद गुजरात की फाइल हमेशा की तरह अलमारी में बंद कर दी गई और उसे तब निकाला गया जब चुनाव में महज छह महीने बचे थे। कांग्रेस जिसे गुजरात की जनता ने 77 सीटें देकर एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का जनादेश दिया था, इसमें पूरी तरह विफल रही थी। चुनाव के कुछ महीनों के भीतर ही उसके कई विधायक पाला बदलकर भाजपा में चले गए। संगठन की सक्रियता का आलम ये रहा कि लंबे समय तक पार्टी अध्यक्ष और प्रभारी विहीन रही। प्रभारी राजीव सातव के आकस्मिक निधन के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने किसी को गुजरात का प्रभारी तक नहीं बनाया। चुनाव से कुछ महीने पहले राजस्थान के मंत्री रघु शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई। पूरे पांच साल तक कांग्रेस ने न तो विधानसभा और न ही सड़कों पर जनता के किसी भी मुद्दे को लेकर कोई आवाज उठाई या संघर्ष किया। यहां तक कि विधायक दल के नेता और कुछ अन्य विधायक चुनाव से ठीक पहले पाला बदलकर भाजपा में चले गए। ऐसी कमजोर और लड़खड़ाती मुद्दा विहीन, चेहरा विहीन कांग्रेस पर मोदी-शाह के नेतृत्व वाली भाजपा को भारी पड़ना ही था।

मप्र में टिकट के 3 फॉर्मूले

4 साल बाद देश के किसी राज्य हिमाचल प्रदेश में मिली पूर्ण बहुमत की जीत से उत्साहित कांग्रेस ने मप्र में टिकटों के बंटवारे के लिए 3 फॉर्मूले तय किए हैं। **पहला**- विनेबिलिटी यानी जिताऊ उम्मीदवार। **दूसरा**- हाल में हुए नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में परफॉर्मेंस। **तीसरा**- अहम क्राइटेरिया पार्टी के सर्वे में नाम होना है। तीनों में पास होने के बाद उम्मीदवारों का नाम तय होगा फिर चाहे वह युवा हो या उम्रदराज। पार्टी की वर्तमान 96 सीटों में से 75 से 80 पर सिटिंग एमएलए ही उम्मीदवार होंगे। बाकी 16 सीटों पर सिटिंग एमएलए बदले जा सकते हैं। इनमें 8 से 10 सीटें मालवा-निमाड़ की हैं। 3 सीटें ग्वालियर-चंबल और 2 सीटें बुंदेलखंड की हैं। निमाड़ में बड़वाह से कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भाजपा का दामन थाम चुके हैं, लेकिन वे अभी भी तकनीकी रूप से कांग्रेस के विधायक हैं, इस सीट से कांग्रेस ने उम्मीदवार खोजना शुरू कर दिया है।

21 सीटें, जहां प्रत्याशी रिपीट होंगे- दतिया, विजयपुर, अटेर, ग्वालियर पूर्व, बीना, टीकमगढ़, चंदला, टीकमगढ़, जबेरा, नागोद, अमरपाटन, देवतालाब, धौहनी, सिंगरौली, शुजालपुर, इंदौर-3, रतलाम ग्रामीण, गरोठ और जावद आदि सीट पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार 2018 में 5 हजार से कम वोटों से हारे थे, उन्हें टिकट देने की तैयारी है। इन्हें कह दिया गया है कि क्षेत्र में समय दें। कोलारस और जावरा सीट पर हारे उम्मीदवारों के भाजपा में शामिल होने से यहां चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है।

यहां भाजपा के नेताओं पर नजर- सांची, सुरखी, सांवेर, मेहगांव, ग्वालियर, भांडेर, पोहरी, बमोरी, अशोकनगर, मुंगावली और सुवासरा में भाजपा के असंतुष्ट नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। ये वे लोग हैं, जो कांग्रेस से भाजपा में गए उम्मीदवारों का टिकट रिपीट होने पर अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख रहे हैं।

इन सीटों पर उम्मीदवार ऐसे होंगे, जिनकी क्षेत्र में हो सक्रियता- रहली, नरयावली, सागर, खुरई, गुना, शिवपुरी, अंबेडकर नगर, इंदौर दो, इंदौर-4, इंदौर-5, विजावर, पथरिया, हटा, सिरमौर, सेमरिया, त्योंथर, रामपुरबघेलान, रीवा, सीधी, देवसर, जैतपुर, बांधवगढ़, मानपुर, मुड़वारा, जयसिंह नगर, जबलपुर कैंट, पनागर, सिहोरा, परसवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, आमला, टिमरनी, सिवनी मालवा, हरदा, होशंगाबाद, सोहागपुर, पिपरिया, भोजपुर, कुरवाई, शमशाबाद, बैरसिया, नरेला, हुजूर, गोविंदपुरा, बुधनी, आष्टा, सीहोर आदि सीटों पर कांग्रेस 3-4 चुनावों से हार रही है। यहां सक्रियता और लोकप्रियता देखकर टिकट दिया जाएगा।

अपने-अपने मुद्दे

गुजरात के रण में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बड़े जोरशोर से कूदी। नगर निगम चुनावों में सूरत में मिली 28 सभासदों की जीत की कामयाबी से उसका हौसला बढ़ गया। आप ने पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और मुफ्त बिजली के मुद्दों पर भाजपा को चुनौती दी। उसकी इस चुनौती के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राज्य के स्कूलों में जाकर हालात का जायजा लेना पड़ा। आप के इन मुद्दों ने गुजरात में मोदी के चेहरे, गुजराती अस्मिता और हिंदुत्व के बल पर 27 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज भाजपा को हिला दिया। लगा कि इस बार मुकाबला भाजपा बनाम आप हो जाएगा। लेकिन जल्द ही आम आदमी पार्टी मुद्दों से हटकर अपने प्रमुख चेहरे अरविंद केजरीवाल पर आ गई। उसे लगा कि मोदी के मुकाबले केजरीवाल का चेहरा और विकास के गुजरात मॉडल पर दिल्ली मॉडल भारी पड़ेगा। भाजपा के हिंदुत्व के मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी ने भारतीय रुपए पर गणेश-लक्ष्मी के चित्र छापने की मांग शुरू कर दी।

मुस्लिम परस्ती के आरोप से बचने के लिए बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई पर चुप्पी साध ली। यानी आप ने जनता के मुद्दों की बजाय भाजपा का मुकाबला उसके ही हथियार से करने की कोशिश की। नतीजा यह हुआ कि आप ने करीब 13 फीसदी वोट हासिल करके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो पा लिया, लेकिन राज्य की राजनीति को विपक्ष विहीन भी कर दिया। उसके महज पांच विधायक जीते और तीस विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के वोट विभाजित होने का फायदा सीधा भाजपा को मिला। यह साबित हो गया गुजरात में मोदी से बड़ा चेहरा किसी भी दल के पास नहीं है और अगर भाजपा का मुकाबला करना है तो उसे चेहरे पर नहीं मुद्दों पर ही लड़ा जा सकता है जैसा कि कांग्रेस ने 2017 में किया था और हार के बावजूद उसने मोदी के चेहरे के बावजूद भाजपा की जीत बहुत कठिन कर दी थी। यही बात लोकसभा चुनावों में भी लागू होती है क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी के मुकाबले कोई दूसरा लोकप्रिय चेहरा नहीं है और यह भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव, नवीन पटनायक, एमके स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी क्षेत्रीय चेहरे तो हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये अभी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

कांग्रेस ने इसे समझ लिया है। इसलिए राहुल गांधी खुद को चेहरा बनाने से ज्यादा जोर उन मुद्दों पर दे रहे हैं जिन्हें लेकर वह भारत जोड़ो पदयात्रा पर निकले हैं। इसे उनकी इस बात से भी समझा जा सकता है, जब उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं राहुल गांधी को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। आप अभी भी राहुल गांधी को देख रहे हैं। राहुल के इस कथन का सीधा मतलब है कि अब वह कांग्रेस की राजनीति को राहुल गांधी या किसी व्यक्ति पर आधारित करने की बजाय उसे मुद्दों पर आधारित करना चाहते हैं। वह कहते हैं कि उनकी भारत जोड़ो पदयात्रा किसी चुनावी या राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं है बल्कि देश को भीतर से तोड़ने वाली विभाजनकारी विचारधारा और नीतियों के खिलाफ है तब इसका सीधा मतलब है कि वह मुद्दों पर जनता को गोलबंद करना चाहते हैं। इसीलिए हर जगह वह समाज में नफरत के साथ-साथ महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी जीएसटी के कारण पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था, आदिवासी बनाम वनवासी जैसे मुद्दे भी लगातार उठा रहे हैं।

भाजपा पर भारी पड़ा केजरीवाल का राजनीतिक कोलाज

2017 के नगर निगम चुनावों की तुलना में देखें तो भाजपा की हार बड़ी है, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों की नजर में देखें तो आम आदमी पार्टी की जीत भी बड़ी नहीं है। फिर भी यह सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि अपने उभार के बाद केजरीवाल तकरीबन हर चुनाव में दिल्ली की जनता का भरोसा जीत लेते हैं? लोकसभा चुनाव जरूर इसके अपवाद हैं, जिनमें अब तक दोनों बार केजरीवाल को मुंह की खानी पड़ी है। 2013 में केजरीवाल के उभार के बाद लोकसभा के दो चुनाव हुए हैं। दोनों ही चुनावों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, इसका फायदा भाजपा को मिला भी। लेकिन कुछ महीनों बाद जैसे ही विधानसभा चुनाव आए, दिल्ली भाजपा में वैसा उत्साह नजर नहीं आया। जिनसे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन की उम्मीद रहती है, विधानसभा चुनावों की रणनीति के मसले पर वे पल्ला झाड़ते दिखे। जबकि अमित शाह ने खुद प्रचार का मोर्चा संभाल रखा था। इसका असर इतना ही हुआ कि 2015 की 67 विधानसभा सीटों के मुकाबले आम आदमी पार्टी की पांच सीटें कम हो गईं। दरअसल दिल्ली में भाजपा को संभालने वाली जो ताकतें हैं, उनके मानस अब भी दिल्ली की पुरानी जनसांख्यिकी पर केंद्रित है। आजादी के बाद दिल्ली की जनसंख्या सिर्फ छह लाख थी। तब दिल्ली का दायरा परकोटे के अंदर के शहर से कुछ ही बड़ा था। बंटवारे के बाद दिल्ली में पश्चिमी पंजाब के शरणार्थियों की आवक बढ़ी। इस वजह से पिछली सदी के 80 के दशक तक पंजाबी, बनिया और शरणार्थी समुदाय की दिल्ली की जनसंख्या में प्रभावी उपस्थिति थी। तब दिल्ली देहात के जाट और गुर्जर समुदाय के लोगों का भाजपा में प्रभाव कम था या यूं कह सकते हैं कि भाजपा की पहुंच भी इन समुदायों तक कम थी।

राहुल की यात्रा प्रभावहीन

राहुल गांधी को अहसास है कि उनकी यात्रा में जो उनके समर्थन के लिए भारी तादाद में लोग आ रहे हैं वे राहुल गांधी या किसी व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उन मुद्दों के लिए आ रहे हैं जो यात्रा में उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों ने मुद्दों की राजनीति को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ किया है। कांग्रेस के साथ-साथ बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल (यू) के नेता नीतीश कुमार ने भी मुद्दों के आधार पर विपक्षी एकता की बात कही है। नीतीश भी विपक्षी खेमे में नेता की बजाय मुद्दों पर जोर दे रहे हैं। इससे एक तरफ विपक्ष में नेता को लेकर होने वाले विवाद से बचा जा सकेगा, तो दूसरी तरफ भाजपा के 'मोदी के मुकाबले कौन' के राजनीतिक विमर्श की धार को भी कमजोर करके उसे मुद्दों पर घेरा जा सकेगा। इसलिए अगले लोकसभा चुनाव में मुकाबला चेहरा बनाम चेहरा नहीं बल्कि चेहरा बनाम मुद्दे बनाने की विपक्ष की पूरी कोशिश है।

राजनीति में जब झटका लगता है तो उसके किरदार अपना गम छिपाने का बहाना ढूंढ ही लेते

है, लेकिन जब खुशी का थोड़ा भी मौका मिलता है तो उसे मनाने और भुनाने की कोई कसर नहीं छोड़ते। इन चुनाव नतीजों ने तो गम भी दिया तो गम गलत करने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आप को खुशियां भी दे दी। अब देखना यह है कि इन दलों को जो झटके मिले हैं उन पर आगे के लिए कितना मनन करते हैं। अब आगे चुनाव ही चुनाव हैं और 2024 में देश की सत्ता के लिए चुनावी महाभारत तय है।

चिंतन-मनन का मिला मौका

इन चुनावों में विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को हिमाचल प्रदेश में झटका लगा तो गुजरात में उसके हाथ ऐतिहासिक जीत लग गई। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को गुजरात में शर्मनाक हार से गुजरना पड़ा। मगर हिमाचल में उसने भाजपा से आराम से सत्ता छीन ली। तीसरी किरदार आम आदमी पार्टी हिमाचल में खाता भी न खोल सकी और कांग्रेस को पीछे धकेलने के प्रति आश्वस्त होने के बावजूद गुजरात में कांग्रेस से बहुत पीछे रह गई। लेकिन दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के साथ ही उसे राष्ट्रीय दल दर्जे की खुशी मिल गई। इस तरह इन चुनावों ने तीनों ही दलों को खुशी और गम, दोनों ही देकर आत्म चिंतन के लिए वक्त दे दिया। भाजपा का गुजरात में चुनाव जीतना पहले ही तय माना जा रहा था। जीत का अंतर भी काफी अनुमानित था, मगर इतनी बड़ी जीत की संभवतः भाजपाइयों को भी उम्मीद नहीं रही होगी। वहीं, एजेंसियों ने हिमाचल में तो भाजपा को बहुमत मिलते हुए दिखाया, मगर गुजरात में इतनी बड़ी जीत की कल्पना नहीं की।

भाजपा की जीत प्रधानमंत्री मोदी का गृह राज्य होने, मोदी का करिश्मा और गुजरात के गौरव जैसे भावनात्मक कारणों से सुनिश्चित ही थी। सन् 2017 के मुश्किल चुनाव को ध्यान में रखकर न केवल भाजपा ने, अपितु प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उन्हें 2017 के चुनाव की तरह अपने सम्मान और स्वाभिमान को गुजरात के स्वाभिमान से जोड़ना पड़ा। देशभर से गुजरात गए बाकी पार्टी नेताओं का ध्यान भी हिंदुत्व पर रहा। इसलिए भाजपा की

भारी जीत पहले ही पक्की हो गई थी। वहीं, भाजपा को हिमाचल से जो झटका लगा उसकी गूंज आने वाले चुनावों तक जा सकती है। वह इसलिए कि हार के महंगाई, बेराजगारी, भ्रष्टाचार और एंटी इंकम्बेंसी जैसे जो कारण हिमाचल में थे वे अगले साल 9 राज्यों में होने वाले चुनावों में उभर सकते हैं। भाजपा ने उत्तराखंड में बारी-बारी चुनाव जीतने का ट्रेंड तो तोड़ दिया मगर ट्रेंड को हिमाचल में पूरी ताकत लगाने के बाद भी तोड़ न सकी। मोदी का करिश्मा इस हिमालयी राज्य में न चल सका। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के क्षेत्रों में तक पार्टी हार गई। भाजपा अब तक 12 राज्यों में पूरी तरह और महाराष्ट्र में शिंदे गुट की शिवसेना के साथ सत्ता भागीदार थी। हिमाचल के हाथ से निकलने के बाद उसके पास 11 राज्य रह गए जहां पूरी तरह उसकी हुकूमत है। अगले साल होने वाले चुनाव में उसे त्रिपुरा, कर्नाटक और मप्र की सत्ता भी बचानी है। जहां उसका मुख्य मुकाबला कांग्रेस से होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी वहां भी भाजपा की मदद कर सकती है।

16 राज्यों में नहीं खुला खाता

आम आदमी पार्टी 10 वर्षों के अपने जीवनकाल में अब तक 18 राज्यों में 21 चुनाव लड़ चुकी थी। इनमें से 15 चुनावों में वह जीरो पर आउट हो गई थी। अब खाली हाथ वाला सोलहवां राज्य हिमाचल बन गया है। लेकिन इस बार उसका खाता गुजरात में खुल ही गया। इस प्रकार वह दिल्ली, पंजाब, गोवा के बाद गुजरात में अस्तित्व में होने के कारण राष्ट्रीय दल बनने की हकदार बन गई। लेकिन उसका पहला लक्ष्य भाजपा न होकर कांग्रेस मुक्त भारत का है ताकि वह कांग्रेस की जगह ले सके और यह लक्ष्य फिलहाल संभव नजर नहीं आता। अलबत्ता विपक्षी एकता में सबसे बड़ा बाधक अवश्य बन सकता है। लोकसभा के 2024 में होने जा रहे चुनाव से पहले 2023 फरवरी में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके बाद मई में कर्नाटक के चुनाव, नवंबर में छत्तीसगढ़, मिजोरम और मध्य प्रदेश के चुनाव और दिसंबर में राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा के चुनाव होने हैं। इनमें से नवंबर और दिसंबर में होने वाले चुनावों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। इसलिए आने वाला साल भी चुनावी गहमागहमी वाला होने वाला है। इन चुनावों में केजरीवाल की पार्टी जरूर किस्मत आजमाएगी और उसे खाता खोलने का मौका मिले या न मिले मगर कांग्रेस को पलीता लगाने का मौका अवश्य मिल जाएगा। इन चुनावों में कांग्रेस अपने नए गढ़ बचाने के साथ ही कर्नाटक और मप्र के जैसे लुटे हुए गढ़ पुनः जीतने का प्रयास करेंगी।

कांग्रेस को अभी और चिंतन-मनन और मेहनत की जरूरत

कांग्रेस जो वर्ष 2017 के गुजरात चुनाव में भाजपा को टक्कर देती नजर आ रही थी, वह इस बार चारों खाने चित हो गई। अगर यह कहा जाए कि कांग्रेस नेतृत्व ने गुजरात चुनाव लड़ने की अनिच्छा जताई तो कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस के मुख्य प्रचारक राहुल गांधी पूरी तरह अपनी भारत जोड़ो यात्रा के प्रति समर्पित रहे। वह केवल एक दिन के लिए गुजरात में कैंपेनिंग करने आए। पार्टी कहीं से भी मतदाताओं को यह संदेश नहीं दे पाई कि वह 27 साल पुराने भाजपा के राज को उखाड़ फेंकेगी। शायद यही कारण रहा कि पार्टी के 12 प्रतिशत से अधिक वोटर आम आदमी पार्टी की तरफ चले गए। कई विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को भारी नुकसान पहुंचाया और वो 27.3 प्रतिशत वोटों और 17 सीटों तक सिमट गई, जबकि उसे पिछले चुनावों में 35-40 प्रतिशत के बीच मत मिलते रहे हैं। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा भी है कि लोकतंत्र में हार-जीत होती है। गुजरात की जनता का जनादेश हम स्वीकार करते हैं। हम अपनी विचारधारा से समझौता करें बिना लड़ते रहेंगे और जो कमियां हैं, उन्हें हम दूर करेंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस को कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र में एक सशक्त विपक्ष का रहना भी जरूरी है। सत्तापक्ष पर चेक-बैलेंस नहीं होगा तो लोकतंत्र ही हारेगा। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो जो लंबे-चौड़े वादे संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को लेकर किए थे, वह सभी गलत साबित हुए।

आप बिगाड़ेगी खेल

छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की शुरुआत हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बारी-बारी से राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों की टीम भी प्रदेश में पहुंच रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों में कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद आप अब हर गांव में 20-20 लोगों को जोड़ने का प्लान बना रही है। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि आप नेताओं ने 2023 के विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने कई विधानसभा सम्मेलन किए थे उसके बहाने पार्टी का विस्तार हुआ। अब गांव-गांव तक संगठन को पहुंचाने की तैयारी है। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में टीमें बनाई गई हैं। जानकारी के अनुसार कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ है, इसके बाद से प्रदेश में चुनावी मुकाबले दो तरफा ही रहे हैं। आम आदमी पार्टी इसे बदलने में जुट गई है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सभी बड़े पार्टी नेताओं का छत्तीसगढ़ का दौरा तेजी से शुरू हो गया है। इस दौरान उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि पार्टी यहां सभी 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसी को देखते हुए पार्टी नेता **संगठन विस्तार** करने में अपना फोकस कर रहे हैं। पार्टी की रणनीति इस बात पर आधारित है कि राज्य के लोग कांग्रेस और भाजपा से ऊब चुके हैं, उन्हें तीसरे विकल्प की तलाश है और आम आदमी पार्टी यह कमी पूरी करेगी।

पहले दिल्ली में सत्ता में आए। फिर पंजाब में छाए। फिर हिमाचल और गुजरात चुनाव में भी कूदे और अब मप्र और बाकी राज्यों के लिए भी तैयारी में लगे हैं। अन्ना आंदोलन से चर्चा में आए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जैसे छोटे राज्य में आम आदमी बनकर राजनीति शुरू की थी और अब राष्ट्रीय स्तर के 'खास' हो गए हैं। गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या गुजरात आम आदमी पार्टी जिस भी नए राज्य में चुनाव लड़ रही है, वहां उसके पास पाने के लिए सारा आसमान है, जबकि खोने के लिए कुछ नहीं है। पंजाब की तरह जीत गए तो बल्ले-बल्ले। एकाध सीटें मिलीं या वो भी नहीं जीते तो भी कोई बात नहीं। पार्टी अपनी जमीन तो तलाश ही रही है। वोट परसेंटेज से अगली तैयारी का अंदाजा तो लग ही जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। आप चुनाव जीते या नहीं, उसकी धमक से कांग्रेस का जनाधार जरूर कम हो रहा है। आप के खाते में जो एंटी-भाजपा वोट आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं कांग्रेस के ही खाते से जा रहे हैं। पंजाब में सत्ता की कुर्सी पर से कांग्रेस को धकेलकर उतारने वाली आम आदमी पार्टी, अन्य राज्यों में भी कांग्रेस की लुटिया डुबो रही है। गुजरात चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए। आप यदि इसी तरह कांग्रेस को घाटा लगाती रही तो फायदा भाजपा को पहुंचता रहेगा। और यही हाल रहा तो कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य भी निकल सकते हैं।

राजनीतिक जानकार और दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षक डॉ. संतोष कुमार राय बताते हैं कि आप ने भाजपा को कम नुकसान पहुंचाया है, जबकि कांग्रेस की जमीन ही सरका दी है। इस बात की संभावना प्रबल हो गई है कि मप्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है। आप इन राज्यों में कांग्रेस के लिए वोटकटवा साबित हुई तो इसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। राजस्थान में पिछले चुनाव में 58 सीटों पर हार-जीत का अंतर 5 प्रतिशत से भी कम रहा था। मप्र में पिछले चुनाव में 70 से ज्यादा सीटों पर जीत का अंतर 5 प्रतिशत से कम रहा था। जबकि राजस्थान में 18 सीटों पर यही हाल था। अगर आम आदमी पार्टी कुछ फीसदी वोट भी इधर-उधर करती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में जनता के लिए काफी हद तक बिजली-पानी फ्री कर रखा है। महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री है। स्कूलों और अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था को भी वह अपनी उपलब्धि बताती रही है। इस तरह दिल्ली मॉडल दिखाकर अन्य राज्यों में भी लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश में लगी है। यह अन्य पार्टियों, खासकर कांग्रेस के लिए चुनौती है। आम आदमी पार्टी के पास नए राज्यों में नए चेहरे तैयार करने का विकल्प है। राज्य में नए सामाजिक समीकरण के अनुसार वो नए चेहरों पर दांव खेलती है। इससे एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उसे मिलने की संभावना रहती है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

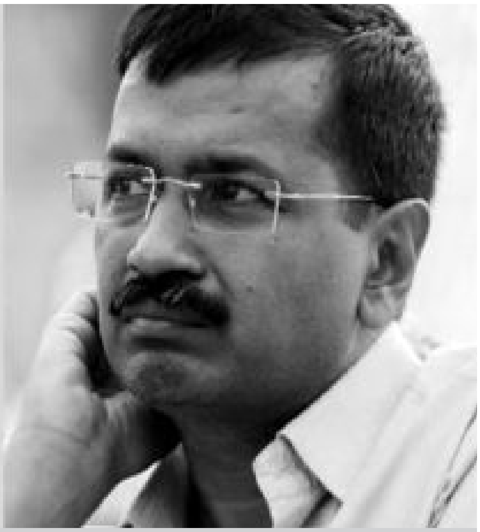

आईएएस की राजनीति में एंट्री

छत्तीसगढ़ में एक और आईएएस अफसर ने अपनी नौकरी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की है। यह अफसर 2013 बैच के शैंकी बग्गा हैं। वह गत दिनों राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहीं से इस्तीफा देकर भाजपा में प्रवेश किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सहित अन्य भाजपा नेता मौजूद थे। शैंकी बग्गा ने सिविल सर्विसेज की नौकरी छोड़ भाजपा ज्वाइन करने और नेता बनने का कारण भी बताया। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागपुर में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की। इस दौरान ट्रेन राजनांदगांव पहुंची तो उसका ग्रांड वेलकम किया गया। इसमें बड़ी संख्या में भाजपा नेता पहुंचे हुए थे। यहीं पर आईएएस अफसर शैंकी बग्गा भी पहुंचे। उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और वीआरएस के लिए आवेदन किया। इसके बाद भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। फिर भाजपा नेताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा ज्वाइन करने के बाद शैंकी बग्गा ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, वह बहुत ही अच्छा है। उससे प्रेरित होकर इस्तीफा दिया। सोचा कि देश सेवा के लिए अपना जीवन व्यतीत करूं। मैंने सात साल आईएएस में काम किया है। उससे समझ में आया कि अभी जो समय है, आने वाले 25 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 40 मिलियन होने वाली है। उसे साकार करने के लिए हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा।

राजनीति में जय सियाराम का नारा लगाने वाले राहुल गांधी पहले नेता तो नहीं हैं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से मिल रहे रिस्पॉन्स के बीच संघ और भाजपा के खिलाफ बड़ा हमला जरूर बोला है, लेकिन क्या कांग्रेस ने भी हिंदुत्व की अपनी लाइन पकड़ ली है? ये ठीक है कि राहुल गांधी की बातों का मजाक बना दिया जाता है। कभी-कभी वो खुद भी ऐसी हरकत कर बैठते हैं, लेकिन हिंदुत्व को लेकर अभी तक कांग्रेस नेता के स्टैंड में कोई बदलाव तो नहीं आया है। वैसे राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि वो हिंदू नहीं हैं।

हिंदुत्व में हिस्सेदारी

राहुल गांधी को अरसे से एक ऐसे अस्त्र की तलाश रही है, जिसे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र जो संघ और भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर सके और येन-केन प्रकारेण वो अपनी पार्टी को फिर से वो जगह दिला सके जो कांग्रेस-मुक्त-भारत कैंपेन से पहले रही।

जैसा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई चुनावी मकसद नहीं है, मतलब ये कि संघ और भाजपा के खिलाफ ही राहुल गांधी सड़क पर उतरे हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि यात्रा नफरत के खिलाफ लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने और उनके करीब पहुंचने का मिशन है और जिस तरह का रिस्पॉन्स यात्रा को मिल रहा है, निश्चित तौर पर राहुल गांधी के लिए उत्साहवर्धक तो है ही। बढ़े चलो।

भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी नए-नए प्रयोग कर रहे हैं। भले ही भाजपा नेता हिमंत बिस्वा सरमा को लगता हो कि दाढ़ी बढ़ाने के बाद वो सद्दाम हुसैन जैसे दिखने लगे हैं। भले भाजपा नेता अमित मालवीय को महाकाल की सीढ़ियों पर राहुल गांधी का साष्टांग प्रणाम दिखावा लगता हो, लेकिन अब संघ और भाजपा नेतृत्व को भी मालूम होना चाहिए कि राहुल गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व के प्रयोग से भी काफी आगे बढ़ चुके हैं।

जैसे गुरिल्ला युद्ध में दुश्मन के खिलाफ घात लगाकर हमले किए जाते हैं और मौका देखकर घुसपैठ, राहुल गांधी भी बिलकुल वही तौर तरीका अपना रहे हैं और खास बात ये है कि कांग्रेस नेता के निशाने पर संघ और भाजपा का हिंदुत्व एजेंडा ही है।

ये सब राहुल गांधी के दिमाग में ऐसे रच बस गया है कि कांग्रेस महंगाई पर भी रैली बुलाती है तो राहुल गांधी हिंदुत्व और हिंदुत्ववादियों में फर्क समझाने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे। लेकिन लड़ाई जब हद से ज्यादा मुश्किल हो तो हल्के-फुल्के दांव और चाल से काम नहीं चलता है। बड़े पैमाने पर गदर मचानी पड़ती है।

संघ और भाजपा के खिलाफ राहुल गांधी ने वैसा ही हथियार खोज निकाला है, जैसे भाजपा तीन तलाक के जरिए मुस्लिम घरों में घुसकर पुरुषों और महिलाओं का बंटवारा कर अपने खिलाफ पड़ने वाले एकजुट वोटों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। तमाम राजनीतिक तरकीबों की मदद से भाजपा ने 2019 में हारी हुई आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर तो काबिज हो चुकी है, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में आजम खान बड़ी आसानी से अपने लोगों को समझा रहे हैं कि अगर वे भाजपा को वोट देते हैं तो अब्दुल को उनके घरों में पोछा लगाने से ज्यादा काम नहीं मिलने वाला है।

मुश्किल ये है कि न तो भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत अभियान ही मंजिल हासिल कर सका है, न ही वो अमित शाह के ड्रीम प्रोजेक्ट पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा के शासन के स्वर्णिमकाल में ही पहुंच सकी है और ऐन इसी बीच राहुल गांधी घात लगाकर धावा बोलने लगे हैं।

राहुल गांधी ने कोई नॉवेल आइडिया तो नहीं अपनाया है, लेकिन संघ और भाजपा की जय श्रीराम के

सिर्फ नारेबाजी होगी या आगे भी कोई इरादा है

राहुल गांधी की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी जय सियाराम के नारे लगा चुके हैं। लेकिन अहम बात ये है कि राहुल गांधी सिर्फ नारा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि संघ और भाजपा को उसी नारे में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक संघ या भाजपा की तरफ से ऐसा कोई जवाब नहीं आया है जिससे ये मुद्दा खत्म हो जाए। अगस्त, 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमिपूजन करने पहुंचे तो संबोधन की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जय के साथ ही की थी। मोदी के मुंह से ये स्लोगन सुनकर लोगों को लगा जैसे भाजपा सबका साथ, सबका विकास के स्लोगन में सबका विश्वास जोड़ने की कोशिश कर रही है। अपने भाषण की नरेंद्र मोदी ने शुरुआत कुछ ऐसे की, सबसे पहले हम भगवान राम और माता जानकी को स्मरण करें... सियावर रामचंद्र की जय... जय सियाराम! पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान मार्च, 2021 में ममता बनर्जी जय श्रीराम के नारे विरोध पर भाजपा की आपत्ति के बारे में लोगों को समझा रही थीं, बोलीं- 'वो कह रहे हैं कि आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे... आपको जय श्रीराम कहना होगा, लेकिन आप जय सियाराम नहीं कह पाएंगे।' ये मुद्दा नए सिरे से छेड़कर कांग्रेस नेता ने संघ और भाजपा की मुश्किल तो बढ़ाने की कोशिश की ही है और ऐसा करके राहुल गांधी एक ही प्रयास में हिंदुत्व में अपनी हिस्सेदारी भी जताने की कोशिश कर रहे हैं, और महिलाओं का मुद्दा भी उठा रहे हैं। भाजपा के लिए सीधे-सीधे बचाव करना मुश्किल हो सकता है।

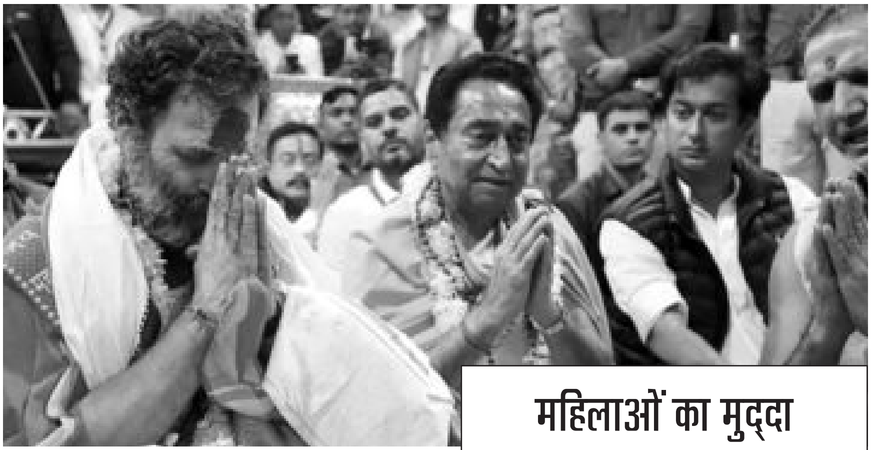

नारे की जगह जय सियाराम बोलने की चुनौती दे रहे हैं, वो नक्कारखाने की तूती तो नहीं ही साबित होने वाला है। समझने वाली बात ये है कि ऐसा करके वो संघ और भाजपा के साथ-साथ हिंदुत्व की राजनीतिक राह पर बढ़ रहे अरविंद केजरीवाल को भी पछाड़ने की जुगत लगा चुके हैं। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ठीक उसी जगह चोट किया है, जहां वो कमजोर पड़ता है, संघ में महिलाओं की गैरमौजूदगी। राहुल गांधी ने ये मुद्दा 2017 में हो रहे गुजरात विधानसभा के दौरान भी उठाया था, लेकिन संघ की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं दिया जा सका। स्थिति अब भी कुछ बदली हो, ऐसा भी नहीं लगता। जैसे राहुल गांधी कांग्रेस न बनने की अपनी जिद पर कायम रहे, अगर जय सियाराम भी यूं ही बोलते रहे तो कांग्रेस का भी कल्याण हो सकता है। महिलाओं के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने पूछा था, आरएसएस की शाखा में आपने एक भी महिला को शार्ट्स पहने देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। आखिर आरएसएस में महिलाओं को आने की अनुमति क्यों नहीं है? फिर राहुल गांधी ने ये भी ध्यान दिलाया कि भाजपा में कई महिलाएं हैं, लेकिन आरएसएस में मैंने किसी महिला को नहीं देखा है। तभी संघ के सीनियर नेता मनमोहन वैद्य की तरफ से राहुल गांधी को समझाने की कोशिश हुई, ये ऐसा ही है कि कोई पुरुष हॉकी के मैच में पहुंच जाए और वहां महिला हॉकी खिलाड़ियों की तलाश करे! मनमोहन वैद्य का कहना रहा कि संघ शाखाओं पर पुरुषों के साथ काम करता है और उनके जरिए परिवारों से भी जुड़ता है। ऐसे सवाल उठने पर संघ की तरफ से आरएसएस के महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति का उदाहरण दिया जाता है, लेकिन संघ की तरह उसकी सक्रियता कभी नहीं देखी गई।

समय-समय पर कभी महिलाओं की रूटीन तो कभी किसी और बहाने से संघ की तरफ से इस सवाल को काउंटर करने की कोशिश होती रही है और राहुल गांधी ने फिर से संघ की उसी कमजोर नस पर प्रहार किया है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत मप्र पहुंचे राहुल गांधी ने किसी पंडित जी से मुलाकात और उनकी बातों का जिक्र करते हुए कहा, उनके संगठन में सीता नहीं आ सकतीं... उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया... ये बहुत गहरी बात मप्र के एक पंडित जी ने सड़क पर मुझसे कही। राहुल गांधी बोले, पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि भाजपा के लोग जय श्रीराम करते हैं मगर कभी जय सियाराम या हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा... बहुत गहरी बात बोली... आरएसएस और भाजपा के लोग जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते... राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया... भगवान राम की जो भावना थी, जो उनके जीने का तरीका है, आरएसएस के लोग और भाजपा के लोग नहीं अपनाते। और फिर उसी क्रम में राहुल गांधी ने संघ और भाजपा को सलाह दी, हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं... मैं उनसे कहना चाहता हूं... जय श्रीराम, जय सियाराम और हे राम... तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए।

राहुल गांधी कहते हैं, हम सीता को याद करते हैं... समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसका आदर करते हैं... जय सियाराम, जय सीताराम और जय श्रीराम... हम राम भगवान की जय करते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है जिसमें वो कहते हैं, जय सियाराम तो वे कह ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है... वह जय सियाराम का संगठन ही नहीं है, उनके संगठन में महिला तो आ ही नहीं सकती... सीता तो आ ही नहीं सकती... सीता को तो बाहर कर दिया। राहुल गांधी के बयान पर भाजपा की तरफ से जोरदार विरोध हुआ है, लेकिन किसी ने भी कांग्रेस नेता के सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं की है। वैसे भी जब जवाब न हो तो सवाल पूछने वाले पर सवाल उठाकर काम तो चलाया ही जा सकता है और अगर समर्थकों की तादाद अच्छी हो तो काम और भी आसान हो जाता है।

भाजपा प्रवक्ता सैय्यद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा ही कमजोर बचाव किया है, भाजपा को राहुल गांधी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ऊपर से राहुल गांधी को नकली हिंदू के तंज के साथ इस बार इलेक्शन हिंदू करार दिया है। मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है, राहुल बाबा का ज्ञान, बाबा ब्लैक शीप तक ही सीमित है। उप्र के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक राहुल गांधी को नाटक मंडली का नेता बता रहे हैं। कहते हैं, वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं। उप्र के ही एक और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य तो अपनी ही जीत बताने लगते हैं, भाजपा ने जय सियाराम बोलने के लिए विवश कर दिया है... ये भाजपा की वैचारिक विजय और कांग्रेसी विचारधारा की हार है! केशव मौर्य आगे कहते हैं, अभी आपसे जय श्री राधारानी सरकार की और जय श्रीकृष्ण भी कहलवाना है!

● विपिन कंधारी

महिलाओं का मुद्दा

महिलाओं का मुद्दा अलग-अलग तरीके से उठाता रहा है और सबसे ज्यादा ये मुद्दा चर्चित रहा जब उप्र में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। उप्र चुनाव 2022 में महिला उम्मीदवारों को 40 फीसदी आरक्षण देने की प्रियंका गांधी ने घोषणा की थी, तब राहुल गांधी की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया रही- अभी तो ये शुरुआत है। हालांकि, उसके बाद ये मुद्दा ठंडा पड़ता भी लगा, लेकिन कोई बात नहीं जब जगे तभी सवेरा मान लेंगे। बतौर कांग्रेस राहुल गांधी और उनसे पहले सोनिया गांधी भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बारी-बारी पत्र लिख चुके हैं। दोनों ही पत्रों में भाजपा सरकार को एक जैसी ही सलाह दी गई थी, आप महिला आरक्षण बिल लाइए और हम सपोर्ट करेंगे। दोनों नेताओं ने ये भी याद दिलाया था कि कैसे यूपीए सरकार में कांग्रेस ने कोशिश की, लेकिन गठबंधन की सरकार होने की वहज से अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। सोनिया गांधी ने लिखा था, आपके पास तो बहुमत है... आप कर सकते हैं। दोनों ही पत्रों पर मोदी सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन या ऐसी प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जैसी अपेक्षित रही होगी। बल्कि भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व को ये समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस पहले मोदी सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसे सपोर्ट करना चाहिए। 2019 में कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण की शुरुआत की थी, बहनों और भाइयों। आमतौर पर नेता बहनों और भाइयों कह कर संबोधित करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी ऐसा किया करती थीं और आपको याद होगा, स्वामी विवेकानंद ने 1893 के शिकागो सम्मेलन में अपने संबोधन की शुरुआत भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स... कहकर ही की थी।

> 2023 के विदा होने के पहले ही अगले आम चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। कुछ दलों ने तो इन चुनावों की तैयारी शुरू भी कर दी है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है उसका उद्देश्य 2024 के चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है।

चुनाव प्रधान देश बनता भारत

गत दिवस जिस समय गुजरात, हिमाचल और दिल्ली नगर निगम चुनावों के एक्टिजट पोल की प्रतीक्षा हो रही थी, उसी समय उप्र में नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण सूची जारी हो रही थी। यह सूची जारी होते ही निकाय चुनावों की तैयारी तेज हो गई। उप्र में कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 545 नगर पंचायतें हैं। इसका मतलब है कि चंद दिनों बाद उप्र में गली-गली में चुनावी माहौल दिखेगा। यह इस वर्ष दूसरी बार होगा। इसके पहले ऐसा माहौल विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला था, जो फरवरी-मार्च में हुए थे। उप्र के साथ पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के भी विधानसभा चुनाव हुए थे।

इसके पिछले वर्ष यानी 2021 में पांच राज्यों- केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और पुदुचेरी विधानसभा के चुनाव हुए थे। हिमाचल और गुजरात विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों की निगाह अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों पर लग जाएंगी। इसलिए कुछ ज्यादा ही लग जाएंगी, क्योंकि अगले वर्ष कर्नाटक, राजस्थान, मप्र समेत 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। चूंकि इन सभी राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं होंगे, इसलिए अगले वर्ष रह-रहकर चुनाव होते हुए देखने को मिलेंगे। एक तरह से वर्ष 2023 चुनावमय बना रहेगा।

2023 के विदा होने के पहले ही अगले आम चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। कुछ दलों ने तो इन चुनावों की तैयारी शुरू भी कर दी है। कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसका उद्देश्य भले ही देश को जोड़ना बताया जा रहा हो, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य 2024 के आम चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। स्पष्ट है कि देश को लगातार होने वाले चुनावों से कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। हर वर्ष किसी न किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते ही रहते हैं। विधानसभा चुनावों के अतिरिक्त निकायों और पंचायतों के चुनाव भी होते हैं। राजनीतिक दल तो विधानसभा और लोकसभा चुनावों के साथ निकाय एवं पंचायत चुनावों में अपना समय खपाते ही हैं, प्रशासनिक मशीनरी भी अपना सारा जोर इन चुनावों को संपन्न कराने में लगाती है। इससे जनहित के कई काम रुक जाते हैं, क्योंकि आचार संहिता प्रभावी हो जाती है।

राजनीतिक दल और प्रशासनिक मशीनरी एक तरह से 5 साल में 4 बार चुनावों का सामना करती है। किसी विधायक-सांसद के निधन, उसके अयोग्य पाए जाने, पाला बदलने या इस्तीफा दे देने के कारण होने वाले उपचुनावों से बचा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ अवश्य किया जा सकता है, जिससे देश को बार-बार चुनावों का सामना न करना पड़े। रह-रहकर होने वाले चुनावों से केवल इसलिए नहीं बचा जाना चाहिए कि उनमें अच्छा-खासा धन खर्च होता है, बल्कि इसलिए भी बचा जाना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का सारा ध्यान चुनावों पर केंद्रित हो जाता है। वैसे चुनावों में खर्च होने वाला धन इतना

घर से नहीं निकले मतदाता

दरअसल राजनीतिक दल कभी प्रत्याशियों के चयन में जनता की राय जानने की ईमानदार कोशिश करते ही नहीं। तब जातिवाद, धनबल, बाहुबल और भाई भतीजावाद की बिना पर टिकट मिले उम्मीदवारों में जनता रूचि क्यों ले? खास गुजरात चुनाव की ही बात करें तो भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों ही दलों ने अथक प्रयास किए हैं कि मतदाता घरों से बाहर निकलें, परंतु वे आशानुरूप नहीं निकले। सीधी सी बात है यदि वोटर लिस्ट परफेक्ट है यानी जेन्युइन है और सभी वोटर जीवित हैं तो मतदान कम से कम 80 फीसदी तो होना ही चाहिए। 20 फीसदी की छूट इस बिना पर मान लें कि कोई बीमार है या बाहर से आ नहीं पाया या दीगर वाजिब वजह। हालांकि तमाम वाजिब वजहों के लिए भी यथासंभव इंतजाम किए जाते हैं चुनाव आयोग द्वारा पोस्टल बैलट के माध्यम से। फिर भी मतदान का प्रतिशत 60 के आसपास रुक जाए और उसमें नोटा के मत भी शामिल हैं, तो जो चुना जाएगा उसे प्रतिनिधि कैसे मान लिया जाए? साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 31 फीसदी मतों के साथ 282 लोकसभा सीटें मिल गई थीं तब दिल है कि मानता नहीं प्रधानमंत्री मोदी के पास जनादेश है भले ही वे बार-बार दावा करते रहें! आखिर जनसमर्थन तो एक तिहाई ही हुआ ना।

कम भी नहीं है कि उसकी अनदेखी कर दी जाए। वर्ष दर वर्ष चुनावों पर होने वाला खर्च बढ़ता जा रहा है। एक अनुमान के अनुसार पिछले लोकसभा चुनावों में करीब 60 हजार करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2014 के लोकसभा चुनावों का खर्च 30 हजार करोड़ रुपए था। यह सरकारी खर्च है। उस खर्च का हिसाब लगाना कठिन है, जो राजनीतिक दल चोरी-छिपे करते हैं।

जब चुनाव आते हैं तो राजनीतिक दलों के साथ शासन-प्रशासन की भी प्राथमिकता बदल जाती है। जिन राज्यों में सत्ता बदलने के आसार होते हैं, वहां तो प्रशासन पंगु सा पड़ जाता है। यह सही है कि चुनाव लोकतंत्र के लिए एक उत्सव की तरह होते हैं, लेकिन जब कोई उत्सव बार-बार मनाया जाने लगे तो वह एक बोझ की तरह लगने लगता है। किसी भी चीज की अति भली नहीं होती, वे चाहे उत्सव हो या चुनाव अथवा अन्य कोई आयोजन। एक समय था, जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ-साथ हुआ करते थे। 1952 से लेकर 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए। यह सिलसला तब टूटा जब राजनीतिक कारणों से 1968-69 में कई राज्यों की विधासभाएं भंग कर दी गईं और 1971 के आम चुनाव समय से पहले करा दिए गए।

हालांकि समय-समय पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की चर्चा होती रही है, लेकिन वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। यह तब है, जब विधि आयोग एक साथ चुनाव की पैरवी कर चुका है। एक साथ चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों और खासकर क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि यदि विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव होंगे तो उनमें उभरे राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पर भारी पड़ेंगे और इससे उन्हें नुकसान होगा।

यह आपत्ति कितनी सही है, कहना कठिन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव संग ओडिशा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। इन विधानसभा चुनावों में बीजू जनता दल जीत हासिल करता चला आ रहा है। वह एक क्षेत्रीय दल है। उसकी ओर से यह सुनने को नहीं मिला कि एक साथ चुनाव होने से उसे घाटा होता है। यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों को नुकसान होगा तो इसका भी उपाय है और वह यह कि आम चुनाव के दो-तीन साल बाद सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। यदि राजनीतिक दल चाहें तो इस पर आम सहमति हो सकती है और भारत चुनाव प्रधान देश होने से बच सकता है। ऐसा होने से संसाधनों की बचत तो होगी ही, हमारे नीति-नियंताओं के पास देश की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिक समय भी होगा।

गिरता मतदान प्रतिशत लोकतंत्र के प्रति उदासीनता है या फिर लोग निश्चिंत हैं? गुजरात के हालिया प्रथम चरण के मतदान के आंकड़ों ने एक बार फिर इस सवाल को जन्म दिया है। देखा जाए तो ऐसा चुनाव दर चुनाव हो रहा है। जबकि चुनाव आयोग और सरकार की पिछले कई वर्षों से ये लगातार कोशिशें जारी हैं कि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जाए। फिर सभी राजनीतिक पार्टियां, सत्तापक्ष हो या विपक्ष, भी लोगों से मतदान करने की पुरजोर अपील करती हैं। लेकिन दुख व चिंता का विषय है कि तमाम कोशिशों व प्रचार के बाद भी वोट प्रतिशत बढ़ने की बजाय घट रहा है। असल में लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक मतदाता का लोकतंत्र में भागीदारी करना बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है और वोट प्रतिशत में बढ़ोत्तरी किसी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की निशानी है। सवाल है भारत में जहां चुनावों को लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है वहां मतदान में रूचि कम क्यों होने लगी है? गुजरात में प्रथम चरण के लिए 63.14 फीसदी मतदान हुआ जो 2017 में 68 फीसदी था यानी इस बार करीब 5 फीसदी कम रहा। कुल मिलाकर व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं तो चुनावों में हर बार होता है कि कहीं मतदान का प्रतिशत उम्मीद से ज्यादा होता है तो कहीं इतना कम कि 20 फीसदी वोट हासिल करने वाले भी विधायिकाओं तक पहुंच जाते हैं।

हालांकि आश्चर्य तब होता है जब इन्हीं कम मतदान की खबरों के बीच केरल और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों में 85 फीसदी से ज्यादा वोटिंग होती है। फिर एक खास राज्य में भी कहीं ज्यादा मतदान होता है तो कहीं कम। गुजरात भी अपवाद नहीं रहा है, दक्षिण गुजरात के मतदाताओं का मतदान में सौराष्ट्र के मुकाबले उत्साह ज्यादा रहा। ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह मतदाताओं की बेरूखी रही हो। प्रथम चरण के चुनाव में ही तापी जिले में 78 फीसदी मतदान दर्ज हुआ। सवाल है ऐसा क्यों होता है? उत्तर है राजनीतिक दल चाहें तो लोगों को वोट डालने के लिए घरों से बाहर ला सकते हैं। इसका मतलब अवांक्षित प्रभाव सरीखी कोई बात नहीं है और ना ही किसी एक दल के कारण ऐसा हो सकता है। ये तो सभी दलों के सामूहिक प्रयासों से संभव है मसलन अपने-अपने उम्मीदवारों का निरपेक्ष चयन, आसमान से तारे तोड़ने जैसी बातों से परहेज, आदर्श आचार संहिता का आदर्श पालन आदि।

● इन्द्र कुमार

जैसा राजा तैसी प्रजा

पुरानी कहावत थी जैसा राजा तैसी प्रजा। लेकिन आज के जमाने में जैसी प्रजा तैसा राजा होता है। इसलिए राजा या नेता चुनने वाले ही यदि उदासीन हैं तब सत्ता कैसी होगी ये आसानी से समझा जा सकता है। विगत 75 सालों में हमारे देश के सामाजिक जीवन पर राजनीति की छाया इतनी व्यापक और घनी हो चुकी है कि गांव में बैठे अनपढ़ से लेकर अभिजात्यवर्गीय क्लब और अन्य उच्चवर्गीय जमावड़ों में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर अधिकांश समय राजनीति ही चर्चा का विषय रहती है। नागरिकों को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सहभागिता के बिना न तो उनका भला होगा और न ही लोकतंत्र का भला होगा। नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता को बढ़ाना होगा। असल में जब लोकतंत्र में नागरिकों की सहभागिता बढ़ेगी तभी एक स्वस्थ, सुंदर एवं सुदृढ़ लोकतंत्र की स्थापना कर सकेंगे। या फिर सरकार चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्ति दें कि वह किसी भी चुनाव के लिए मतदान की अनिवार्यता हेतु नियम कानून बनाएं और तंत्र पालन सुनिश्चित कराएं।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में ठनी

एक अखंडित व संप्रभु देश में दो राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर तलवारें खिंची नजर आएं तो यह आश्चर्य और चिंता, दोनों का विषय है। लेकिन, हमारे देश में यह कोई नई बात नहीं है। असम-मेघालय, असम-मिजोरम, असम-नागालैंड, असम-अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच सीमा विवाद लंबे समय से अस्तित्व में है। इसी हफ्ते, असम और मेघालय की सीमा पर भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत और अब महाराष्ट्र-कर्नाटक के बीच तनाव की खबरों ने इस मसले को फिर से चर्चा में ला दिया है।

इन दिनों महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों के बीच सीमावर्ती इलाकों पर अधिकार को लेकर ठनी हुई है। दोनों राज्य ही एक-दूसरे के क्षेत्र में आने वाले गांव-शहरों को लेकर दावों-प्रतिदावों में उलझे हुए हैं। हालांकि यह विवाद कोई नया नहीं है। पिछले करीब पचास सालों से अक्सर यह विषय दोनों राज्यों के बीच तनाव का कारण बनता रहा है। लेकिन इस बार, यह इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वर्तमान में दोनों राज्यों में एक ही दल, भाजपा की सरकार है। इस नाते, उनसे यही अपेक्षा की जा रही थी कि वे आपसी बातचीत के जरिए, इसका कोई रचनात्मक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। बजाय इसके, दोनों राज्यों के नेताओं ने इसे निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है।

मौजूदा फसाद की शुरूआत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के इस दावे से हुई कि महाराष्ट्र के सांगली जिले के जत तालुका के 40 कन्नड़भाषी गांव, कर्नाटक में शामिल होना चाहते हैं। जवाब में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए हुंकार भरी कि वे राज्य का एक भी गांव कर्नाटक में नहीं जाने देंगे। इसी के साथ, उन्होंने कर्नाटक राज्य की उत्तरी सीमा के भीतर मौजूद मराठीभाषी क्षेत्रों, बेलगांव, कारवार और निपाणी को वापस लेने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की भी बात कही।

दोनों राज्यों के बीच चल रहा यह विवाद साल 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के समय से ही अस्तित्व में है। उस दौरान महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने मराठी भाषी बेलगावी सिटी, खानापुर, निप्पानी, नांदगाड और कारवार को महाराष्ट्र में शामिल किए जाने की मांग की थी। इस मांग पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश मेहर चंद महाजन की अध्यक्षता में एक आयोग के गठन का फैसला लिया था। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री के इस पर सहमत हो जाने के बाद, राज्य में विवाद शुरू हो गया। जब आयोग की रिपोर्ट आई तो उसमें महाराष्ट्र के कुछ इलाके कर्नाटक को और कर्नाटक के कुछ इलाके महाराष्ट्र को सौंपने की बात कही गई थी। लेकिन, इससे दोनों ही राज्य सहमत नहीं थे और मसला हल नहीं हो सका। मराठीभाषी **कन्नड़ इलाकों** को महाराष्ट्र में मिलाने की मांग को लेकर कुछ नेताओं ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति गठित की, लेकिन वह बेअसर साबित हुई। वर्ष 2006 में यह विवाद फिर से सुर्खियों में आया, जब महाराष्ट्र सरकार ने बेलगाम पर दावा जताते हुए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में दलील दी गई कि कर्नाटक में रहने वाले मराठी भाषी लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है।

जिस समय भारत को ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली, उस समय देश में 563 रियासतें थीं। इनका एकीकरण और पुनर्गठन, नई सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। विचार बना कि नए राज्यों के निर्माण के लिए भाषा को आधार बनाया जाए। इसके लिए 1947 में श्याम कृष्ण आयोग बनाया गया, लेकिन वह इस विचार के पक्ष में नहीं था। पर सरकार को लगता था कि जनता की यही इच्छा है। इसी साल एक नया जेवीपी (जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, पट्टाभिसीतारमैया) आयोग गठित हुआ, जिसने भाषाई आधार पर पुनर्गठन का समर्थन किया। दिसंबर 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और केएम पाणिक्कर की सदस्यता वाला राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। उन्होंने एक ही सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवहार्यता, आर्थिक विकास, **अल्पसंख्यक हितों** की रक्षा तथा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी। कुछ संशोधनों के साथ इन सिफारिशों को सरकार ने अनुमति दे दी और 1956 में संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास कर दिया गया। इसके अंतर्गत, देश में 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसके बाद कई बार राज्यों का पुनर्गठन किया गया और नए-नए राज्य बनते गए। ज्यादातर मामलों में भाषा ही इनके गठन का मुख्य आधार रही।

● बिन्दु माथुर

अस्तित्व में, लेकिन सुस्त अंतर-राज्यीय परिषद

शायद ही ज्यादा लोगों को पता हो कि देश में भाषाई, सीमाओं संबंधी और नदियों के जल के बंटवारे, सुरक्षा की दृष्टि से सैन्य बलों की तैनाती, वित्तीय मामले जैसे मुद्दों को लेकर विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक अंतर-राज्यीय परिषद भी है। सरकारिया आयोग की सिफारिशों और स्वयं राष्ट्रपति के आदेश से, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत यह संस्था 28 मई 1990 को गठित की गई। 32 सालों से यह एक संवैधानिक निकाय के रूप में अस्तित्व में है, जिसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। संस्था के सदस्यों में देश के गृहमंत्री सहित, प्रधानमंत्री द्वारा नामांकित छह केंद्रीय मंत्री, सभी राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल होते हैं। लेकिन, हैरानी की बात यह है कि पिछले तीन दशकों में अंतर-राज्यीय परिषद की सिर्फ 12 मीटिंग ही हुई हैं। इनमें भी आखिरी, पांच साल पहले 25 नवंबर 2017 को हुई थी। चाहे असम-मेघालय हो या महाराष्ट्र-कर्नाटक, देखने में आ रहा है कि विवादों को हवा देकर राजनीतिक फायदा उठाने के प्रयास जोर पकड़ रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इस परिषद को अधिक मजबूत, चुस्त और सक्रिय किया जाए, ताकि यह भविष्य में भयावह रूप ले सकने वाली अंतर-राज्यीय समस्याओं को समय रहते सुलझाने में अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके।

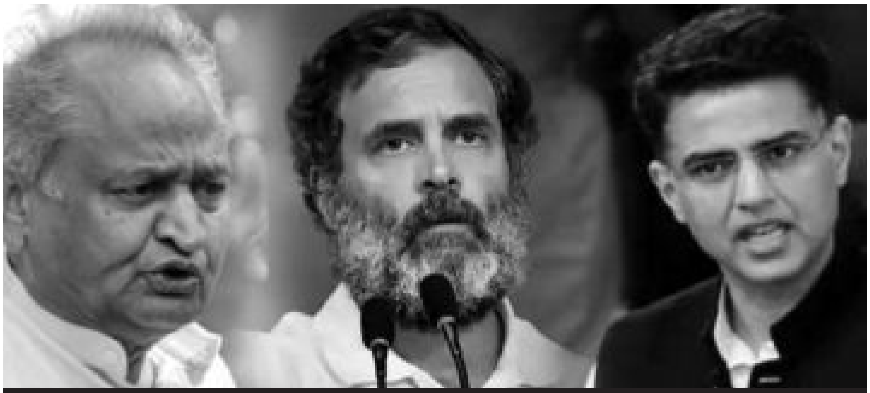

गहलोत-पायलट का सीजफायर

कहते हैं रेगिस्तान में रेत गर्मियों में गर्म भी जल्दी होती है और सर्दियों में ठंडी भी जल्दी होती है। राजस्थान में पारा इतना गिर गया है कि माऊंट आबू में बर्फ जमने लगी है, लेकिन जैसे-जैसे पारा गिर रहा है, वैसे-वैसे राजस्थान की राजनीति का पारा चढ़ रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले ही अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कांग्रेस से गद्दारी का बम फोड़ दिया था। इस बम धमाके ने दस जनपथ की चूलें हिला दी थीं। क्योंकि अशोक गहलोत के खंडन के बावजूद अभी भी यही माना जाता है कि गांधी परिवार ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनवाना चाहता है। इस धमाकेदार बयान के बाद राहुल गांधी ने गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी के लिए एसेट्स कहकर सीजफायर करवाने की कोशिश की थी, लेकिन अशोक गहलोत ने राहुल गांधी के कहे का अपनी मर्जी से अर्थ निकालकर उनकी सीजफायर की कोशिश को भी नाकाम कर दिया।

आखिर कांग्रेस के संगठन महासचिव वेणुगोपाल को जयपुर जाकर राहुल की यात्रा निकल जाने तक दोनों में सीजफायर करवाना पड़ा। वेणुगोपाल ने **हाथ-पैर जोड़कर** अशोक गहलोत को मनाया है। वेणुगोपाल अशोक गहलोत से बड़े नेता नहीं हैं। जिस पद पर वेणुगोपाल अब हैं, उस पद पर अशोक गहलोत पांच साल रह चुके हैं। यह भी खबर आई कि गहलोत ने वेणुगोपाल से सख्त लहजे में बात की। इसलिए यह सीजफायर स्थाई युद्ध विराम नहीं है। वेणुगोपाल के दिल्ली लौटने से पहले ही सचिन पायलट समर्थक मीडिया ने यह कहकर अशोक गहलोत को फिर भड़का दिया कि राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान हो जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत यह किसी हालत में नहीं होने देंगे। अव्वल तो आलाकमान अशोक गहलोत को हटाने के बार में अब सोचेगा ही नहीं। अगर सचिन पायलट के दबाव में हाईकमान ने अशोक गहलोत को हाथ-पैर जोड़कर राजी कर भी लिया, तो भी सचिन पायलट तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।

वैसे अगर तुलना की जाए, तो अशोक गहलोत बड़े एसेट हैं और सचिन पायलट छोटे एसेट हैं। कांग्रेस यह भी अच्छी तरह जानती है। कांग्रेस के पास अब अध्यक्ष का पद भी नहीं बचा कि वह उन्हें दिल्ली लाकर अध्यक्ष पद पर बिठा दें। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर वेणुगोपाल की कुर्सी पर बैठना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस में अगर थोड़ी भी बुद्धि होगी, तो अशोक गहलोत को डिस्टर्ब नहीं करेगी।

विधानसभा चुनावों में अब सिर्फ 10 महीने बाकी बचे हैं। 10 महीने पहले तो चुनावी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। भाजपा ने 10 महीने पहले ही जन आक्रोश यात्रा शुरू कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने 4 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश किया है, जेपी नड्डा ने पहली दिसंबर को ही जयपुर से जन आक्रोश यात्रा को रवाना कर दिया, जो सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। जबकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तो 15 दिन में 7 जिलों के सिर्फ 18 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी।

अब राहुल की इस यात्रा को सचिन पायलट की गुर्जर सेना ने काले झंडे दिखा दिए, तो सीजफायर राहुल गांधी की मौजूदगी में टूट जाएगा और कांग्रेस में गृहयुद्ध शुरू हो जाएगा। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि राजस्थान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का सबसे मुश्किल क्षेत्र है। इस बीच राहुल गांधी की पदयात्रा राजस्थान पहुंचने से ठीक पहले कांग्रेस के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। यह संकट विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने खड़ा किया है, जिन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई है कि विधानसभा अध्यक्ष को उन 80 विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने के निर्देश दिए जाएं, जिन्होंने 25 सितंबर को इस्तीफे दिए थे। राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि विधानसभा अध्यक्ष सरकार को बचाने में लगे हैं, इसलिए इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। नियम यह है कि अगर कोई विधायक खुद विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश होकर इस्तीफा देता है, तो अध्यक्ष के पास उसे मंजूर करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। इन 80 विधायकों ने 25 सितंबर को न सिर्फ खुद अध्यक्ष के सरकारी आवास पर जाकर व्यक्तिगत तौर पर इस्तीफे सौंपे थे, बल्कि उनके घर पर भोज भी किया था।

राठौड़ ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि वह विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दें कि वह इस्तीफे स्वीकार करें। वैसे इस तरह की याचिकाओं पर कोर्ट जल्दी फैसला नहीं करती। महाराष्ट्र के 16 विधायकों की बर्खास्तगी पर फैसला पिछले कई महीनों से सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट कब फैसला लेता है और क्या फैसला लेता है, यह आने वाले दिनों में साफ होगा। इतना तय है कि कांग्रेस सरकार के सामने यह नया संकट है, जिसका सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। वह भी ऐसे समय में जब 18 दिसंबर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में होगी।

● जयपुर से आर.के. बिन्नानी

गांधी परिवार तक पहुंचा मुख्यमंत्री पद का विवाद

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश से पहले गहलोत और पायलट गुट के बीच चल रही बयानबाजी की गर्मी को केसी वेणुगोपाल ने ठंडा करने में कामयाबी जरूर हासिल की। वेणुगोपाल ने दोनों नेताओं का हाथ उठा कर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की लेकिन जानकारी के मुताबिक, गहलोत और पायलट का झगड़ा सुलझा नहीं है। दोनों नेताओं के मतभेद अब भी रह गए हैं। सूत्रों के मुताबिक, सचिन पायलट कांग्रेस आलाकमान पर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए दबाव बना रहे हैं। बीते दिनों उन्हें महासचिव बनाने का ऑफर दिया गया, जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए। पायलट के करीबी नेताओं का दावा है कि उन्हें आखिरी के एक साल में मुख्यमंत्री बनाए जाने का वादा किया गया था। सूत्रों ने बताया है कि इस बीच सचिन ने एक-दो माध्यमों से गांधी परिवार तक यह संदेश पहुंचाया है कि अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो वो पार्टी छोड़ भी सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या पायलट भाजपा में शामिल होते हैं या क्या भाजपा उन्हें पार्टी में लेगी?

चीनी मिलों में करोड़ों का घोटाला!

उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शून्य भ्रष्टाचार योजना को पलीता कैसे लगाया जाता है और कायदे-कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, इसका यदि जीता-जागता कोई उदाहरण देखना हो, तो यह आपको उप्र सहकारी चीनी मिल संघ में देखने को मिल जाएगा। यहां भाजपा की सरकार के विगत 6 वर्षों के कार्यकाल में चाहे नियुक्तियों की जांच हो या फिर चाहे चीनी बिक्री घोटाला, चीनी निर्यात घोटाला हो, चाहे भ्रष्टाचार में लिप्त सेवानिवृत्त अधिकारियों को संविदा पर रखकर चीनी तथा शीरा विक्रय कराने का कार्य, चीनी मिलों के अपग्रेडेशन का घोटाला हो, चाहे शून्य तरल निर्वहन (जीरो लिक्विड डिस्चार्ज) के नाम पर भट्टियों (डिस्टिलरीज) में हुआ घोटाला हो, या फिर नई चीनी मिल परियोजना में हुआ घोटाला हो, आज तक किसी भी प्रकरण की सही जांच नहीं होने के कारण सारे घोटाले चीनी मिल संघ की फाइल में ही दबे हुए हैं। संघ के अधिकारी सरकार की जीरो भ्रष्टाचार **पॉलिसी की धज्जियां** उड़ाते हुए मलाई खाने और अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं।

दरअसल उप्र की सहकारी चीनी मिल संघ में केंद्रीय क्रय एवं आवंटन बजट में करोड़ों के घोटाले की खबरें आ रही हैं। प्रधान प्रबंधक क्रय तथा प्रधान प्रबंधक तकनीकी के पद एक ही अधिकारी के पास होने से करोड़ों के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। जाहिर है कि उप्र की सहकारी चीनी मिलों के मरम्मत तथा रखरखाव के तकनीकी बजट आवंटन में भी करोड़ों के वारे-न्यारे किए जा रहे हैं। बताते हैं कि अपर मुख्य सचिव गन्ना तथा प्रबंध निदेशक के चहेते अधिकारी प्रधान प्रबंधक तकनीकी एवं क्रय विनोद कुमार के पास कुल चार प्रमुख प्रधान प्रबंधक का प्रभार और सभी तकनीकी पांच विभागों का प्रभार में से तीन विनोद कुमार के अधीन हैं।

खबरों के मुताबिक, ताजा घोटाला केंद्रीय क्रय पद्धति के अंतर्गत तकरीबन सभी सहकारी चीनी मिलों की मरम्मत के लिए खरीदे जाने वाले सामानों की दर संविदा जारी करने में प्रकाश में आया है। इसमें विगत कई वर्षों से प्रधान प्रबंधक क्रय तथा प्रधान प्रबंधक तकनीकी के दोनों पदों पर जमे प्रधान प्रबंधक द्वारा पार्टियों से सांठ-गांठ करके कई इंजीनियरिंग सामानों की दरें तय करने में एक और जहां करोड़ों रुपए का नुकसान चीनी मिल संघ को पहुंचाया है। वहीं दूसरी ओर सप्लायर्स से करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर अपनी जेबें भरने का काम किया है। जानकारी के मुताबिक, विनोद कुमार की करोड़ों की संपत्ति मेरठ तथा गुरुग्राम सहित अन्य जगहों पर भी है। अगर प्रधान प्रबंधक क्रय तथा प्रधान प्रबंधक तकनीकी के भ्रष्टाचार तथा आय से अधिक संपत्ति की निष्पक्ष जांच सरकार करा ले, तो दूध-का-दूध और पानी-का-पानी हो जाएगा।

सूत्र बताते हैं कि प्रधान प्रबंधक क्रय तथा प्रधान प्रबंधक तकनीकी लगातार अपने भ्रष्ट कला कौशल के आधार पर सभी प्रबंध निदेशक के चहेते अधिकारी बने रहे हैं, जिसके कारण ही पिछली समाजवादी की अखिलेश सरकार में भी यह तत्कालीन प्रबंध निदेशक डॉ. बीके यादव के चहेते अधिकारी रहे तथा कई मलाईदार चीनी मिलों के प्रधान प्रबंधक भी रहे। बताते हैं कि सन् 2016 में सहारनपुर जिले की सहकारी चीनी मिल नानौता में प्रधान प्रबंधक रहते हुए इन्होंने तत्कालीन प्रबंध निदेशक के कहने पर मिल में लगभग 70 फर्जी भर्तियां भी की थीं। इनकी कोई भी जांच आज तक नहीं कराई गई, जबकि हैरानी की बात है कि डॉ. बीके यादव के कार्यकाल में सहकारी चीनी मिल संघ में हुई भर्तियों की जांच भी हुई, जिसमें भर्तियों को लखनऊ मंडल के आयुक्त ने फर्जी पाया तथा सरकार द्वारा अब यही जांच सीबीआई से कराई जा रही है। इन्होंने दोनों महत्वपूर्ण पद का प्रभार होने के कारण ई-टेंडर में इतनी सफाई से तकनीकी शर्तों में मनमाने तरीके से सप्लायर्स से सांठगांठ करके परिवर्तन किए, ताकि किसी अन्य अधिकारी को इसकी कोई जानकारी न हो पाए तथा टेंडर में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों के विपरीत कई इंजीनियरिंग सामानों में एल-1 के साथ-साथ एल-2, एल-3 की सभी पार्टियों को भी उनकी ही मूल्य सूची (प्राइस लिस्ट) पर विभिन्न छूटें (डिस्काउंट) दिखाकर दर संविदा जारी कर दी। इन आइटम में प्रमुख रूप से मिलों में भारी मात्रा में उपयोग होने वाले वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक आइटम, सेंट्रीफ्यूगल पम्प, मिलों में उपयोग होने वाली बियरिंग आदि है। इसका परिणाम यह हुआ कि मिलों द्वारा मनमाने तरीके से महंगा-महंगा सामान खरीदा गया, जिससे आवंटित बजट में वृद्धि हुई तथा मिलों को अनावश्यक घाटा उठाना पड़ा।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

नियमों को किया गया दरकिनार

प्रधान प्रबंधक क्रय तथा प्रधान प्रबंधक तकनीकी के पद पर बैठे अधिकारी ने पम्प की दर संविदा में सन् 2014 में निम्न गुणवत्ता के पम्प आपूर्ति करने वाली मेरठ जिले की फर्म अम्बा प्रसाद जैन को अम्बा मेक के पम्प को ई-टेंडर में भाग लेने पर रोक लगा दी थी तथा सभी चीनी मिलों को उच्च गुणवत्ता के पम्प खरीदने के निर्देश दिए गए थे। परंतु प्रधान प्रबंधक तकनीकी एवं क्रय ने सन् 2018 में दोनों पदों का प्रभार लेकर बड़ी सफाई से पुनः ई-टेंडर में अम्बा मेक के पम्प को शामिल कराकर अम्बा प्रसाद जैन की अपनी ही प्राइस लिस्ट पर छूट दिखाकर दर संविदा जारी करा दी। उसका प्रभाव यह हुआ कि सन् 2014 में संघ द्वारा जारी आदेश कि किर्लोस्कर कंपनी के उच्च गुणवत्ता के पम्पों के स्थान पर चीनी मिलों में पुनः निम्न गुणवत्ता के अम्बा मेक के पम्प पार्टी द्वारा संघ तथा मिलों के अधिकारियों को भारी कमीशन देकर आपूर्ति करा दिए। यदि सन् 2018 से 2022 तक की मिलों को आपूर्ति पम्पों की निष्पक्ष जांच हो, तो सारी स्थिति स्वयं ही साफ हो जाएगी।

भूमिहारों का दबदबा

बिहार में चुनाव भले 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण अभी से ही बनाने में जुट गई हैं। इस समीकरण को लेकर सभी पार्टियों ने सवर्ण वोटरों को साधने के लिए अपने दल में शीर्ष पद पर सवर्ण को सेट किया है। जेडीयू, आरजेडी, भाजपा या फिर कांग्रेस इन चारों पार्टियों के शीर्ष पद पर किसी न किसी रूप में सवर्ण समाज के नेता शीर्ष पर हैं। इन सभी का टारगेट ऑफ वोट ऊंची जाति के वोटर हैं। पिछड़ों की राजनीति को बढ़ावा देकर स्थापित हुई यह पार्टियां अब सवर्ण वोटरों को रिझाने में जुटी है। माना जाता है कि भले सवर्ण का वोट प्रतिशत कम हो लेकिन राजनीतिक शब्दों में सवर्णों को खाने का तड़का कहा जाता है। जिसके बिना राजनीति का स्वाद अधूरा रह जाता है। बिहार में लालू यादव का मुखर विरोध करने वाले भूमिहार लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के भी प्रिय हो गए हैं। भूमिहार-ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन की ओर से आयोजित परशुराम जयंती पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर भूमिहार समाज और यादव एकजुट हो जाएं तो कोई हमें सत्ता से दूर नहीं कर सकता। तेजस्वी के इस अपील के बाद से बिहार की राजनीति में भूमिहारों का **कद** बढ़ने लगा।

भूमिहारों को अपना वोटर समझने वाली भाजपा ने भी अपने रुख में परिवर्तन किया और उन्हें एक बार फिर से सम्मान देना शुरू कर दिया। तीन माह पूर्व भाजपा ने सदन में विजय कुमार सिन्हा को विधायक दल का नेता बनाया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भी भूमिहार जाति से आते हैं। कांग्रेस ने ब्राह्मण की जगह भूमिहार जाति से आने वाले अखिलेश प्रसाद सिंह को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी इसी जाति से आते हैं। लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने भी भूमिहार जाति से संबंध रखने वाले डॉ. अरुण कुमार को अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है।

करीब तीन दशक तक बिहार की राजनीति में हाशिये पर रहने वाले भूमिहार हाल के दिनों में बिहार की राजनीति में क्यों खास हो गए। इस सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री रामजतन सिन्हा कहते हैं कि बिहार में 90 के दशक में लालू प्रसाद ने सर्वणों के खिलाफ बिहार के दलित, पिछड़ा और **अति पिछड़ा** को एकजुट कर एक मजबूत फ्रंट बनाया, जो अब खंड-खंड में विभक्त हो गया। इसके बिखरने के बाद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को लगने लगा है कि बिहार में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने के लिए एकजुट सवर्णों को अपने पक्ष में करना होगा। इसके बाद से ही बिहार में सभी राजनीतिक दलों ने सवर्णों को अपने पक्ष में करने की कवायद शुरू कर दी है। चूंकि भूमिहारों ने सवर्णों में सबसे ज्यादा फ्रंट में रहकर लालू प्रसाद के भूरा बाल साफ करो अभियान का विरोध किया इसलिए सभी राजनीतिक दलों की ये पहली पसंद बन गए हैं।

भूमिहार ही क्यों?

कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में भूमिहारों ने जब भाजपा को अपना समर्थन दिया तो यहां से भाजपा हारी हुई बाजी जीत गई। वहीं बोचहां विधान उपचुनाव में भूमिहारों ने महागठबंधन को अपना समर्थन दिया तो यह सीट महागठबंधन ने जीत ली। यही कारण है कि प्रदेश की राजनीति में भूमिहारों का कद बढ़ा दिया है। आरजेडी ने भी बोचहां विधानसभा जीत के बाद इसे कैश करने का प्रयास किया था। एक नया नारा दिया था भूमाई (भूमिहार-मुस्लिम-यादव)। तेजस्वी यादव भूमिहारों को अपने पक्ष में करने के लिए उनकी सभा में जाने लगे तो भाजपा ने अपने परंपरागत वोट बैंक को बचाने की कवायद शुरू की और वो इसमें सफल भी रही। भाजपा को इसका कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में लाभ भी मिला।

राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार में चुनाव भले 2 साल के बाद होने हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपना समीकरण अभी से ही बनाने में जुट गई हैं। इस समीकरण को साधने के लिए अपने दल में शीर्ष पद पर सवर्ण को सेट करना शुरू कर दिया है। जेडीयू, आरजेडी, भाजपा या फिर कांग्रेस इन चारों पार्टियों के शीर्ष पद पर किसी न किसी रूप में सवर्ण समाज के नेता शीर्ष पर हैं। इन सभी राजनीतिक दलों का टारगेट ऊंची जाति के वोटर हैं। पिछड़ों की राजनीति को बढ़ावा देकर स्थापित हुई यह पार्टियां अब सवर्ण वोटरों को रिझाने में लग गई है।

बिहार विधानसभा के 243 में 21 सीटों पर भूमिहारों का कब्जा है। बात अगर सवर्णों की बात की जाए तो 243 सीटों वाली विधानसभा में 64 विधायक सवर्ण जाति से आते हैं। यह आकंडा तब है जब बिहार की कई प्रमुख राजनीतिक दल उनसे परहेज करती हैं। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉ. अरुण कुमार कहते हैं कि हम अपने बल पर यह अंक प्राप्त करते हैं। क्योंकि हमारे अपने गांव में दलित-महादलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा से आज भी काफी दोस्ताना संबंध है। सुख-दुख में हम एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि वे हमें पार्टी और दल से ऊपर उठकर हमारा साथ देते हैं। जमीन पर हमारा यह काम ही बिहार की राजनीति में हमें दूसरों से अलग एक नई पहचान देने का काम किया है। बिहार के राजनीतिक दल हमारे इस **सरोकार** को अपने वोटबैंक में बदलने के लिए हमें महत्व देने के लिए हमें पद और सम्मान देने का प्रयास कर रहे हैं।

बहरहाल किसी एक जाति की बात करें तो यादव जाति से सबसे ज्यादा 54 सदस्य विधानसभा पहुंचे हैं, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ी जाति से 46 सदस्य विधानसभा पहुंचे हैं। 39 दलित और महादलित जाति से हैं और सदन में मुस्लिम सदस्यों की संख्या 20 है। इससे साफ है कि अगर सवर्ण एकजुट होते हैं तो वो ही तय करेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। इसकी बानगी बिहार के कुढ़नी-बोचहां विधानसभा उपचुनाव में दिखी।

● **विनोद बक्सरी**

चीन पर अंकुश की दरकार

सं प्रभुता, पड़ोसी देशों की मदद और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दों पर भारत से अग्रणी देश कोई नहीं है। हमेशा देखा गया है कि भारत ने हर आपदा में पड़ोसी देशों की मदद की है। कोरोनाकाल में कई देशों को कोरोना-टीका और दूसरी दवाएं देने से लेकर नेपाल और श्रीलंका की बुरे समय में मदद करने से भारत पीछे नहीं हटा। लेकिन इससे इतर एक बात यह भी है कि भारत के पड़ोसी देश उससे हमेशा शत्रुता रखते रहे हैं। अकारण ही भारत से शत्रुता करने वाले देशों की अगर लिस्ट तैयार करें, तो भारत का चीन से बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं निकलेगा।

हालांकि पाकिस्तान भी भारत का बहुत बड़ा और बंटवारे के समय का ही शत्रु है, लेकिन शत्रुता की हदें पार करते हुए कई मामलों में चीन ने पाकिस्तान को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि चीन कभी नहीं चाहता कि भारत उससे कभी आगे निकल सके। दरअसल चीन जानता है कि अगर एशिया में कोई देश उसे हर क्षेत्र में चुनौती दे सकता है, तो वो इकलौता भारत है। बस यही बात चीन को अखरती है और वो कई दशक से भारत को दबाने की और तबाह करने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसके लिए न केवल चीन स्वयं दबंगई पर उतरा हुआ है, बल्कि उसने भारत के मित्र पड़ोसी देशों को भी साम, दाम, दंड और भेद की नीति से अपने पक्ष में किया हुआ है।

आज की तारीख में भारत से ही अलग होकर बने सभी देशों ने भारत को आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। चीन की मुख्य योजना है- पड़ोसी देशों की जमीन पर अवैध कब्जा करना। इसी पॉलिसी के तहत उसने न केवल भारत की बहुत सारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान, कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, उत्तर कोरिया, रूस, तजाकिस्तान और वियतनाम को भी नहीं बख्शा है। ताइवान पर भी उसने पिछले दिनों कब्ज़ा करने की रणनीति बना ली थी, लेकिन ताइवान की हिम्मत और अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते चीन ताइवान पर हमला नहीं कर सका। तिब्बत पर तो चीन 23 मई, 1951 से ही अवैध कब्जा किए बैठा है।

दरअसल चीन की सीमा से दुनिया के 14 देशों की सीमा लगती है और इन सभी देशों के साथ चीन का सीमा विवाद है। इसकी प्रमुख वजह है चीन की नीयत खराब होना। वास्तव में चीन को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनने का फोबिया है, जिसके लिए वह सबसे पहले अपने पड़ोसी देशों पर दबदबा बनाना चाहता है। जैसा कि पिछले समय में कई रिपोर्ट्स आई हैं कि चीन ने भारत की करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। फरवरी, 2022 को संसद में सरकार ने खुद स्वीकार किया कि चीन ने भारत की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। हालांकि अब तक के तमाम बयानों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह तक इस बात को नकारते आए हैं, लेकिन इसी साल फरवरी में एक सवाल के जवाब में विदेश राज्यमंत्री वी. मुरलीधरन ने लोकसभा में यह बात स्वीकार की कि चीन ने भारत के लद्दाख की करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने बताया कि चीन लद्दाख में पिछले करीब 6 दशक से कब्जा कर रहा है। भारत की जमीन पर चीन के अवैध कब्जे को लेकर अब तक प्रकाशित विभिन्न रिपोर्ट बताती हैं कि चीन का भारत की करीब 43,180 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। ऐसे में सरकार के हाथ पर हाथ धरे रहने को लेकर सवाल उठने ही चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से चीन भारत की ज़मीनें कब्जाता रहा, तो हिमालय की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, जिसे हड़पने के लिए चीन कई दशक से चालें चल रहा है। चीन ने भारत को कमजोर करने के लिए उसके सात पड़ोसी देशों की जमीनों पर न केवल काफी हद तक कब्जा किया है, बल्कि उन्हें किसी-न-किसी तरह से अपने पक्ष में किया है। इन सात देशों में तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हैं। इसके साथ ही चीन हिमालय पर कब्जे के लिए भारत की पांच उंगलियों पर पूरी तरह कब्जा करना चाहता है, जिन्हें फाइव फिंगर कहा जाता है। इन फाइव फिंगर में दो भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान हैं, जबकि तीन भारत के प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और सिक्किम हैं। चीन जानता है कि अगर ये पांचों उसके कब्जे में आ गए, तो उसे हिमालय पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकेगा। पिछले कुछ वर्षों से चीन ने इन फाइव फिंगर पर कब्जे के प्रयास तेज कर दिए हैं।

पिछले ही साल अप्रैल, 2021 में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख लोबसांग सांग्ये ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए चीन की इस चाल का खुलासा किया था। लोबसांग सांग्ये ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि तिब्बत तो बस एक जरिया है, चीन का असली मकसद हिमालय और हिमालयी क्षेत्र में फाइव फिंगर कहे जाने वाले हिस्सों पर कब्जा करना है, ताकि वह भारत को अपने पंजे में फंसा सके। विदित हो कि तिब्बत पर कब्जे के बाद से ही चीन की नजर भारत की ओर टिकी हुई है, जिसके लिए वह लगातार अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। ऐसे में भारत को अपनी सैन्य शक्ति को कमजोर नहीं करना चाहिए, जिसके कि आरोप भारत सरकार पर लगते रहे हैं। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्तियां निकालने से तो यह आशंका ही बढ़ गई है कि भारत सरकार अपनी सेनाओं को कमजोर कर रही है, जबकि चीन अपनी सेनाओं को लगातार ताकतवर बना रहा है। दोनों देशों के रक्षा बजट की तुलना ही नहीं है।

● राजेश बोरकर

तवांग पर चीन की बुरी नजर

जून 2020 के बाद से चीन ने फिर भारत की सीमा में आने की हिमाकत की। इस बार उसने पूर्वी सेक्टर स्थित अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दाखिल होने की कोशिशें की। भारतीय सैनिकों ने भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एक भी सैनिक भारत की धरती पर दाखिल नहीं हो सका है। तवांग, चीन की वह दुखती रग है जो उसे हमेशा तकलीफ देती हैं। 9 दिसंबर को चीनी सैनिक, भारतीय सेना से उलझ गए थे। तवांग के पास यांगत्से में यह घटना हुई है। यांगत्से, 17 हजार फीट की ऊंचाई पर तवांग का वह हिस्सा जिस पर सन् 1962 की जंग के बाद से ही चीन की बुरी नजर है। वह युद्ध के समय से ही तवांग के यांगत्से पर कब्जे के सपने देख रहा है। सेना के सूत्रों की मानें तो यांगत्से को पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी हमेशा से निशाना बनाने की फिराक में रहती थी। आखिर तवांग और यांगत्से में ऐसा क्या है जो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस पर कब्जे का सपना पाले हुए हैं।

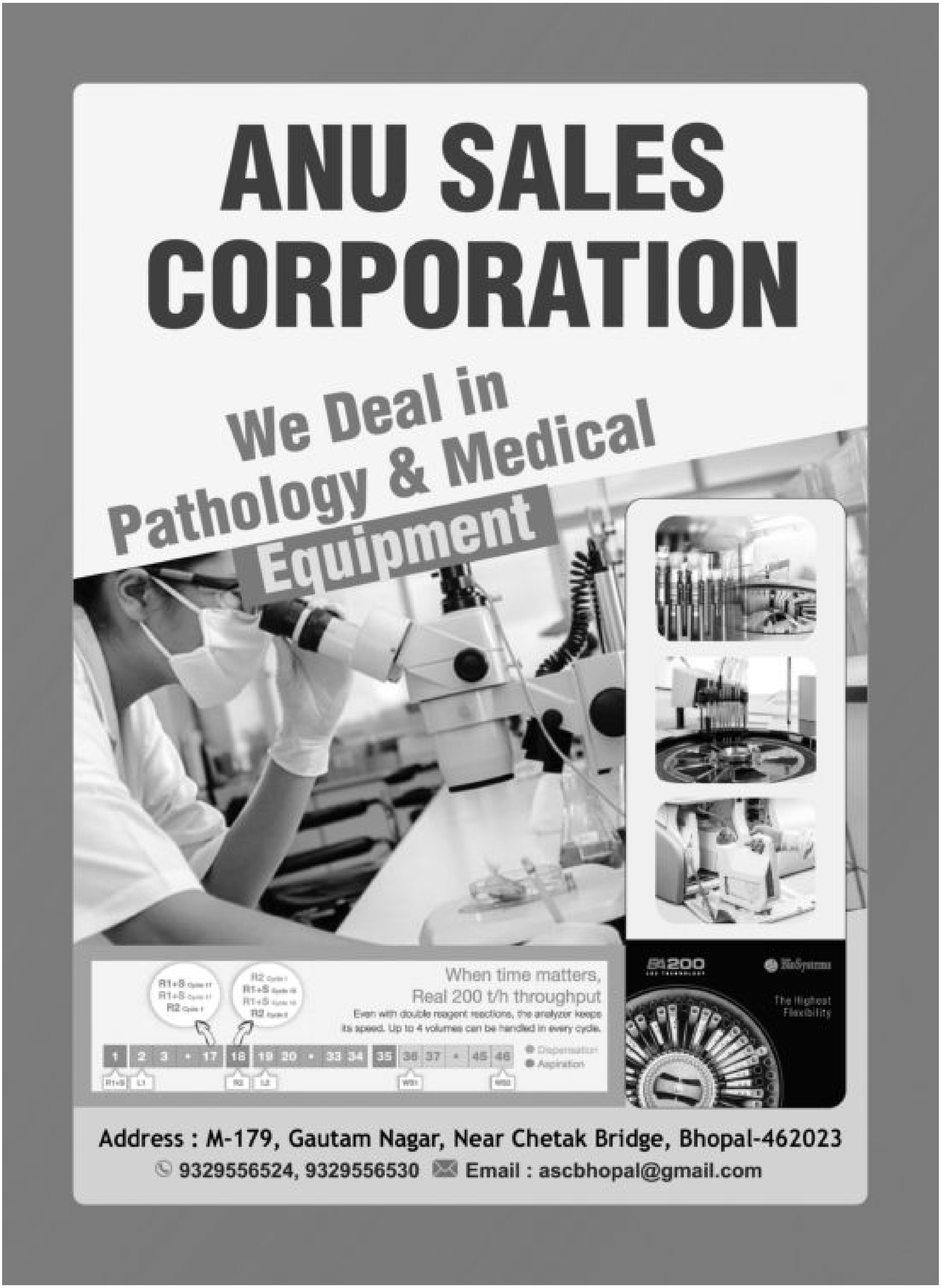

ANU SALES CORPORATION
We Deal in Pathology & Medical Equipment
When time matters,
Real 200 t/h throughput
Even with double reagent reactions, the analyzer keeps its speed. Up to 4 volumes can be handled in every cycle.
The Highest Flexibility
Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

दोहरा अत्याचार पर वार

सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्य पीठ ने 31 अक्टूबर को एक मामले की सुनवाई के दौरान टू फिंगर टेस्ट को लैंगिकतावादी, प्रतिगामी बताते हुए इसे फिर अनुचित बताया और टिप्पणी की कि दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं के लिए यह जांच दोहरा आघात है। उनका अपमान है और उनकी गरिमा के खिलाफ है। दरअसल इस बार भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी नौ साल पुरानी स्थिति यानी राय को ही सरकार, चिकित्सक संस्थाओं, कार्यपालकों व समाज के सामने रखा है। सर्वोच्च न्यायालय इस टू फिंगर टेस्ट को बार-बार अस्वीकार करता है, इस पर रोक लगाता है। लेकिन इसके बावजूद इस अवैज्ञानिक जांच से यौन-हिंसा या बलात्कार की शिकार महिलाओं को अपमानित किया जाता है। इस नजरिए के पीछे पुरुष प्रधान समाज एक मजबूत कारक है।

सवाल यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय इस पर रोक लगा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस पर रोक लगाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। फिर जिनके कंधों पर इसे अमल में लाने की जिम्मेदारी है, वे क्या कर रहे हैं? एक बात यह भी है कि चिकित्सा समुदाय से जुड़े पेशेवर इस जांच की अवैज्ञानिक प्रवृत्ति को लेकर कितने जागरूक हैं। सवाल यह भी है कि समय-समय पर महिलाओं के प्रति जो लैंगिकतावादी, प्रतिगामी टिप्पणियां सुनाई देती हैं, उन पर रोक कैसे लगेगी? बहरहाल सर्वोच्च न्यायालय ने इसी 31 अक्टूबर को चेतावनी दी थी कि ऐसी जांच करने वाले व्यक्तियों या डॉक्टरों को दोषी ठहराया जाएगा। दरअसल न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने 18 साल पुराने एक दुष्कर्म के मामले में निचले न्यायालय की **दोषसिद्धि** वाले फैसले को बहाल रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए गए आरोपी को दोषी करार देते हुए फौरन हिरासत में लेने का आदेश दिया। दोषी को हत्या के मामले में उम्रकैद व दुष्कर्म के मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी। मामले को जानने के लिए 18 साल पीछे लौटना होगा। झारखंड के नारंगी गांव में 7 नवंबर, 2004 को शैलेंद्र कुमार नामक एक युवक ने घर में घुसकर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और फिर उस पर मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। उसका अस्पताल मेडिकल बोर्ड के द्वारा टू फिंगर टेस्ट किया गया। युवती ने पुलिस के समक्ष दिए अपने बयान में आरोपी के बारे में बताया। यह बात दीगर है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने से पहले ही पीड़िता की मौत हो गई।

इस संदर्भ में भी सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि मृत्यु पूर्व पीड़ित का बयान अहम है। इसे केवल इस आधार पर खारिज नहीं कर सकते कि बयान पुलिस ने दर्ज किया। बयान साबित करने वाले तथ्य सत्यता दर्शा रहे हैं, तो पुलिस को दिया अंतिम बयान भी स्वीकार्य और अहम है। देवघर जिला न्यायालय ने इस मामले में आरोपी को दोषी बताते हुए सन् 2006 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। आरोपी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की और उच्च न्यायालय ने टू फिंगर टेस्ट और सुबूतों के अभाव में आरोपी को बरी कर दिया। राज्य पुलिस ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी और सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को दोबारा दोषी करार दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को हत्या के मामले में उम्रकैद और दुष्कर्म के मामले में 10 साल सश्रम कारावास की सजा दी। इस सजा के अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई के दौरान टू फिंगर टेस्ट जारी रहने पर जो चिंता जाहिर की है, वह वाजिब है। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस न्यायालय ने बार-बार दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपों के मामलों में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल को रोका है।

यह टेस्ट अवैज्ञानिक है और पीड़ित महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाता है। यह जांच यौन उत्पीड़न व दुष्कर्म पीड़िता के बारे में यह जानने के लिए किया जाता है कि पीड़ित यौन रूप से सक्रिय है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि एक महिला की गवाही का संभावित मूल्य उसके यौन इतिहास पर निर्भर नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि वह पहले भी कह चुका है कि किसी व्यक्ति के साथ यौन संबंधों का पूर्व इतिहास और चरित्र उसे दुष्कर्म करने की मंजूरी के रूप में नहीं देखा जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह कहना संकुचित सोच को दर्शाता है कि किसी महिला के साथ दुष्कर्म होने की बात पर इसलिए विश्वास नहीं किया जा सकता कि क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय रही है। सन् 2012 में निर्भया सामूहिक दुष्कर्म के बाद गठित सेवानिवृत्त न्यायाधीश जेएस वर्मा समिति ने भी अपनी सिफारिशों में इस जांच को बंद करने के लिए कहा था।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए

गौरतलब है कि इन्हीं सिफारिशों के मद्देनजर सन् 2013 में आपराधिक कानून में संशोधन किया गया था। धारा-53(ए) को साक्ष्य कानून में जोड़ा गया था कि पीड़िता का पूर्व यौन अनुभव यौन अपराध सिद्ध करने के लिए प्रासगिंक नहीं होगा। सन् 2013 में ही सर्वोच्च न्यायालय ने लिलु राजेश बनाम हरियाणा सरकार के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए इस पर रोक लगाने संबंधी आदेश जारी किए थे। सन् 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं की जांच के लिए कुछ अहम दिशा-निर्देश जारी किए थे। इनमें एक यह भी था कि यौन हिंसा या दुष्कर्म को स्थापित करने के लिए टू फिंगर टेस्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान देने वाला बिंदु यह है कि यह महज एक दिशा-निर्देश है, इसका पालन करना कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। सन् 2019 में ही करीब 1,500 दुष्कर्म पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों ने सर्वोच्च न्यायालय में शिकायत की थी कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद यह टेस्ट हो रहा है। याचिका में यह जांच करने वाले डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करने की मांग की गई थी। यह जांच महिलाओं की निजता, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े अधिकारों का उल्लंघन है। बीते एक साल में देश की संवैधानिक पीठों यानी न्यायालयों में इस जांच की आलोचना कर चुकी है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सन् 2013 के बहुचर्चित शक्ति मिल दुष्कर्म के मामले में ऐसी ही राय से अवगत कराया। फिर मद्रास उच्च न्यायालय ने इस साल अप्रैल में यही रुख अपनाया और राज्य सरकार को इस जांच पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए।

संगति अच्छी तो मनोयोग भी अच्छा होगा

श्रीमद्भागवत गीता मनुष्य के जीवन की दशा और दिशा को परिवर्तन करने वाला ग्रंथ है। अर्जुन तो माध्यम मात्र है, यह संदेश संपूर्ण चराचर जगत को दिया गया है कि अक्षर ब्रह्म है, इसका कभी विनाश नहीं होता। तनाव का मुख्य कारण अपेक्षा है, हम अपेक्षा पालते हैं, इससे वैमनस्यता बढ़ती है, भगवान कहते हैं कि विजय यदि प्राप्त करना है तो अपेक्षा नहीं करें, दुर्योधन के पतन का कारण अति अपेक्षा है, हमें अपने अंतरंग में सद्‌गुणों का विकास करना होगा, संगति अच्छी होगी तो मनोयोग भी अच्छा होगा।

भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना।
न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुतः सुखम्।।

अर्थात् योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा।

छोटे बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं उसे वह हमेशा याद रखते हैं। बच्चों का बचपन उनके भविष्य की नींव होती है। ऐसे में बच्चों को कम उम्र में माता-पिता को बच्चों को अच्छी बाते सिखानी चाहिए। जिससे उनकी जिदंगी बेहतर बनें। अगर आप अपने बच्चे को ज्ञान देना चाहती हैं तो श्रीमद् भागवत गीता के अनमोल वचन अपने बच्चों को जरूर सुनाएं या फिर उन्हें पढ़ाएं। भागवत गीता के ये वचन न केवल बड़े लोगों बल्कि आपके बच्चे का सही मार्गदर्शन करेंगी। इस लेख में हम आपको भगवत गीता के उन वचन के बारे में बताएंगे जिसे आपको अपने बच्चों को जरूर बतानी वा पढ़ानी चाहिए।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतु र्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि।।

अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन। कर्म करने में तेरा अधिकार है। उसके फलों के विषय में मत सोच। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो और कर्म न करने के विषय में भी तू आग्रह न कर। अपने बच्चों को गीता ये वचन जरूर बताएं। इंसान को अपना कर्म करना चाहिए फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कई बार किसी काम करने से पहले उसका फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि वह एग्जाम बहुत मुश्किल है उनसे नहीं होगा। ऐसे में उन्हें समझाएं कि वह फल की न सोचे वह केवल अपना कर्म करें। उनका कर्म है पढ़ना और उस एग्जाम को देना। अगर मन में पहले ही आ जाएगा कि नहीं होगा तो फिर एग्जाम के लिए बच्चे उतनी मेहनत नहीं करेंगे।

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः।
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।।

अर्थात् तू शास्त्रों में बताए गए अपने धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा।

अगर आपके बच्चे किसी भी काम को करने के लिए आलस करते हैं तो उनकी इस आदत में सुधार लगाएं। क्योंकि आलस्य किसी भी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जीवन में सफल होने के लिए आलस को छोड़ना बहुत जरूरी है। बच्चे कई बार आराम करने की वजह से स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे में उनकी इस आदत को बदलें। वहीं कुछ बच्चे अपने आलस की वजह से स्कूल होमवर्क नहीं करते हैं। अगर आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उन्हें बताएं कि जीवन में सफलता पाने के लिए आलस छोड़ना होगा।

योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्तवा धनंजय।
सिद्धय-सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।।

अर्थात् हे धनंजय (अर्जुन), कर्म न करने का आग्रह त्यागकर, यश-अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योगयुक्त होकर, कर्म कर, (क्योंकि) समत्व को ही योग कहते हैं। बच्चों को भागवत गीता का ये वचन जरूर बताएं। अक्सर बच्चे पढ़ने या फिर किसी भी काम करने के लिए झट से मना कर देते हैं। ऐसे में उनके बताना चाहिए जीवन में बिना मेहनत कुछ नहीं मिलता है। कभी भी मेहनत से नहीं भागना चाहिए। हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

विहाय कामान् यः कर्वान्पुमांश्चरति निस्पृहः।
निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति।।

अर्थात् जो मनुष्य सभी इच्छाओं व कामनाओं को त्याग कर ममता रहित और अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। लालच करना गलत बात है हमें अपने बच्चों को जरूर बताना चाहिए। गीता में बताया है कि लालच और गुस्सा नरक का द्वार है। जीवन में सुखी रहने के लिए लालच और गुस्से से दूर रहना चाहिए। आप अपने बच्चों को समझाए कि किसी भी चीज को लेकर लालच नहीं करना चाहिए। बच्चों को अपने मन पर कंट्रोल रखना सिखाएं। क्योंकि अगर इंसान का मन कंट्रोल नहीं रहेगा तो जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा वहीं सफलता पाने में भी काफी दिक्कत होगी। बच्चों को मन पर कंट्रोल करना जरूर सिखाएं क्योंकि कोई भी इंसान बचपन में जो भी सीखता है उसे जीवनभर के लिए फॉलो करता है।

● **ओम**

HEIDELBERGCEMENT
149 वर्षों का
अतुलनीय अनुभव
HEIDELBERGCEMENT SINCE 1873 QUALITY ASSURANCE MARK
mycem cement
माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।
क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..
माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए
सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका
For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

दाल-बाटी राष्ट्रीय खाद्य हो?

टीटेम से पहले खाओ बाटी, यही मालवा की है परिपाटी, दाल-बाटी की जोड़ी बड़ी खाटी, लंबा मनख हो या नॉटी, प्रत्येक खाता दालबाटी, फिर गहरी नींद में बजाता खर्राटों की सीटी, यात्री हो या टीटी? दीर्घायु के लिए गांव में कहावत है कि ये सबकी बाटी खाकर ही मरेगो, भय्या? जैसे खिचड़ी के चार यार-दही, पापड़, घी, अचार। वैसे ही दालबाटी के चार मित्र तली मिर्च, चटनी, प्याज, नीबू अनिवार्य घटक है। इनके बिना ऐसे जैसे चेयर बिना नेता, हॉकी बिना स्टिक, संगीतकार बिना तबला? बाटी प्रेमी संघ केंद्र सरकार से चाहते हैं कि रविवार, बाटी दिवस व सालाना एक दिन राष्ट्रीय बाटी दिवस के रूप में घोषित हो? इसे अंतर्राष्ट्रीय आहार घोषित कर इन गोलों की साइज एक सी रखी जानी चाहिए। यह विधेयक संसद में पारित होना चाहिए। भक्षण प्रक्रिया भी एक सी होनी चाहिए कोई इन्हें चूर कर, कोई मसलकर कोई अन सिक्कड़ दाल में डूबा कर, कोई घेंदाघेंद कर चम्मच से भकोसता है। एक रूपता हेतु संसद में समान नीति बिल, इस हेतु पारित किया जाना चाहिए? इसमें घी की मात्रा भी तयशुदा होनी चाहिए? एक घोर बाटी प्रेमी ने बचे आधा किलो घी को बाटी में चूरकर सपड़ लिया, भीषण शीतलहर में घी थीज गया तब चिकित्सा सुविधा से उस बाटी शिरोमणि को बचाया जा सका? बाटी को राष्ट्रीय पकवान घोषित करना चाहिए। इसके कंपोजिशन में मोयन, मीठासोडा, हल्दी, अजवाइन, मीठा तेल मिलाना, राष्ट्रीय नीति हो! बाटी, युवकों के लिए करकरी, प्रौढ़ों को बादामी मुरमुरी, बुजुर्गों के वास्ते नरम लुच्च रखी जाना, संसद में स्वीकृत बिल सा है? इस बाटी बिल को संसद में पारित कर देशभर में लागू किया जाना चाहिए। ताकि सप्ताह में एक दिन बाटी के गोले खाए जा सकें। बाटी विरोधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसे देशद्रोह करार देना चाहिए? इन गोलों को निगलने के बाद न सोना, हरामीपन, अपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखा जाना चाहिए? न सोने वाले सजायाफ्ता हो? कोड़े भी मारे जा सकते है? विस्तृत शोध से ज्ञात हुआ कि ढीले कपड़े पहनकर इसका सेवन करना संतुष्टि कारक, पर्याप्त पानी न पीना कष्टकारक होता है। उस समय मोबाईल फोन मृत रहना उचित है। बाटी खावकों का मत है कि फोन पर बतियाने से पेट मे हवा भराती है और एक गोला कम खवाता है। बाटी घी में डूबी गुलाब जामुन सी होना चाहिए। तर्क है कि जितना घी शरीर में जाएगा उतनी तरावट मगज में समाएगी। नींद भी कुंभकर्ण सी चक झन्नाट, टेंशन फ्री, सन्नाट, जोरदार आएगी। चाहो तो घोड़ा बेचकर सोओ? मालवी कहावत भी है-ढंग पड़े न ढोला, भसक लिया है बाटी का गोला? दक्षिण भारतीय तो इसे बम-बारूद का गोला समझकर खाते ही नहीं है। मुंबई की एक सभ्रांत महिला ने तो इन बाफले, बाटियों को गोबर के उपले पर सेंकते देखा तो बाटी खाना ही छोड़ दिया। तर्क था कि ये गंदे गोबर के कंडों पर सिका है? बाटी, जीन्स पेंट पहनकर नहीं खानी चाहिए। यह वैधानिक अपराध है। ऐसे बैठने में तकलीफ होती है, बाटी कम जिमाती-भाती है। आवाज से बाटीभक्षण में व्यवधान उत्पन्न होता है।

बाटी की महिमा-सोमवार हो या रविवार रोज खाओ बाटी यार। जिस दिन घर पे बाटी बनती है उस दिन घर में खुशी का माहौल रहता है। दिनभर बाटी के दीवाने पगलाते रहते है। बच्चे भी सभी व्यस्त रहते हैं। दाल-बाटी, लड्डू खिलाने से पुण्य मिलता है, अनेकानेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। बाटी खाने के बाद आदमी कर्जाहीन सा महसूसता हैं। दशा, दुर्दशा, महादशा, तीज, त्यौहार, मान सम्मान, गौना, सगाई, मान मनौव्वल, सिर फुटौव्वल, हर कार्यक्रम में आना हो अव्वल तो एक ही व्यंजन ऑल इन वन ओनली दाल-बाटी, जिन्हें खाकर मालवा-निमाड़ में कई-कई प्रेमयुद्ध जीते जाते रहे हैं और स्वाद के ये गोले अब भी बदस्तूर जारी हैं। गैस के गोले भरी महफिल में उड़ाए जाते रहे है? पुराने जमाने में बारूद के गोले दाग कर युद्ध जीते जाते थे। चुनावों में गोले-बोटियों के सामंजस्य से कई देहाती चुनाव, फतह किए जाते रहे हैं? अत: बाटियां राजनीतिक दखलंदाजी रखती है और अनेको बार चुनाव जिताती है। (मौलिक, अप्रसारित, अप्रकाशित, प्रमाणित)

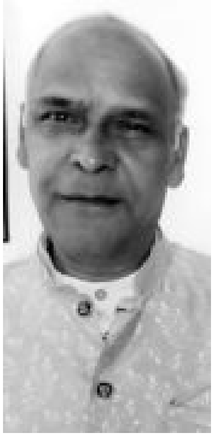

प्रेषक
दिनेश गंगराड़े, 9425936653
निपानिया, इंदौर, मप्र

लघुकथा - योग्य कौन?

अपने बेटे के अनुत्तीर्ण हो जाने की बात को स्वीकारना ललन के लिए बहुत कष्टकर था।

वह देखता था बिरजू कितनी मेहनत करता, दिन और रात बराबर कर दिया था।

आपके बेटे के साथ ही परीक्षा दी थी न मास्टरजी! चाहे किसी श्रेणी से उत्तीर्ण न होता पर पास तो करता।

इतना कमजोर नहीं था मेरा बिरजू!!

उसने बड़े ही विश्वास से कहा था कि परीक्षा में वह प्रथम आएगा। सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। जो उसके लिए बहुत बड़ी मदद होगी।

मगर परिणाम सारे सपनों पर पानी फेर गया...

मास्टरजी! वो तो बार-बार यही कहता है कि सारे प्रश्न के उत्तर लिख आया है और वो भी एकदम सही-सही।

हम्म! सभी बच्चे ऐसा ही कहते हैं। जब नंबर देने की बारी आती है तब पता चलता है कि किसने क्या लिखा।

ये बातें तुम क्या जानो।

मास्टरजी का बेटा प्रथम आया है। पास बैठे सहयोगी शिक्षक ने ललन से कहा... खेलते-कूदते प्रथम आना बहुत बड़ी बात है।

तभी बिरजू मास्टरजी के पास आता है और कहता है ...

सर! मैं अपनी रिजल्ट के खिलाफ चैलेंज करूंगा। ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।

मेरे पिता को भी सारी बात समझ में आ जाएगी।

योग्यता हार कैसे मान सकती है।

सपना चन्द्रा
कहलगांव भागलपुर, बिहार

फाइनल में दोस्त बनेंगे दुश्मन

कतर की मेजबानी में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में न केवल अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच मुकाबला होगा बल्कि दो दोस्तों लियोनेल मेसी और एम्बाप्पे की टक्कर भी देखने को मिलेगी। दरअसल किलियन एम्बाप्पे और मेसी दोनों एक ही क्लब के लिए खेलते हैं। एम्बाप्पे कतर में खेले जा रहे विश्वकप में शानदार फॉर्म में हैं और वह अब तक अपनी टीम के लिए पांच गोल दाग चुके हैं। वहीं मेसी भी एम्बाप्पे से पीछे नहीं हैं। वे भी अब तक खेले मुकाबलों में पांच गोल दाग चुके हैं। पेरिस सेंट-जर्मेन, यह एक ऐसा फुटबॉल क्लब है जिसमें खेलने वाले दुनिया के दो धुरंधर खिलाड़ी एक-दूसरे से टकराने के लिए तैयार हैं। दरअसल इस क्लब के साथ किलियन एम्बाप्पे 2017 से खेल रहे हैं। वहीं मेसी पिछले साल ही इस क्लब से जुड़े हैं। ऐसे में एक ही क्लब से खेलने वाले दो स्टार खिलाड़ी फाइनल में एक-दूसरे के खिलाफ भिड़ेंगे। यानी 18 दिसंबर को होने वाला मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। फीफा विश्व 2022 का पहला सेमीफाइनल मैच अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच खेला गया। इस मैच में अर्जेंटीना ने क्रोएशिया को 3-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। यह छठी बार है जब अर्जेंटीना की टीम फीफा विश्वकप के फाइनल में पहुंची है। कतर में खेले जा रहे इस साल के टूर्नामेंट में अब अर्जेंटीना से उम्मीद होगी कि वह फाइनल में अपने विरोधी को हराकर तीसरी बार चैंपियन बने। हालांकि उसके लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला है।

वहीं टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल फ्रांस और मोरक्को के बीच खेला गया। मोरक्को पहला ऐसा अफ्रीकी देश है जो सेमीफाइनल तक पहुंचा। सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को के सपने चकनाचूर करते हुए लगातार दूसरी बार फाइनल में अपनी जगह बना ली है। फाइनल में अब फ्रांस की टक्कर लियोनल मेसी की अर्जेंटीना के साथ होगी। मोरक्को का टूर्नामेंट में अब तक का प्रदर्शन शानदार रहा था लेकिन फ्रांस के खिलाफ उसकी मजबूत दीवार धराशायी हो गई। मैच में फ्रांस ने 2-0 से जीत हासिल की। मोरक्को की टीम अब तक टूर्नामेंट में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए आ रही थी लेकिन सेमीफाइनल में उसका जादू नहीं चला।

इस जीत के साथ ही फ्रांस की टीम ने फीफा विश्व कप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास में 60 साल बाद कोई डिफेंडिंग चैंपियन लगातार दूसरी बार फाइनल खेलने मैदान पर उतरेगा। इससे पहले 1958 में ब्राजील की टीम विश्व कप जीतने के बाद 1962 के फाइनल में भी खिताब बचाने मैदान पर उतरी थी। वहीं दूसरी तरफ मोरक्को का फीफा विश्व कप खेलने का सपना अधूरा रह गया। मोरक्को अफ्रीकी देशों की पहली टीम बनी है जिसने फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल तक सफर तय किया। हालांकि वह फाइनल में नहीं पहुंच सकी लेकिन मोरक्को ने टूर्नामेंट में अपने सभी विरोधियों को कड़ी टक्कर दी।

मोरक्को के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने उतरी फ्रांस की टीम ने शुरुआत से आक्रामक खेल दिखाया। इसका नतीजा यह हुआ कि खेल के पांचवें मिनट में ही टीम के लिए थियो हर्नांडेज ने गोल दागकर सनसनी मचा दी। इसके बाद भी फ्रांस का खेमा लगातार मोरक्को के गोल पोस्ट पर वार करता रहा। इस तरह पहले हाफ में फ्रांस की टीम 1-0 से आगे रही। खेल के दूसरे हाफ में फ्रांस ने 79वें मिनट में अपनी बढ़त दोगुनी कर ली। फ्रांस के लिए यह गोल रैंडल कोलो मुआनी ने किया। रैंडल सब्सीट्यूट के तौर पर मैदान पर उतरे थे। उन्होंने मैदान पर आने के 44 सेकंड बाद ही गेंद को गोल पोस्ट में डाल दिया। इसके बाद फ्रांस ने मोरक्को को कोई मौका नहीं दिया। फाइनल हूटर बजने तक 2-0 की अपनी बढ़त को बरकरार रखा। पहले हाफ के शुरुआत मिनट में गोल दागने के बावजूद फ्रांस का खेमा मोरक्को को कोई ढील नहीं देना चाहता था। यही कारण है कि पहले हाफ के खेल में फ्रांसीसी टीम ने कुल 10 शॉट्स दागे जिसमें उन्हें एक सफलता हासिल हुई। वहीं बात की जाए मोरक्को की तो उसने कुल पांच मौके बनाए जिसमें से दो टारगेट पर लगे लेकिन वह गोल पोस्ट के अंदर नहीं जा सका। हालांकि दूसरे हाफ में मैदान पर उतरते ही मोरक्को की टीम ने आक्रामकता दिखाई लेकिन फ्रांस के डिफेंस को वह भेद नहीं पाए। इस दौरान फ्रांस ने पलटवार करना जारी रखा और दूसरे हाफ में भी वह एक गोल दागने में सफल रहा।

● आशीष नेमा

फुटबॉल की सबसे महान पीढ़ी का अंतिम पड़ाव

एक समय के बाद हर चीज का अंत होता है। मौजूदा फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे कई महान दिग्गजों के कैरियर की समाप्ति होने वाली है। क्वार्टर फाइनल में पिछले बार की रनरअप क्रोएशिया ने ब्राजील को पेनल्टी शूटआउट में हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। इसके बाद ब्राजील के नेमार ने खेल से संन्यास लेने के संकेत दिए हैं। वे अभी अंतिम फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। टूर्नामेंट में खेल रही अलग-अलग टीमों में कई खिलाड़ियों की उम्र 30+ है। इसमें हेडर किंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, रॉबर्ट लेवानडोस्की सहित कई महान खिलाड़ी हैं। इनकी टीमें टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। अब अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी और डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे की टीम पर सबकी नजर है। वर्ल्ड कप के पिछले दो हफ्तों में कई बार ऐसा महसूस हुआ कि यह वर्ल्ड कप अनिवार्य रूप से मेसी और रोनाल्डो के लिए एक समापन दौरा है। दोनों खिलाड़ियों का एक दशक से अधिक समय तक दबदबा रहा। इन्होंने शानदार प्रदर्शन कर न केवल कई रिकॉर्ड कायम किए, बल्कि अपनी टीम को बड़े-बड़े टूर्नामेंट में खिताब भी दिलाए हैं। इन दोनों के अलावा लेवानडोस्की, सुआरेज, मोड्रिच, लुकाकू, बस्केट्स, मुलर, नेउर, जोर्डी अल्बा, सर्जियो रामोस, बेंजेमा, पॉल पोग्बा, एडेन हैजर्ड और केविन डि ब्रुएन जैसे कुछ दर्जन अन्य नाम भी हैं, जिनके लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। हजार्ड को चेल्सी से जुड़े 10 साल हो चुके हैं। बेंजेमा 2009 में रियल मैड्रिड से जुड़े थे। उन्हें रियल में 13 साल हो गए हैं। इसी तरह अल्वेस के बार्सिलोना में 14 साल हो चुके हैं।

...जब अकेले बैठकर घंटो रोते थे ऋतिक

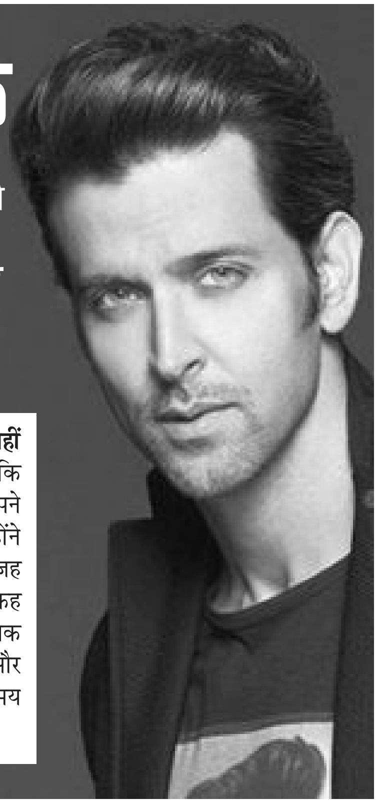

ऋतिक रोशन आज एक नामचीन हस्ती हैं, लेकिन एक समय था जब वे घंटों अकेले बैठकर रोते रहते थे। ऋतिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि एक समय था जब वो फिजिकल और मेंटल कंडीशन से जूझते रहते थे। ऋतिक का कहना है कि बचपन में वो काफी ज्यादा हकलाते थे जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में काफी ज्यादा तंग किया जाता था। ऋतिक का कहना है कि गर्लफ्रेंड तो दूर उनका कोई दोस्त तक नहीं था।

ऋतिक रोशन अपने एक्टिंग और डान्स के लिए जाने जाते हैं। उनकी गिनती दुनिया के सबसे सुंदर लोगों में की जाती है लेकिन एक समय था जब वो फिजिकली काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। इन्हीं सब बातों को याद करते हुए ऋतिक ने एक इंटरव्यू में कहा- बचपन में मैं काफी ज्यादा हकलाता था जिसकी वजह से मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के मुझे चिढ़ाते थे और तंग करते थे। मैं घर आकर सिर्फ रोता रहता था। वो समय मेरे लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड तो दूर कोई अच्छा दोस्त तक नहीं था।

डाक्टर्स ने बोल दिया था कि मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता- ऋतिक ने इसके अलावा ये भी बताया कि वो कैसे इन दिक्कतों को झेल कर आगे बढ़े और अपने आप को एक एक्टर के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा - मेरी रीढ की हड्डी में दिक्कत थी जिसकी वजह से मैं डांस नहीं कर सकता था। डाक्टर्स ने मुझसे कह दिया था मैं कभी एक्टर नहीं बन सकता। मैं महीनों तक डिप्रेशन में रहा लेकिन कुछ समय बाद मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर काम करना शुरू किया और समय के साथ अपने आप को बदल पाया।

नरगिस की शादी होने के बाद खुद को सिगरेट से जलाया करते थे राज कपूर

बॉलीवुड के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर के कई मशहूर किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा है जो शायद कुछ ही लोगों को याद होगा। राज कपूर और नरगिस एक दूसरे से बेइंतेहा मोहब्बत करते थे। दोनों ने तकरीबन 9 साल तक एक-दूसरे को डेट भी किया। इनकी जोड़ी फिल्म बरसात, अंदाज, आवारा, श्री 420 समेत 16 फिल्मों में भी खूब पसंद की गई। नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थीं लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जिसके चलते ये रिश्ता टूट गया। दोनों की प्रेम कहानी में सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि राज कपूर पहले से शादीशुदा थे। उनकी शादी कृष्णा राज से हो चुकी थी। राज कपूर पांच बच्चों के पिता भी थे। वो नरगिस को बेहद पसंद करते थे लेकिन उन्होंने कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा। इसी वजह से नरगिस का दिल टूट गया और वह राज कपूर से हमेशा के लिए दूर चली गईं। बाद में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली और इस खबर को सुनने के बाद राज कपूर बेहद टूट गए। एक इंटरव्यू में राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर ने इस बात का खुलासा किया था कि नरगिस की शादी के बाद शायद ही कोई रात ऐसी बीती होगी जब राज कपूर रोए न होंगे, वह घर पर देर से आते थे, शराब के नशे में चूर वह बाथटब में रोते थे। और कई बार नशे में जलती सिगरेट से खुद को दागा भी करते थे।

पिता नहीं चाहते थे कि फिल्मों में काम करें दिलीप कुमार... इसलिए नाम बदलना पड़ा

दिलीप कुमार आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके नाम का किस्सा आज भी लोगों में मशहूर है। दिलीप साहब के पिता लाला गुलाम सरवर खान और माता आयशा बेगम ने अपने बेटे का नाम यूसुफ खान रखा था। ऐसे में यह जेहन में आता है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार कैसे बने। यूसुफ खान के दिलीप कुमार बनने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। यह किस्सा दिलीप कुमार के डर से जुड़ा हुआ है, जिसे सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे। कहा जाता है कि दिलीप कुमार को पिटाई के डर से नाम बदलना पड़ा था। इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में खुद ही किया था। उन्होंने कहा- मेरे वालिद फिल्मों के सख्त खिलाफ थे। उनके एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जिनका नाम लाला बंसी नाथ था। इनके बटे फिल्मों में एक्टिंग करते थे। मेरे वालिद अक्सर उनसे शिकायत करते थे कि ये तुमने क्या कर रखा है। तुम्हारा नौजवान और इतना सेहतमंद लड़का देखो क्या काम करता है। दिलीप कुमार ने बताया- मैं जब फिल्मों में आया तो मुझे बहुत खौफ हुआ कि जब उन्हें मालूम होगा, तो वह बहुत नाराज होंगे। मेरी पिटाई भी कर सकते हैं। उस समय मेरे सामने तीन नाम रखे गए। युसूफ खान, दिलीप कुमार और बासुदेव। मैंने कहा कि युसुफ खान मत रखिए, बाकी जो आपके दिल में आए वो नाम रख दीजिए।

माफलर लूट लिया पैसे वाला शराबी

माफलर के संबंध में आज की पीढ़ी क्या जानें? माफलर व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता था। यह धारणा थी कि माफलर है तो आधी ठंढ छूमंतर हो जाती है। बचपन से यह मन में बैठ गया था। हमारी पीढ़ी के लोगों के गले में माफलर जरूर होती थी।

रात के दस बजे थे। मैं रात्रि भ्रमण पर था। निश्चित था। कोई डर नहीं था। क्योंकि क्षेत्र तो अपना ही था। ऐसे भी दिल्ली के मुख्य क्षेत्रों में सुरक्षा तो सक्रिय ही रहती है। मुझे यह उम्मीद तक नहीं थी कि मैं एक फ्रेंडली लूट का शिकार हो जाऊंगा। पर घटनाएं तो अचानक ही घटती है। घटनाएं घटने की उम्मीद होती तो सर्तक और सावधान के साथ ही साथ प्रतिकार के कवच भी साथ होते?

अचानक एक शराबी मेरे पास आया। वह बोल पड़ा। अरे मेरे भाई तू कहां था। इतने दिनों के बाद मिला। तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारी कितने सालों से राह देख रहा था, इंतजार कर रहा था। आगे बोला, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम जो बोलोगे, मैं वही करूंगा। तुम्हारे पास कोई चीज की कमी है तो बोलो, अभी दुकान से खरीद देता हूं। इसके अलावा भी उसने कई वाक्य बोले।

मैंने दिमाग पर जोर डाला। याद आया। मेरा पुराना परिचित निकल गया। मैं दिल्ली स्थायी रूप से रहने के लिए आया था, उस समय यानी 1992 का परिचित था। शराबी पहले भी था। वह सोशल वर्कर भी था। पर उसकी रात में पीने के बाद सड़कों पर घूमना और परिचितों को परेशान करना प्रिय करतूत थी।

फिर अचानक मेरे गले में पड़े माफलर की प्रशंसा करने लगा। कहा– तुम्हारा यह माफलर बहुत अच्छा है, तुम्हारे गले में नहीं मेरे गले में यह माफलर अच्छा लगेगा। मेरे गले से माफलर लेकर अपने गले में लगा लिया। मैं सोचा कि यह सिर्फ मजाक कर रहा है। वह बोला कि तुम्हे मैं दूसरा माफलर दिला देता हूं। फिर वह माफलर लेकर चला गया। मैं माफलर ले जाते हुए सिर्फ देखता रह गया।

उस शराबी को क्या मालूम? मेरा यह माफलर कितना कीमती और पसंदीदा था। उसे यह भी मालूम नहीं कि मैंने उस माफलर को कहां से मंगवाया था और मंगवाने में मुझे कितनी परेशानी हुई थी। इस माफलर का मूल्य पांच हजार रुपए था। मैंने इसे कश्मीर से मंगवाया था। कश्मीर से मंगवाने में मुझे बहुत परेशानी हुई थी और प्रयास भी खूब करने पड़े थे। अगर इतना बड़ा मूल्य नहीं चुकाता और प्रयास नहीं करता तो फिर वह माफलर मेरे गले में नहीं पहुंचता।

लुटेरा शराबी कंगाल कतई नहीं है। अच्छी संपत्ति वाला है। वह एक चार मंजिला बिल्डिंग का मालिक है। उसके बच्चे अच्छी जगह पर गतिशील हैं।

माफलर के संबंध में आज की पीढ़ी क्या जानें? माफलर व्यक्ति के लिए कितना महत्वपूर्ण होता था। यह धारणा थी कि माफलर है तो आधी ठंढ छूमंतर हो जाती है। बचपन से यह मन में बैठ गया था। हमारी पीढ़ी के लोगों के गले में माफलर जरूर होती थी।

1980 के दशक तक लाल ईमली के माफलर की अपनी धाक होती थी। लाल ईमली के माफलर गले में लगाना और लाल ईमली का चादर, शॉल ओढ़ना शान का विषय होता था और उसकी गिनती विशेष मनुष्य के तौर पर होती थी।

माफलर के साथ ही साथ सिक्को फाइव घड़ी और बजाज स्कूटर स्टेटस सिंबल हुआ करती थी। लाल ईमली का माफलर तो शुलभ हो जाता था। पर सिक्को फाइव घड़ी और बजाज स्कूटर पैसा होने के बाद भी सपना ही होती थी। सिक्को फाइव घड़ी सोवियत संघ मेड थी और ऑटोमैटिक भी थी, चाभी भरनी नहीं होती थी। शेष घड़ियों में चाभी भरनी होती थी। लाखों लोगों के अनुपात में एक मनुष्य के पास यह घड़ी होती थी। यानी कि लाखों में एक मनुष्य सिक्को घड़ी पहनने वाला होता था। बजाज स्कूटर के लिए वर्षों लाइन में लगनी पड़ती थी। बजाज स्कूटर की ब्लैक मार्केटिंग खूब होती थी।

मैं अपने आप को विशेष मनुष्य तो नहीं कह सकता हूं पर मैं सौभाग्यशाली जरूर था कि मेरे पास लाल ईमली का माफलर भी होता था, सिक्को फाइव घड़ी भी होती थी और बजाज स्कूटर भी होती थी। सिक्को फाइव घड़ी भी मैंने नई खरीदी थी और बजाज स्कूटर भी नई खरीदी थी। उस काल में बजाज स्कूटर का होना ऑडी कार होने का अहसास होता था, स्वाभिमान भी होता था। वह बजाज स्कूटर गांव स्थित मेरे घर में आज भी निशानी के तौर पर रखा हुआ है।

आज मेरा गला माफलर रहित है। उस माफलर की ताजगी और गुरूर को भूल नहीं पा रहा हूं। उस शराबी से मैं वह माफलर मांग भी नहीं सकता। वैसा नया माफलर इस सर्दी तक मुझे शायद ही मिल पाएगा? वैसा माफलर खरीदने में मुझे पांच हजार से ज्यादा पैसे चुकाने होंगे और कश्मीर से मंगवाना पड़ सकता है।

परिस्थितियों और घटनाओं पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। उस माफलर की नियति उस शराबी के गले में पड़कर शराब की बदबू सूंघते रहने की होगी। जैसे चंदन की नियति विशैले सर्प के बीच रहने की होती है।

● आचार्य श्री विष्णुगुप्त

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)

A Subsidiary of Coal India Limited

Singrauli (M.P.) India - 486889

www.nclcil.in

/northerncoalfields @NCL_SINGRAULI YouTube /northerncoalfields